# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 17 जून–23 जून 2013 | मूल्य 5 रुपये



**मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं**

पेज : 4

**रोटी से खेलने वाला कौन है देश की संसद मौन है...**

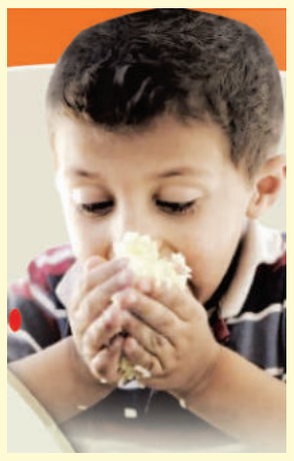

पेज : 6

**डॉ. अंबेडकर की चेतावनी सच साबित हो रही है**

पेज : 7

**साई की महिमा**

पेज : 12


# कांग्रेस में ज़्यादा भ्रष्ट है भाजपा

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

**देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा की मौजूदा हालत किसी से छिपी नहीं है. संगठन के अंदरखाने चल रही उठापटक जितनी उच्चस्तरीय है, उतनी ही दोयम दर्जे की है. भाजपा को लेकर संघ में निराशा चरम पर है, क्योंकि सिद्धांतों और मर्यादाओं को तिलांजलि देने के मामले में भाजपा अब कांग्रेस से चार क़दम आगे निकल गई है. संघ की चिंता और पार्टी की दयनीय हालत पर रोशनी डाल रही है इस बार की आमुख कथा.**

संतोष भारतीय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखा जाए, तो वह बहुत अच्छा शायद न हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के असरदार लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. संघ के लोग अपनी अनदेखी से दु:खी हैं और अपने सिद्धांतों की हत्या करने वाले नेताओं से नाराज़ भी हैं. वे दरअसल, अब उस मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां बूढ़ा शेर शिकार को सामने से जाते हुए देखकर भी उस पर हमला नहीं कर पाता. उसकी बेबसी ज़रूर होती है, लेकिन वह इसका एक रास्ता निकालता है और वह रास्ता यह है कि वह बच्चे से जवान होते हुए शेरों को नए सिरे से शिकार के लिए ट्रेनिंग देता है. भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन बूढ़े, निराश और गुस्से से भरे हुए कुछ शेरों से जब हमारी बातचीत हुई, तब हमें लगा कि इनका दर्द भी लोगों के सामने आना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की यह कहानी इन बूढ़े, असहाय, निराश, लेकिन नाराज़ संघ के लोगों की व्यथा कथा है. यह व्यथा तब और बढ़ जाती है, जब ये लोग गोवा में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक दूसरे को गिराने की रणनीति खुलेआम बनाते और उस पर अमल करते दिखते हैं.

भारतीय जनता पार्टी आज अंदरूनी तौर पर कई हिस्सों में बंटी हुई है. हर आदमी दूसरे को पटकने में लगा है. स्थिति ऐसी हो गई है कि दूसरे भले ही डूब जाएं, मैं बच जाऊं. श्री लालकृष्ण आडवाणी ज़िंदगी में मिले इस आख़िरी मौक़े को गंवाना नहीं चाहते. नरेंद्र मोदी और उनके साथी मान रहे हैं कि ऐसा मौक़ा उन्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा. सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह सबके सिर पर सवार होना चाहते हैं. वहीं राजनाथ सिंह मोदी का इस्तेमाल कर सीटें तो लाना चाहते हैं, पर ऐसी स्थितियां भी पैदा कर रहे हैं, जिनसे मोदी के सर्वसम्मत प्रधानमंत्री बनने में संदेह पैदा हो जाए. नरेंद्र मोदी का सहारा लेकर सीटें लाना और फिर ख़ुद प्रधानमंत्री बनना राजनाथ सिंह की रणनीति का सूत्र वाक्य है. ऐसा ही उन्होंने 2004 में आडवाणी जी के समय भी किया था और सभी से कहा था कि मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, इसलिए मेरे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है. संयोग है कि 2014 के आम चुनावों से पहले राजनाथ सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं.

नरेंद्र मोदी अपने साथ संसदीय बोर्ड में अमित शाह को ले आए. हालांकि उनका क़द भारतीय राजनीति में कभी ऊंचा था ही नहीं. उनकी साख गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़े खलनायक की रही है और उन्हें गुजरात में छोटा प्रमोद महाजन माना जाता रहा है. अब उन्हें नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनवा दिया है. नरेंद्र मोदी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी ज़्यादा सीटें उनके अपने उम्मीदवारों को मिलेंगी, उनके प्रधानमंत्री बनने में उतनी ही सहूलियत होगी. नरेंद्र मोदी के इस हित की देखभाल अमित शाह को उत्तर प्रदेश में करनी है, पर मोदी की इस चाल का जवाब बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के असरदार लोगों ने राम जेठमलानी को पार्टी से निकाल कर दे दिया. राम जेठमलानी मोदी के आदमी हैं और उन्हें गुरुमूर्ति इस तर्क के साथ संसद में लेकर आए थे कि जेठमलानी मोदी के लिए सारे देश में अच्छी ज़मीन तैयार करेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि गुजरात दंगों में किसी भी चूक की वजह से मोदी जेल न जाएं, क्योंकि यही संघ परिवार के हित में है, इसीलिए राम जेठमलानी को पार्टी और संसद में लाना चाहिए. हमें भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों की मूर्खता के बारे में बताया गया और कहा गया कि राम जेठमलानी वकील हैं और वह पैसा लेकर मुक़दमा लड़ते हैं, इसलिए उन्हें पैसा देकर नरेंद्र मोदी का मुक़दमा लड़वाया जा सकता था. इसके लिए उन्हें पार्टी में लेने की क्या ज़रूरत थी. एक दूसरा उदाहरण हमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी में संघ से आए प्रतिनिधि मदनदास देवी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में यह तर्क दिया कि महेश चंद्र शर्मा के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए और उन्हें रहने के लिए घर न होने के कारण टिकट भी मिल गया. इसी तरह गुरुमूर्ति ने तर्क दिया और वह तर्क भी मान लिया गया. राम जेठमलानी अधिवक्ता हैं. उन्होंने वही किया, जो उन्हें करना चाहिए था. उन्होंने तर्क दिए, अब चाहे वे तर्क किसी निशाने पर लगें. हमें एक अच्छा उदाहरण दिया गया कि कोयला अगर हथेली पर रखें, तो यदि वह गरम होगा, तो हाथ जलाएगा और ठंडा होगा, तो हाथ काला करेगा.

पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस बैठक में सभी लोग थे, जिसमें राम जेठमलानी को निकालने का फ़ैसला लिया गया. अनंत कुमार ने प्रस्ताव रखा और सबने इस प्रस्ताव को माना. इस प्रस्ताव के पीछे आडवाणी जी थे, जिन्होंने मोदी को स्पष्ट संदेश दिया. आडवाणी जी ने अनंत कुमार के ज़रिए जेठमलानी को निकलवा कर मोदी को बता दिया कि भले ही वह पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ गए हों, लेकिन उनके पर बहुत सुरक्षित नहीं हैं.

भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की राजनीति बताती है कि नरेंद्र मोदी कहीं पहुंच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि न तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और न ही 89–90 जैसा माहौल अब देश में है. मज़े की बात यही है कि न नेतृत्व है और न माहौल है. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि वह 200 सीटें पा जाएगी. हालांकि जब माहौल था, नेता था, उस समय भी 190 सीटें नहीं आ पाई थीं. इन दावों का खोखलापन भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, पर इसके बाद भी रणनीति यह चल रही है कि अगर सीटें आ गईं, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं अपनी दावेदारी अभी से क्यों न ठोक दूं. राजनाथ सिंह जब सीटें आएंगी, तब दावा ठोकेंगे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने सीटें आने से पहले ही दावा ठोकना शुरू कर दिया है.

भारतीय जनता पार्टी में कई गुट बन गए हैं. पहला गुट आडवाणी जी का है, जिसके अब तक नरेंद्र मोदी भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब इसके दो हिस्से हो गए हैं. एक का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दूसरे का लालकृष्ण आडवाणी. नरेंद्र मोदी को इस समय राजनाथ सिंह ताक़त दे रहे हैं. सत्यता तो यह है कि राजनाथ सिंह बैलेंस साधने का खेल खेल रहे हैं.


**(शेष पृष्ठ 2 पर)**

मंत्री का तर्क था कि इस तरह का कोई संस्थान सिर्फ़ सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए केंद्र के स्तर पर ही स्थापित किया जा सकता है.



# दिल्ली का बाबू

## नेता नाखुश

महाराष्ट्र के नेताओं का यह कहना है कि राज्य में नौकरशाही सरकार से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को हाल में उस समय शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, जब उनके ही कैबिनेट के एक सहयोगी ने वरिष्ठ नौकरशाह के पी बख्शी एवं संजय चाचांडे द्वारा पेश राज्य में पुलिस अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव खारिज कर दिया. उक्त मंत्री का तर्क था कि इस तरह का कोई संस्थान सिर्फ़ सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए केंद्र के स्तर पर ही स्थापित किया जा सकता है. सूत्रों का कहना है कि जब मंत्रियों के पास नौकरशाहों को लेकर विभिन्न तरह की शिकायतें आती हैं, तो उनका यह कहना दु:खद है कि नौकरशाहों ने कैबिनेट में बिना नोटिस दिए उन्हें वेतन पर मासिक भत्ते में बढ़ोत्तरी दे दी. सचमुच यह बहुत दु:ख की बात है! ■

## भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लंबित मुकदमे

अधिकांश जांच एजेंसियों की शिकायत है कि रिश्वतखोर नौकरशाहों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा अनुमति मिलने में देरी हो रही है. सरकार की इस उदासीनता के कारण लोगों में यह संदेश जा रहा है कि इन लोगों को छुटकारा मिल गया है. सूत्रों के अनुसार, यूपीए ने पिछले साल चार्जशीट फाइल होने के तीन महीने के अंदर इन बाबुओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में अब तक थोड़ा ही काम हो सका है. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अनुसार, ऐसे कम से कम 27 मामले सरकारी अनुमति का इंतज़ार कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि अजमेर के पुलिस प्रमुख राजेश मीणा का मामला ऐसा है, जिस पर सीवीसी ने खुद आगे बढ़कर मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई की है. राजेश मीणा जिले में चल रही अवैध वसूली के मामले में अभियुक्त हैं और वह बीते जनवरी माह में गिरफ्तार हुए थे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मामलों को सतर्कता आयोग का पैनल हाल में सामने लाया. इनमें 3500 से अधिक मामले थे, जिनमें से 83 मामले संबंधित विभाग के मंत्रियों के पास जांच के लिए भेज दिए गए हैं. अब इनमें से कितने मामलों पर कार्रवाई होगी, इस बारे में सिर्फ़ अनुमान ही लगाया जा सकता है. ■

दिलीप चेरियन

## क़ीमत चुकानी पड़ी

राजनीतिक पार्टियों को अगर कहीं तनिक भी फ़ायदा दिखता है, तो वे तुरंत आक्रामक हो जाती हैं. केरल की वेटरीनरी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. बी अशोक इस बात को भूल गए और उन्हें इसकी क़ीमत चुकानी पड़ी. डॉ. अशोक ने अख़बार में एक लेख लिखा, जिसे कांग्रेस के दिग्गजों ने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के विरुद्ध माना. इसके बाद डॉ. अशोक को बर्खास्त कर दिया गया और उन पर जल्द ही कार्रवाई किए जाने की संभावना है. विश्लेषणकर्ताओं का कहना है कि अशोक की बर्खास्तगी राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर हुई है, जो सिविल सर्विस के नियमों के हिसाब से ठीक नहीं है. वहीं भाजपा के कूदने और डॉ. अशोक के बचाव में आने से धीरे–धीरे यह मामला राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है.■

dilipcherian@gmail..com

# साउथ ब्लॉक

## जितेंद्र शंकर, सुशील और राजीव अतिरिक्त सचिव बने

1982 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी जितेंद्र शंकर माथुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (कल्याण) में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वह इसी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं. इसी प्रकार 1982 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी सुशील कुमार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह 1979 बैच एवं राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी मीरा मेहरिशी का स्थान लेंगे. वर्तमान में वह आवास एवं शहरी ग़रीबी निवारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. इसी तरह 1981 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह 1979 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सुधीर भार्गव का स्थान लेंगे, जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है.

## अनिल और सुनीता संयुक्त सचिव बने

1986 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार काची को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह 1982 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश की जगह लेंगे. अनिल वर्तमान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. इसी प्रकार सुनीता एच खुराना को राष्ट्रीय महिला आयोग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. यह विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट है भाजपा

पृष्ठ एक का शेष

एक तरफ़ उन्होंने नरेंद्र मोदी के अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजा और दूसरी तरफ़ उन्होंने उमा भारती को उत्तर प्रदेश में दबाया और साथ ही वरुण गांधी को महत्वपूर्ण रोल दिया. उमा भारती ने फौरन बयान दिया कि आडवाणी जी ही प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं. भाजपा के नेतृत्व में कहा जाने वाला हर व्यक्ति बिना दूसरे की चिंता किए खुद को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है और ऐसी स्थिति में संगठन मार खा रहा है, यही संघ की सबसे बड़ी चिंता है.

राजनाथ सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. उन्हें पता था कि नरेंद्र मोदी को अमित शाह नामक मोहरे का उत्तर उमा भारती से कैसे दिलाया जा सकता है. उन्होंने उमा भारती को जानबूझ कर इतना दबाया कि वह आडवाणी जी की गोद में जाकर बैठ गईं और उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए आडवाणी जी का नाम ले लिया. उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में नहीं हैं. वह इस समय गंगा यात्रा कर रही हैं. दरअसल, भाजपा में हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा है. चेहरा कुछ है, सत्य कुछ है. शिवराज सिंह चौहान ज़ाहिरा तौर पर कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन वह मध्य प्रदेश में इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना चाहते हैं, ताकि वहां के लोग उनका भी नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ले सकें. यही हाल वसुंधरा राजे का है. हर आदमी अपना घर पक्का करने में लगा हुआ है. उसकी सोच केंद्र में आने वाली भाजपा की सरकार के लिए कम और अपनी सत्ता कैसे बने, इसके लिए ज़्यादा है.

भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू भी बन गई है. किस्सा राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर है. लालकृष्ण आडवाणी और नवीन पटनायक बैठे बात कर रहे थे. नवीन पटनायक ने कहा कि हर बार हम आपके उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, इसलिए इस बार आप हमारे उम्मीदवार का समर्थन कर दीजिए. उन्होंने इसके लिए संगमा का नाम सामने किया और आडवाणी जी ने उसका समर्थन किया. इसके बाद नवीन पटनायक ने आडवाणी से यह भी कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ने के लिए उन्हें उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तीसरे मोर्चे की ही बनेगी. भारतीय जनता पार्टी अब नेतृत्व करने की जगह समर्थक की भूमिका में आ गई है.

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में चले गए हैं. संघ का मानना है कि इन कार्यकर्ताओं को अब इस बात का विश्वास नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व कांग्रेस को हटाने में कोई गंभीर भूमिका निभा पाएगा. कार्यकर्ताओं को इस बात का दु:ख है कि जिन्हें भी भाजपा में पहले सिर पर बैठाया गया, उन्हें बाद में जूते से रौंदा भी गया. ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, जिसमें मदन लाल खुराना, उमा भारती, वसुंधरा राजे, शांता कुमार, भगत सिंह कोश्यारी, बी सी खंडूरी और ख़ुद राजनाथ सिंह का नाम है. इनमें सिर्फ़ राजनाथ सिंह ऐसे सौभाग्यशाली हैं, जो मुख्य धारा में फिर वापस आ गए.

आडवाणी जी ने भाजपा में यह कहकर कि नितिन गडकरी लोकसभा का चुनाव निर्देशित करेंगे, एक नए सत्ता केंद्र का निर्माण कर दिया. दरअसल, ये छोटी–छोटी घटनाएं ज़रूर हैं, लेकिन ये घटनाएं नरेंद्र मोदी को संदेश देती हैं कि वह अपनी हद में रहें. संघ का दूसरा सबसे बड़ा दु:ख यह है कि उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन बावजूद इसके, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही है. इसकी जड़ में अपना ही अपनों को मारता है, का मनोविज्ञान दिखाई दे रहा है. नरेंद्र मोदी को भी अपने ही मारेंगे, ऐसा उनका मानना है. आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़रा भी उत्साह नहीं है. शायद इसके पीछे कारण उन लोगों का नेतृत्व है, जिनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता नहीं रहा. इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा कार्यकारिणी है. इसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनका भाजपा से कभी लेना–देना ही नहीं रहा. संघ के यह नेता कहते हैं कि अरुण शौरी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज और यशवंत सिन्हा का भाजपा से क्या लेना–देना? कहा जाता है कि संघ भाजपा को नियंत्रित करता है, पर अब भाजपा में न तो संघ की विचारधारा है और न ही संघ के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व. यह भी उदाहरण दिया जा रहा है कि गोविंदाचार्य और संजय जोशी जैसे लोगों को तो भाजपा से निकाल दिया जाता है, लेकिन रामलाल जैसे लोगों को रखा जाता है, जिनके ज़माने में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से तीन करोड़ रुपये गायब हो गए और उनका आज तक पता नहीं चला. न तो आज तक इसकी ज़िम्मेदारी तय हो पाई और न ही किसी ने इस पर कोई सवाल उठाया. संघ के इस निराश नेता का कहना है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे रहे हैं.

कांग्रेस के भीतर शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, भले ही उस शक्ति का इस्तेमाल सिंडिकेट करता है, लेकिन यह सिंडिकेट कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के नाम पर काम करता है. सोनिया गांधी स्वयं ताक़तवर नहीं हैं, लेकिन उन्हें सिंडिकेट ने ताक़तवर बना रखा है. यह सिंडिकेट इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर फ़ैसला सोनिया गांधी के नाम से देश में जाए और जाना जाए. इसका परिणाम यह होता है कि तंत्र और अधिकार जनता के सामने स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता. इसका दूसरा पहलू यह है कि जो भी राजनीतिक सौदेबाज़ी होती है, वह पहले निचले स्तर पर हो जाती है और नेता उस पर मुहर लगा देता है. यह एक प्रकार का सत्ता केंद्र है. दूसरे प्रकार का सत्ता केंद्र कम्युनिस्ट पार्टियों का है, जिसमें सब मिलकर फ़ैसला लेते हैं.

भाजपा पहले कम्युनिस्टों की तरह दिखाई देती थी, जिसमें सभी मिलकर फ़ैसला लेते हैं. इसमें संघ और भाजपा के लोग मिलकर बैठते थे और एक फ़ैसला ले लेते थे, लेकिन आज की तारीख़ में भाजपा में फ़ैसले कौन लेता है और कौन उन फ़ैसलों को पलट देता है, इसका पता किसी को नहीं चलता. एक महीने पहले तक लगता था कि मोदी एक बड़ी ताक़त के रूप में उभर रहे हैं, पर अब भाजपा के शातिर लोगों ने मोदी को भी छीलना शुरू कर दिया है. संघ के लोगों का मानना है कि चूंकि इंडिविजुअल पॉवर सेंटर नहीं है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं है. ग्रुप बैठता नहीं है, इसलिए फ़ैसले भी दाएं–बाएं होते हैं. कांग्रेस और भाजपा में पहले एक समानता थी कि जहां कांग्रेस में एक व्यक्ति

फोटो–प्रभात पाण्डेय

फ़ैसला लेता था, वहीं भाजपा में ग्रुप बैठकर फ़ैसले लेता था. अब एक समानता और हो गई है, जैसे कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में फंस जाए, तो सभी उसका समर्थन कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही अब भाजपा में भी हो रहा है. भाजपा में भी कांग्रेस की तरह पैसे खाए जा रहे हैं. इसका उदाहरण संघ के लोग देते हैं. उनका कहना है कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बांध नहीं बनने चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा शोर भाजपा ने मचाया, लेकिन सबसे ज़्यादा बांध भाजपा की सरकार के समय बने. संघ परिवार और सेना ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया कि श्रीलंका पर बने पुल के निशान को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि नक्शा और नासा, दोनों कहते हैं कि यहीं पर रामसेतु था और इसे नहीं टूटना चाहिए, लेकिन उसे तुड़वाने का काम भाजपा की सरकार ने शुरू किया, क्योंकि उसके पीछे आर्थिक स्वार्थ था.

भाजपा ने ऐसे कई काम किए, जिन्हें कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी. जैसे, कांग्रेस सपने में भी हिंदुस्तान जिंक को पांच सौ करोड़ रुपये में नहीं बेच सकती थी, लेकिन भाजपा ने उसे बेच दिया. हिंदुस्तान जिंक का जो तीस प्रतिशत हिस्सा बचा हुआ है, उसे प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अग्रवाल 20 हज़ार करोड़ में लेने को तैयार हैं. आख़िर पिछले बारह सालों में ऐसा क्या हुआ कि 70 प्रतिशत हिस्से की क़ीमत 452 करोड़ और 30 प्रतिशत हिस्से की क़ीमत 20 हज़ार करोड़ रुपये? मारुति बिकेगी, यह कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था. सिकंदर बख्त भाजपा के मंत्री थे, उन्होंने एक हज़ार करोड़ रुपये में मारुति बेच दी. जो फ़ैसला कांग्रेस नहीं कर सकती, वह फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है.

हम एक नया रहस्योद्घाटन कर रहे हैं. जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य एवं उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा मिलकर पाकिस्तान और अमेरिका से बातचीत कर रहे थे. बातचीत जम्मू–कश्मीर के कुछ हिस्सों को लेकर थी कि उन्हें पाकिस्तान को दे दिया जाए और उसके साथ एक स्थायी सीमा समझौता कर लिया जाए. संघ के लोगों का मानना है कि देश के साथ यह सबसे ख़तरनाक समझौता होने वाला था, जो नहीं हो पाया. उस समय गोविंदाचार्य ने यह शोर मचाया और भारतीय जनता पार्टी से कहा कि अगर देश का एक भी हिस्सा उसने पाकिस्तान को दिया, तो वह ज़िंदगी में कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ सकेगी. उस समय गोविंदाचार्य द्वारा विरोध करने पर अमेरिकन राजदूत बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बाहर निकल कर कहा कि गोविंदाचार्य वाजपेयी को मुखौटा कह रहे हैं. दरअसल, गोविंदाचार्य को पार्टी से बाहर अमेरिका के कहने पर किया गया. नतीजा यह निकलता है कि भाजपा वह कर सकती है, जो कांग्रेस भी नहीं कर सकती और शायद इसीलिए, भ्रष्टाचार में भाजपा कई जगहों पर कांग्रेस से बहुत आगे है. कर्नाटक में येदियुरप्पा और राजस्थान में वसुंधरा राजे के शासनकाल की कहानियां इसकी पुष्टि करती हैं. पैसे खाने, काम न करने और अपने आदमियों के काम न करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे है.

संघ के लोगों का कहना है कि जब कोई कार्यकर्ता भाजपा के मंत्रियों के पास जाता था, या जाता है, तो चूंकि वे उससे पैसा नहीं मांग सकते, इसलिए उसका काम नहीं करते हैं और वहीं इसी काम को पैसे देने पर आसानी से होते देखा गया. भाजपा के राज में जितने बैंकों में डायरेक्टर बने, उनमें से आधे कांग्रेस के लोग थे, जो कभी कांग्रेस के शासन में भी डायरेक्टर नहीं बन पाए. उन दिनों कहा जाता था कि बैंकों के डायरेक्टर बनने वाले लोगों ने एक लाख या दो लाख रुपये दिए हैं. कांग्रेस इस मामले में ए टीम नहीं, बल्कि भाजपा कांग्रेस की ए टीम है. भाजपा में अब कभी भी किसी को निकाला जा सकता है. कांग्रेस में निकाले गए व्यक्ति को कभी वापस नहीं लिया जाता, लेकिन भाजपा में निकाला गया व्यक्ति कभी भी वापस आ सकता है. राम जेठमलानी चार बार पार्टी से बाहर गए और वापस आए. उत्तर प्रदेश में उमा भारती एवं कल्याण सिंह का वापस आना उतनी बड़ी घटना नहीं है, जितना पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती सरकार के एक मंत्री बाबुलाल कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है. भाजपा में सभी जानते हैं कि दिल्ली में मोटा पैसा लेकर इस व्यक्ति को पार्टी में लिया गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई. यही नहीं, डी पी यादव भी मोटा पैसा देकर भारतीय जनता पार्टी में घुसना चाह रहे थे. संघ के यह शुभचिंतक बताते हैं कि डी पी यादव को पार्टी में न लेने का फ़ैसला लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जीत की बुनियाद रख दी. वहीं मायावती के भ्रष्टाचारी मंत्री को पार्टी में लेकर भाजपा ने अपने हाथों अपनी हार का भविष्य लिख लिया. भारतीय जनता पार्टी में एक कमाल की बात यह है कि जिस नेतृत्व के तहत पार्टी की सीटें घटती हैं, उसे कभी बदला ही नहीं जाता.

क्या भारतीय जनता पार्टी स्पैंट फोर्स हो गई है या फिर चुकी हुई ताक़त? सत्यता यह है कि संघ भारतीय जनता पार्टी की निर्णय प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर है. संघ का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कटी पतंग की तरह आकाश में उड़ रही है और यह धीरे–धीरे दस–पंद्रह सीटों पर सिमट जाएगी. जब भाजपा के नेता हताश हो जाएंगे और संघम शरणं गच्छामि हो जाएंगे, तब संघ के कार्यकर्ता दोबारा भाजपा को खड़ा करने में लगेंगे. संघ का कहना है कि आज जैसी महंगाई है, जितनी अनियमितताएं हैं, जितने घोटाले बाहर आ रहे हैं, इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार नहीं गिर पा रही है, तो यह भारतीय जनता पार्टी का दोष है और यह स्थिति तब, जबकि सरकार के पास बहुमत नहीं है. देश का गृहमंत्री अमेरिका में अपनी आंख दिखाने जाए, तो इसका मतलब यह है कि 120 करोड़ लोगों की आंखें देखने वाले डॉक्टर नाकारा हैं. अगर इसे भी भाजपा अपना मुद्दा नहीं बना सकती, तो वह कुछ भी नहीं कर सकती. अगर सुशील कुमार शिंदे की आंखें इतनी ख़राब हैं, तो वह देश के गृहमंत्री कैसे हैं? उनकी बर्ख़ास्तगी की मांग भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उठाई? देश जल रहा था और वह अमेरिका में अपनी आंखें दिखा रहे थे! संघ को इस बात का दु:ख है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई. संघ को इस बात का भी दु:ख है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी विपक्ष की मर्यादा भंग कर दी. दरअसल, भाजपा में कोई धार नहीं है और न ही वे लोग बचे हैं, जो उसे धार दे सकें. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 15
दिल्ली, 17 जून–23 जून 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ओल्ड कैडर बेस्ड जमाअत इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर मोहम्मद सलीम का स्पष्ट रूप से कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और पारदर्शिता के पक्ष में अन्ना हज़ारे ने जो आंदोलन शुरू कर रखा है, जमाअत उसका समर्थन करती है.

# अन्ना और मुसलमान

**अन्ना हज़ारे ने पिछले दिनों अपनी जनतंत्र यात्रा के तहत कई राज्यों का दौरा किया. वह जहां-जहां गए, उन्हें अपार जनसमर्थन मिला. देश के मुस्लिम समुदाय में भी उनकी इस यात्रा को लेकर न केवल खासी दिलचस्पी दिखी, बल्कि उसका समर्थन भी अन्ना के पक्ष में जाहिर हुआ.**

अब्दुल हमीद नोमानी

जमीअत के अंदर भ्रष्टाचार से संबंधित आधिकारिक रूप से कोई नीति नहीं बनी है और न ही कोई करारदाद पारित किया गया है और कभी-कभार ही इस पर बातचीत हुई है.

डॉ. मंज़ूर आलम

लोकायुक्त से संबंधित गुजरात का बदतर उदाहरण हमारे सामने है, जिसके विरुद्ध कोई मुहिम नहीं छिड़ी. लिहाज़ा अन्ना की यह मुहिम राज्य सरकारों के विरुद्ध भी चलनी चाहिए.

डॉ. ज़फ़रुल इस्लाम ख़ां

27 अगस्त, 2011 को सरकार ने अन्ना हज़ारे को केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के हाथों भेजे गए पत्र में जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में वह बुरी तरह असफल रही है. जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया.

मोहम्मद सलीम

भ्रष्टाचार के विरुद्ध और पारदर्शिता के पक्ष में अन्ना हज़ारे ने जो आंदोलन शुरू कर रखा है, जमाअत उसका समर्थन करती है. अन्ना के तीन बिंदुओं से संबंधित भारत सरकार ने जो वादे पौने दो साल पहले किए थे, उन्हें उसे पूरा करना चाहिए.

कमाल फ़ारूक़ी

अन्ना हज़ारे द्वारा उठाए गए मुद्दे के हक़ में हैं और इस सिलसिले में कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने जो धोखा किया है, उस मसले को हल करने की बजाय उसे टालना और उलझा देना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है.

सैयद इमदादुल्लाह

अन्ना हज़ारे ने जब दो साल पहले अपना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया, तो उन्हें ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ था और उसका मूल कारण यह था कि अन्ना जो कुछ कर रहे थे, उसमें आम जनता की सहमति थी.

## प्रधानमंत्री ने मुझे धोखा दिया

**प्रति,**
**मा. श्रीमान मनमोहन सिंह जी,**
**प्रधानमंत्री, भारत सरकार.**

मैंने आपको एक पत्र 12 फरवरी, 2013 को लिखा था. उस पत्र के जवाब में आपके कार्यालय से श्री वी नारायण सामी जी के नाम से पत्र डी.ओ.नंबर 407/67/2012-एवीडी/4बी, ता. 9 मई, 2013 को भेजा गया, जो मुझे 20 मई, 2013 को प्राप्त हुआ.

इस पत्र में लिखा है कि सिटीजन चार्टर के बारे में आप कृपया 27 अगस्त, 2011 को संसद द्वारा पारित संकल्प को याद कर सकते हैं. मुझे इस बात का दुःख हो रहा है कि 16 अगस्त, 2011 को मैं जब रामलीला मैदान में अनशन पर बैठा था, उस वक्त पूरे देश की जनता करोड़ों की संख्या में जन लोकपाल की मांग को लेकर सड़क पर उतर आई थी और 12 दिनों तक देश के सभी हिस्सों में जन आंदोलन चल रहा था. आपके सेहत की चिंता निर्माण हो गई है, आपने जल्दी अनशन छोड़ना ज़रूरी है, आपका ऐसा संदेश आने पर मैंने कहा था कि आप के कहने पर विश्वास करते हुए जल्द से जल्द तीन बातों पर फ़ैसला करें, 1) सिटीजन चार्टर, 2) हर राज्यों में सशक्त लोकायुक्त और 3) वर्ग अ, ब, क, ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाना. इन तीन मुद्दों को संसद में पास करा लो, बाकी बातों पर चर्चा करके निर्णय ले सकते हैं.

इसके मुताबिक, आपने 27 अगस्त, 2011 को रामलीला मैदान में अनशन की जगह पर मंत्री महोदय श्री विलासराव जी देशमुख के साथ पत्र भेजा था. उस पत्र में लिखा था, आपने अपने पत्र में उठाए तीन बिंदुओं पर एक रिजोल्यूशन पास किया है. आशा है कि आप संसद के रिजोल्यूशन को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः स्वस्थ होंगे. हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं. आपके इस पत्र पर मैंने पूरा विश्वास किया था. कारण, उसमें समाज और देश की भलाई थी. जीवन में अपने या अपने परिवार की भलाई के बारे में कभी सोचा नहीं है. दो साल बीतने आए हैं और आज भी आप मुझे यह कह रहे हैं कि आप 27 अगस्त, 2011 को संसद द्वारा पारित संकल्प को याद कर सकते हैं. क्या केवल संसद में पारित संकल्प को याद कर हम संतुष्ट रहें? क्या इसी में हमारी कार्यपूर्ति है?

आज मुझे महसूस हो रहा है कि जन लोकपाल क़ानून के लिए जब देश की करोड़ों जनता सड़क पर उतर आई थी, तब सरकार को शायद ख़तरे की आशंका हो उठी. इसलिए मेरा अनशन समाप्त करवा कर जनता के साथ कहीं यह धोखाधड़ी तो नहीं की गई? कारण कि संसद में बैठे हुए आप सभी महानुभाव अपनी तनखा बढ़ानी हो, हवाई-रेलयात्रा की सुविधा बढ़ानी हो, निवास की सुविधा जैसी कई सारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए बिल को सर्व सम्मति से एक दिन में पास कर लेते हैं, लेकिन समाज और देश की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने वाला जन लोकपाल जैसा बिल दो सालों तक पास नहीं होता है. वास्तव में जिन तीन मुद्दों पर संसद में रिजोल्यूशन सर्व सम्मति से पास हो गया है, उस पर दो साल बीत जाने का मतलब यही है कि सरकार की न तो कुछ करने की मंशा है और इच्छाशक्ति का अभाव तो है ही.

राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रसंग पर विरोध के होते हुए भी आपकी सरकार बहुमत हासिल कर सकती है, एफडीआई का विरोध होते हुए भी बहुमत प्राप्त कर सकती है, वैसे ही भ्रष्टाचार को रोकने वाले जन लोकपाल क़ानून के लिए बहुमत प्राप्त करना सरकार को असंभव नहीं था. दो साल हो जाने पर भी जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ. इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है कि सरकार ने 120 करोड़ जनता और अण्णा हज़ारे के साथ धोखाधड़ी की है. आपने मुझे जो झूठा आश्वासन देकर मेरा अनशन छुड़वाया था, वह मेरा अधूरा अनशन फिर से उसी रामलीला मैदान पर शुरू करने का निर्णय मैंने लिया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण जनता कितनी त्रस्त है, इसका अंदाजा हमेशा एयरकंडीशन में बैठने वालों को नहीं हो पाएगा. भ्रष्टाचार के कारण महंगाई ने चरम सीमा पार कर ली है. अपने परिवार को पालने वाले आम लोगों के दुःख और तकलीफ को आप और आपकी सरकार नहीं समझ रही है, न महसूस करती है. इसलिए मजबूर होकर मैं इस निर्णय पर आ गया हूं कि जब तक शरीर में प्राण हैं, तब तक मैं जन लोकपाल क़ानून के लिए रामलीला मैदान में अनशन पर बैठा रहूं. जनता का दुःख अब मुझे नहीं सहा जाता. मैंने मेरा जीवन ही उनके भलाई के लिए समर्पित किया है. कुछ ही दिनों में मैं अक्टूबर में होने वाले मेरे अनशन की तारीख निश्चित करके आपको बताऊंगा.

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों और उत्तराखंड के सभी जिलों में मैंने भ्रमण करते हुए लोगों को बताया है कि जन लोकपाल बिल के लिए मुझे फिर एक बार रामलीला मैदान पर अनशन करना होगा. इस आंदोलन में आपको भी शामिल होना है.

अब मेरी जनतंत्र यात्रा चल रही है. अभी और पांच राज्यों में जाकर लोगों को जगाऊंगा और फिर अगले पत्र में मैं अक्टूबर में होने वाले मेरे अनशन की तारीख बताऊंगा.

**धन्यवाद.**

**भवदीय**

**(कि. बा. उपनाम अण्णा हजारे)**
**रालेगणसिद्धी, दि. 1 जून, 2013.**

ए यू आसिफ
feedback@chauthiduniya.com

71 वर्षीय समाजसेवी बाबूराम हज़ारे, जो कि अन्ना हज़ारे के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के प्रतीक बन चुके हैं, ने 16 अगस्त से 27 अगस्त 2011 तक दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सफल अनशन एवं आंदोलन के बाद तीन बिंदुओं के संबंध में संसद में लिए गए संकल्प को पूरा न करने पर आगामी अक्टूबर में वहीं पर एक बार फिर से अनशन पर बैठने का बिगुल बजा दिया है. अन्ना ने यह बिगुल इस दौरान देश के पांच राज्यों का भ्रमण करने के बाद बजाया है. उनका अन्य राज्यों का भ्रमण निरंतर जारी है. अक्टूबर में अनशन पर बैठने से पहले वह और पांच राज्यों का भ्रमण कर चुके होंगे. उनके सभी दौरों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ-साथ पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह, पूर्व सांसद एवं चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय और सूफी जिलानी भी शामिल हैं.

इन दौरों के दौरान आम जनता में सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे न करने को लेकर गुस्सा साफ़ तौर पर महसूस होता है. हर जगह यह माहौल है. अन्ना ही नहीं, देश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है और आम आदमी की अपेक्षाओं एवं आशाओं पर पानी फेरा गया है. दरअसल, अन्ना ने आम जनता का मार्गदर्शन करते हुए एक जून, 2013 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे गए एक पत्र में रामलीला मैदान में अनशन करने का निर्णय लिया है. ख़ास बात यह है कि आम जनता में देश के मुसलमान भी पूर्ण रूप से शामिल हैं. अलग-अलग बातचीत के दौरान मुस्लिम संगठनों एवं रहनुमाओं की जो राय सामने आई है, उससे यही प्रतिक्रिया मिलती है. अन्ना ने ग्रामीण विकास और सरकार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ रखा है. इस संबंध में भी मुस्लिम समर्थन अन्ना के पक्ष में है, लेकिन मुस्लिम संगठनों एवं रहनुमाओं का यह कहना है कि मुसलमानों के साथ जो अत्याचार और भेदभाव होता है, उस पर भी अन्ना को खुलकर बोलना चाहिए. उन्हें इस बात की शिकायत है कि लंबे समय से हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर उनकी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

ओल्ड कैडर बेस्ड जमाअत इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर मोहम्मद सलीम का स्पष्ट रूप से कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और पारदर्शिता के पक्ष में अन्ना हज़ारे ने जो आंदोलन शुरू कर रखा है, जमाअत उसका समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि अन्ना के तीन बिंदुओं से संबंधित भारत सरकार ने जो वादे पौने दो साल पहले किए थे, उन्हें उसे पूरा करना चाहिए. लगभग दो साल पहले जमाअत की तर्ज़ पर बनी राजनीतिक पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 11 राज्यों में क़ायम है, के अध्यक्ष मुजतबा फ़ारूक़ कहते हैं कि उनकी पार्टी अन्ना के मिशन को सही समझती है. उनका कहना है कि संसद द्वारा महज़ संकल्प कर लेना मसले का हल नहीं है. उनके अनुसार, यह एप्रोच सरासर ग़लत है और कांग्रेस को किसी मसले को डाइल्यूट और सिस्टम को ख़राब करने में महारथ हासिल है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार पारदर्शी और ईमानदार होती, तो इसकी नौबत ही न आती. 1992 से सक्रिय ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मंज़ूर आलम सैद्धांतिक रूप से अन्ना हज़ारे के तीनों बिंदुओं से सहमत होते हुए कहते हैं कि सिटीज़न चार्टर और लोकपाल के दायरे में संबंधित ज़िम्मेदारों को लाने की बात तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक समस्या राज्यों में लोकायुक्त बिल पास कराने में होगी, क्योंकि केंद्र उससे संबंधित कुछ नहीं कर सकता है, केवल निर्देश दे सकता है. उनका कहना है कि लोकायुक्त से संबंधित गुजरात का बदतर उदाहरण हमारे सामने है, जिसके विरुद्ध कोई मुहिम नहीं छिड़ी. लिहाज़ा अन्ना की यह मुहिम राज्य सरकारों के विरुद्ध भी चलनी चाहिए.

उल्लेखनीय है कि मिल्ली काउंसिल सैद्धांतिक रूप से अन्ना के मिशन के साथ है और आरंभ में जंतर-मंतर पर मौजूद भी थी. 1964 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. ज़फ़रुल इस्लाम ख़ां का कहना है कि 27 अगस्त, 2011 को सरकार ने अन्ना हज़ारे को केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के हाथों भेजे गए पत्र में जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में वह बुरी तरह असफल रही है. जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया और उसे बुरी तरह मूर्ख बनाया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर विरोधाभास है. राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के हालिया फ़ैसले पर उसका एप्रोच एक उदाहरण है. इसके अलावा, इस सिलसिले में वह राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को भी ज़िम्मेदार मानते हुए कहते हैं कि उन दिनों उन्होंने इस मुद्दे पर बहस के दौरान सदन को स्थगित कर दिया था. उनके अनुसार, यह सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर ही हुआ था और इसके लिए उन्हें दोबारा नामित होकर ईनाम भी मिला. वह आगामी अक्टूबर में अन्ना के अनशन के फ़ैसले को उनका लोकतांत्रिक अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध भी आवाज़ उठानी चाहिए.

देश के प्राचीन संगठन जमीअत उलेमा-ए-हिंद के सचिव एवं प्रवक्ता अब्दुल हमीद नोमानी भी अन्य मुस्लिम रहनुमाओं की तरह यही कहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं, उसे उन्हें पूरा करना चाहिए और केवल इसी मामले में ही नहीं, बल्कि अन्य मामलों में भी. वह अनशन के अधिकार को लोकतांत्रिक अधिकार मानते हुए कहते हैं कि यह तो विरोध करने का गांधीवादी तरीक़ा भी है. वैसे उनका यह भी कहना है कि जमीअत के अंदर भ्रष्टाचार से संबंधित आधिकारिक रूप से कोई नीति नहीं बनी है और न ही कोई करारदाद पारित किया गया है और कभी-कभार ही इस पर बातचीत हुई है. 1906 में स्थापित मरकज़ी जमीअत अहले हदीस हिंद के प्रबंधक मौलाना असग़र इमाम मेहंदी सलफी मदनी भी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा अन्ना हज़ारे से ही नहीं, बल्कि देश की जनता से भी की गई वादाख़िलाफ़ी को गलत बताते हुए कहते हैं कि यह सब वे बातें हैं, जिनकी वजह से आम जनता का भरोसा राजनीतिक पार्टियों से उठता जा रहा है. सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसी नौबत हरगिज़ न आने दे कि अन्ना हज़ारे को एक बार फिर रामलीला मैदान में अनशन पर बैठना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए ख़ुदा का ख़ौफ़ भी शर्त है कि घूस लेने और देने वाले, दोनों के हाथ इस एहसास से स्वयं रुक जाएं.

मौलाना असग़र अली

पहले जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने के बाद अब सक्रिय राजनीति से दूर होकर दिल्ली से उर्दू दैनिक कौमी सलामती निकाल रहे 79 वर्षीय सिराज पराचा कहते हैं कि अन्ना हज़ारे के मिशन से कोई इंकार नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें स्थिरता की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू करते समय अन्ना को जनता का जो अपार समर्थन हासिल हुआ था, ऐसा लगता है कि उसे उचित ढंग से संगठित नहीं किया जा सका और सरकार ने झूठे वादे करके उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की. वह कहते हैं कि अन्ना अनशन कर रहे हैं, तो ज़रूर करें और जमकर करें, लेकिन पहले अपना मेडिकल चेकअप भी करा लें, ताकि अनशन के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमाल फ़ारूक़ी अन्ना हज़ारे द्वारा उठाए गए मुद्दे के हक़ में हैं और इस सिलसिले में कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने जो धोखा किया है, उसकी निंदा करते हुए वह कहते हैं कि मसले को हल करने की बजाय उसे टालना और उलझा देना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है.

अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ रखा है, उसे सराहते हुए वह यह भी कहते हैं कि उन्हें देश के मुसलमानों की समस्याओं में भी दिलचस्पी लेनी ही पड़ेगी. वह हैरान होते हुए कहते हैं कि अन्ना मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के संबंध में खुलकर क्यों नहीं बोलते? जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली की स्टूडेंट यूनियन के पूर्व महासचिव एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर इमदादुल्लाह जौहर का कहना है कि अन्ना हज़ारे ने जब दो साल पहले अपना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया, तो उन्हें ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ था और उसका मूल कारण यह था कि अन्ना जो कुछ कर रहे थे, उसमें आम जनता की सहमति थी और उस आंदोलन में युवाओं का बड़ी संख्या में शामिल होना था. ■

जाहिर है, केंद्रीय सूचना आयोग का यह फ़ैसला उन राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगा, जो बात पारदर्शिता की करते हैं, लेकिन अब जबकि ख़ुद की बारी आई है, तो खुलेआम विरोध करते नज़र आ रहे हैं.

## कोयला घोटाला

# मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं?

**कोयला घोटाला एक बार फिर चर्चा का विषय है. वजह, तत्कालीन कोयला सचिव से पूछताछ संबंधी सीबीआई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाना. इस तरह जांच को प्रभावित करने का एक और प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश को भरोसा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होकर ही रहेगा.**

डॉ. क़मर तबरेज़ feedback@chauthiduniya.com

पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे यूपीए सरकार के क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार को कोयला घोटाले की सीबीआई जांच रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम हटवाने की कोशिशों के कारण अपने पद से हाथ धोना पड़ा. हमने यह भी देखा कि किस तरह उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को विशेष निर्देश दिए कि यह जांच रिपोर्ट सरकार के किसी भी मंत्री को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे किसी मंत्री को तो बिल्कुल नहीं, जिसके विरुद्ध स्वयं मामले की जांच चल रही है. अब एक बार फिर सरकार की तरफ़ से सीबीआई जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. पिछले दिनों सीबीआई ने यूपीए सरकार को एक पत्र लिखकर पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता से पूछताछ करने की अनुमति मांगी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने उसे ठुकरा दिया. श्री गुप्ता इन दिनों कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. 1971 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एच सी गुप्ता को 2 जनवरी, 2006 को पी सी पारिख के सेवानिवृत्त होने के बाद कोयला सचिव बनाया गया था.

यह बात सभी जानते हैं कि देश में 26 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला 2006 से 2009 के बीच ही हुआ था, जब तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन के जेल में होने के कारण इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं देख रहे थे. उन दिनों कोयला ब्लॉकों का आवंटन पीएमओ की ओर से गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी देख रही थी, जिसकी निगरानी तत्कालीन कोयला सचिव एच सी गुप्ता कर रहे थे. यह स्क्रीनिंग कमेटी तमाम क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए कैसे कोयला खदानों की बंदरबांट कर रही थी, इसका अनुमान उस समय विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों से लगाया जा सकता है. दूसरी ओर कोयला सचिव श्री गुप्ता पीएमओ को बार-बार पत्र लिखकर अवगत करा रहे थे कि कोयला खदानों के आवंटन में नीलामी सिस्टम अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि नियम हैं, लेकिन पीएमओ ने इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और वह उनके प्रस्ताव को हर बार ठुकराता रहा.

अब, जबकि सीबीआई कोयला घोटाले की जांच कर रही है, तो वह श्री गुप्ता से उन सभी घटनाओं का विवरण जानना चाहती है, लेकिन सरकार है कि बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती है. उसने सीबीआई के श्री गुप्ता से पूछताछ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. जांच टीम के लिए यह जानना आवश्यक है कि कोयला खदानों की नीलामी कराने के कोयला सचिव के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्यों नज़रअंदाज़ किया? इसके अलावा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पीएमओ में बैठे किस व्यक्ति या अधिकारी ने कोयला सचिव की राय रिजेक्ट की. देश को यह भी मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह निर्णय किस नियम के तहत किया.

उल्लेखनीय है कि सबसे पहले चौथी दुनिया ने बताया था कि देश में 26 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला हुआ है. यह एक ऐसा घोटाला था, जिसने भारत में अब तक हुए सभी घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पहले तो किसी ने चौथी दुनिया की इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले साल जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हां, कोयला घोटाला हुआ है, तब जाकर सबको विश्वास हुआ, लेकिन सीएजी ने इस घोटाले को कम करके दिखाया और बताया कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में होने वाली धांधली से देश के ख़ज़ाने को 10.67 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. इसके विपरीत चौथी दुनिया अब भी इस बात पर क़ायम है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिन दिनों कोयला मंत्रालय देख रहे थे, उन दिनों कोयला खदानों के आवंटन में होने वाली धांधली के कारण देश को 26 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. चूंकि कोयला खदानों के आवंटन के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही इस मंत्रालय को देख रहे थे, लिहाज़ा उन्हें अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी अब भी उन्हें ईमानदार और साफ़-सुथरा नेता साबित करने में जुटी हुई है. ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या सीबीआई कोयला घोटाले की निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय जांच कर पाएगी, वह भी ऐसे समय में, जबकि मनमोहन सिंह ख़ुद प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं. ■

### वे सवाल, जिनके जवाब आने बाकी हैं

कोयला सचिव एच सी गुप्ता लगातार इस बात के लिए पत्र लिख रहे थे कि कोयला खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए हो, लेकिन सरकार अब कह रही है कि यह एक नीतिगत फ़ैसला था कि स्टील, बिजली एवं सीमेंट कंपनियों को देश का विकास करने के लिए कोयला खदानें मुफ्त में बांट दी जाएं. अब सवाल यह उठता है कि क्या इस नीति के बारे में कोयला सचिव को पता नहीं था? जाहिर है, इस नीति का फ़ैसला कैबिनेट ने ही लिया होगा, तो अब तक सरकार ने कैबिनेट के उस फ़ैसले को सामने क्यों नहीं रखा और उसके बारे में कोयला सचिव को क्यों नहीं बताया गया? इसका मतलब यह है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री और अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है. अगर यह नीतिगत फ़ैसला था, तो कोयला सचिव की चिट्ठी के जवाब में कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई? सरकार की कोयला खदान मुफ्त में बांटने की नीति क्या महज एक दिमागी उपज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई नीति ही न हो और घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी इसके बहाने घोटाले पर पर्दा डालना चाह रहे हैं. ■

## आरटीआई और राजनीतिक दल

# फिर दिखा असली चाल, चरित्र और चेहरा

**पंच का हुक्म भी नहीं मानेंगे और नाला भी वहीं बहेगा. यानी चोरी के साथ सीनाजोरी भी करेंगे, क्योंकि सैयां और भैया हैं कोतवाल, तो डर काहे का? और ऐसा हो भी क्यों न, जबकि हम्माम में सब नंगे हों या फिर चोर-चोर मौसेरे भाई. इतने सारे हिंदी मुहावरों के इस्तेमाल के पीछे एक मजबूरी है. वह यह कि आख़िर आप चाहकर भी मौजूदा हालात में, मौजूदा तरीके से राजनीति कर रहे मौजूदा राजनीतिक दलों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? भ्रष्टाचार की बात रहने दीजिए, लोकपाल की भी बात थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और सिर्फ़ एक सवाल इन राजनीतिक दलों से पूछिए कि आख़िर वे आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहते?**

शशि शेखर shashishekhar@chauthiduniya.com

**कार्यकर्ता अपनी पार्टी में आरटीआई डालकर अंदर की ख़बर बाहर कर सकते हैं. ऐसे में, पार्टी हाईकमान चाहकर भी मनमाने फ़ैसले नहीं कर पाएगा, यानी राजनीतिक पार्टियों में शुरू से चली आ रही हाईकमान संस्कृति को इस फ़ैसले से ख़तरा दिखाई दे रहा है.**

केंद्रीय सूचना आयोग का एक आदेश क्या आया, मानो राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया हो. बड़ी-बड़ी पार्टियों के नेताओं के ऐसे-ऐसे बयान आने लगे, मानो कोई उनसे सूचना नहीं मांग रहा, बल्कि किसी ने उनकी इज्जत पर हमला कर दिया हो. दरअसल, आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल की अपील पर सुनवाई करते हुए जन केंद्रीय सूचना आयोग ने यह आदेश दिया कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं. इस फ़ैसले के पीछे आयोग ने आधार गिनाए थे कि राजनीतिक दल केंद्र सरकार से बहुत ही कम क़ीमत पर ज़मीन लेते हैं, उन्हें बंगला मिलता है, आयकर में छूट मिलती है, वे जनता का काम करते हैं और चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होते हैं. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका, उनका कामकाज एवं चरित्र आदि भी उन्हें आरटीआई के दायरे में लाते हैं. संवैधानिक एवं क़ानूनी प्रावधानों में भी उनका चरित्र सार्वजनिक संस्थाओं का है. इन सारी वजहों से वे आरटीआई के दायरे में आते हैं.

जाहिर है, केंद्रीय सूचना आयोग का यह फ़ैसला उन राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगा, जो बात पारदर्शिता की करते हैं, लेकिन अब जबकि खुद की बारी आई है, तो खुलेआम विरोध करते नज़र आ रहे हैं. दरअसल, इन पार्टियों को यह डर सता रहा है कि इस फ़ैसले की वजह से अब उन पैसों के बारे में भी जनता जानकारी पा सकेगी, जिनका कोई रिकॉर्ड वे यह कहकर नहीं रखतीं कि अमुक चंदा 20 हज़ार रुपये से कम का है. अरबपति बन चुकीं इन पार्टियों को मिल रहे चंदे की जानकारी वैसे तो चुनाव आयोग से मिलती रही है, लेकिन इसमें वह चंदा शामिल नहीं होता, जो 20 हज़ार रुपये से कम होता है. दूसरी बात, अगर यह फ़ैसला लागू होता है, तो किसी भी पार्टी के ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ता, जिनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन जिन्होंने पार्टी के लिए जी-जान से काम किया और जिन्हें आजीवन न तो कोई पद मिला और न ही टिकट, वे अपनी पार्टी में आरटीआई डालकर अंदर की ख़बर बाहर कर सकते हैं. ऐसे में, पार्टी हाईकमान चाहकर भी मनमाने फ़ैसले नहीं कर पाएगा, यानी राजनीतिक पार्टियों में शुरू से चली आ रही हाईकमान संस्कृति को इस फ़ैसले से ख़तरा दिखाई दे रहा है.

बहरहाल, आरटीआई एक्ट पास करने वाली कांग्रेस की बात तो छोड़िए, जिसके एक वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी यह कहते हुए इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं कि हम एक स्वैच्छिक संगठन हैं, बल्कि इस फ़ैसले ने वरिष्ठ समाजवादी और वामपंथी नेताओं की दकियानूसी सोच को भी जनता के सामने उजागर कर दिया है. जद (यू) अध्यक्ष शरद यादव इस फ़ैसले का विरोध करते हुए कहते हैं कि हम कोई किराना-परचून की दुकान नहीं हैं कि हमारे यहां कोई आरटीआई लगाकर कोई भी सूचना मांग ले. सीपीएम महासचिव प्रकाश करात कहते हैं कि आरटीआई सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता के लिए है, यह हमारे लिए नहीं होना चाहिए. वहीं भाजपा इस मसले पर अभी तक अपनी कोई स्पष्ट राय नहीं दे सकी है. असल में, वह इस मामले में भी राजनीति ही कर रही है. उसे पता है कि जब इतने सारे उसके साथी राजनीतिक दल इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं, तो उसे कुछ उल्टा बोलकर अपनी खिंचाई क्यों करानी चाहिए? लेकिन यह वही भाजपा है, जो डाओ कंपनी से भी लाखों का चंदा लेती है. ग़ौरतलब है कि यह वही डाओ है, जिसने हज़ारों लोगों की हत्या के लिए ज़िम्मेदार यूनियन कार्बाइड को खरीदा है.

वैसे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अभी जो विरोध राजनीतिक दलों की ओर से दिख रहा है, उससे लगता है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अब चाहे जो भी हो, इस फ़ैसले का भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. कुछ प्रभाव तो अभी से ही पड़ने शुरू हो गए हैं, मसलन कि पारदर्शिता के नाम पर सारे राजनीतिक दलों का मुखौटा उतर चुका है. दूसरा यह कि जनता को भी अपने नेताओं की नीति और नीयत एक बार फिर क़रीब से जानने का मौक़ा मिल गया है. अब देखना यह है कि इस फ़ैसले की क़ीमत कौन चुकाता है, राजनीतिक दल, मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना का अधिकार क़ानून? ■

पांच राज्यों के उक्त उपचुनावों को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमी-फाइनल के रूप में देखा जा रहा था, पर उनके नतीजों ने कांग्रेस को निराश कर दिया.

# उपचुनाव के नतीजे

# कांग्रेस का सपना चकनाचूर

***हाल में हुए लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के उपचुनावों के परिणामों ने सबको चौंका दिया है. बिहार में राजद की जीत ने जहां एक नया संदेश दिया है, वहीं गुजरात में जीत के चलते भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ़ हताशा ही हाथ लगी है.***

**अशरफ अस्थानवी**

feedback@chauthiduniya.com

बीते 5 जून को देश के तीन राज्यों में लोकसभा की चार सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिनमें से पश्चिम बंगाल की हावड़ा सीट पर तृणमूल कांग्रेस, बिहार की महाराजगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और गुजरात में बनासकांठा एवं पोरबंदर, यानी दोनों सीटों पर भाजपा को विजयश्री मिली. यही नहीं, गुजरात विधानसभा की चार सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए और आश्चर्यजनक रूप से भाजपा ने ये चारों सीटें कांग्रेस से छीन लीं. इन उपचुनावों के नतीजों को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रदर्शन के बारे में भविष्यवाणी करें, तो उसे उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आम चुनाव और उपचुनावों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है. जनता जिस उत्साह से आम चुनाव में हिस्सा लेती है, उतनी रुचि वह उपचुनावों में नहीं लेती. यही वजह है कि इन चारों लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत 40-47 के बीच रहा. ज़ाहिर है, इतने कम मतदान की बुनियाद पर हम जनता के मूड का अनुमान नहीं लगा सकते कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसकी पहली, दूसरी या तीसरी पसंद कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी.

जहां तक राजनीतिक गठजोड़ की बात है, तो जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि वह कांग्रेस से अलग रहकर भी चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहीं बिहार में नीतीश कुमार के लिए बाज़ी उलट चुकी है. उन्हें शायद अब यह एहसास हो गया है कि भाजपा के सहारे के बिना वह बिहार में एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ा सकते. यह बात और है कि पिछले कुछ महीनों से केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर मेहरबानियों का सिलसिला शुरू किया है, उससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़े, लेकिन ऐसी स्थिति में बिहार में उन्हें इसका शायद ज़्यादा फ़ायदा न मिले. हां, कांग्रेस को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है. तृणमूल एवं जेडीयू काबिल है. ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में इस राज्य में तृणमूल कांग्रेस से अलग होना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है.

कमोबेश यही स्थिति पड़ोसी राज्य बिहार की है. यहां महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह ने जदयू प्रत्याशी एवं राज्य के शिक्षा मंत्री पी के शाही को एक लाख 37 हज़ार से भी ज़्यादा मतों से करारी शिकस्त दी, वह नीतीश का जलवा कम होने का संकेत है. केंद्रीय राजनीति में बिहार की बड़ी भूमिका का महत्व समझते हुए कांग्रेस यहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सियासी रणनीतियों पर काम कर रही थी, लेकिन महाराजगंज के नतीजे ने उसके सारे किए-कराए पर पानी फेर दिया. यहां कांग्रेस प्रत्याशी, जो दिवंगत सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं, अपनी जमानत तक नहीं बचा सके. वैसे इस चुनाव में सहानुभूति फैक्टर प्रभावी न होने का अनुमान कांग्रेस को पहले से ही था, फिर भी उसने जानबूझ कर जितेंद्र स्वामी को मैदान में उतारा, ताकि राजपूत वोटों में विभाजन हो जाए और राजद की बजाय जदयू प्रत्याशी जीत जाए. इसके पीछे कांग्रेस की सोच यह थी कि बिहार में नीतीश को भाजपा से अलग करके यहां उनके साथ गठजोड़ कर खुद को मजबूत किया जाए और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को कमजोर, लेकिन महाराजगंज के नतीजे ने उसके इस समीकरण को अंगूठा दिखा दिया. वहीं दूसरी ओर राजद की लगातार यह कोशिश रही कि कांग्रेस के साथ उसके टूटे संबंध फिर से जुड़ जाएं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर यह सोच बनी कि अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है और राज्य की राजनीति में उनकी पुनर्वापसी संभव नहीं है. उसके इस अनुमान को बल मिला, नीतीश की सूबे में बनी लोकप्रियता और दूसरी बार सत्ता में लौटी एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए चार विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में उसकी जीत से. इस दौरान कांग्रेस को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि राज्य में निचले स्तर पर प्रशासनिक अराजकता की वजह से नीतीश के ख़िलाफ़ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है.

बिहार को कई मदों में आसानी से मिल रही केंद्रीय सहायता एवं राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख और पिछले महीने नीतीश कुमार द्वारा वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कांग्रेस मुख्यालय तक छोड़ने जाने के प्रसंग को इस बात से स्पष्ट रूप से जोड़कर देखा गया कि उनकी कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ रही हैं. इस सियासी खेल पर पैनी नज़र रख रही उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा के कई नेताओं ने सांकेतिक रूप से कड़ी टिप्पणियां भी की थीं. वहीं धर्मनिरपेक्षता के सवाल को लेकर जिस तरह नीतीश एवं उनके दल के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ उकसाने वाली टिप्पणियां की थीं, उससे भी भाजपा आहत हुई थी. दोनों दलों के बीच कई बार यह तकरार इतनी बढ़ी कि गठबंधन कभी भी टूटने की स्थिति बन गई.

दरअसल, पांच राज्यों के उक्त उपचुनावों को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमी-फाइनल के रूप में देखा जा रहा था, पर उनके नतीजों ने कांग्रेस को निराश कर दिया. उसे इस बात का संकेत मिला कि बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार एवं आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर जनता में काफी नाराज़गी है. उधर, कमजोर विपक्ष के चलते अहंकार में डूबे नीतीश कुमार को लगा कि बिहार में तो उनका खूंटा गड़ा ही है, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से उनका महत्व बढ़ रहा है, उसे देखते हुए देश की अगली सरकार और उसके प्रधानमंत्री के चयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. इतना ही नहीं, वह भाजपा को दबाव में रखते हुए अपने हिसाब से गठबंधन की राजनीति चलाना चाह रहे थे, पर महाराजगंज के नतीजे ने उन्हें निराश कर दिया. अब उनकी स्थिति मजबूरी वाली हो गई है और वह यह कि उन्हें भाजपा के इशारे पर काम करना होगा या फिर ख़तरों से भरी अलग राह चुननी होगी, जिसमें सिवाय राजनीतिक नुकसान के, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला और उनकी इसी मजबूरी को अपनी ताकत बनाने में लगे हैं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव.

दूसरी ओर, नीतीश का हश्र देखने के बाद अब कांग्रेस के सामने अपने पुराने साथियों से फिर से हाथ मिलाने की स्थिति बन गई है, जिनमें बिहार में राजद, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एवं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी शामिल हैं. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ दोस्ती अब उसकी मजबूरी हो गई है. अब देखना यह है कि बिहार में नीतीश का अगला क़दम क्या होता है और कांग्रेस की नई सियासी रणनीति क्या होती है. इन सबके बीच उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा अगले वर्ष लोकसभा चुनाव की जंग में अब बेहिचक नरेंद्र मोदी पर दांव खेलने को तैयार दिख रही है. ■

## लोकसभा उपचुनाव में विजयी उम्मीदवार

| चुनाव क्षेत्र | उम्मीदवार | पार्टी | मतों का अंतर |
|---|---|---|---|
| हावड़ा (प. बंगाल) | प्रसून बनर्जी | तृणमूल कांग्रेस | 27 हज़ार |
| महाराजगंज (बिहार) | प्रभुनाथ सिंह | आरजेडी | 1.37 लाख |
| पोरबंदर (गुजरात) | विट्ठल राडिया | भाजपा | 1.28 लाख |
| बनासकांठा (गुजरात) | हरिभाई चौधरी | भाजपा | 71 हज़ार |
| | | | |

से अलग नरेंद्र मोदी ने इन नतीजों के बाद भाजपा में अपनी स्थिति अधिक मज़बूत कर ली है. वह बड़ी तेज़ी से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की ओर बढ़ रहे हैं. यह अलग बात है कि उन्हें पार्टी के अंदर खींचतान का शिकार होना पड़ रहा है.

पांच राज्यों में सिर्फ महाराष्ट्र के एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जीत का स्वाद चखने को मिला, जबकि सभी जगह उन दलों ने जीत का परचम लहराया, जिनसे कांग्रेस के संबंध ठीकठाक नहीं हैं. इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में खराब प्रशासनिक स्थिति के बावजूद सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने हंडिया सीट जीत ली, जबकि कांग्रेस इस राज्य में काफी मेहनत कर रही है, खासकर राहुल गांधी की यह सियासी ज़मीन रही है. चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि कभी कांग्रेस का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश आज भी उसे सुकून देने को तैयार नहीं है, जबकि केंद्र की सत्ता के लिए इस बड़े राज्य में बेहतर प्रदर्शन ज़रूरी है. अगर देखा जाए, तो उक्त उपचुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा और मसले भी क्षेत्रीय ही प्रभावी हुए. राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भले ही भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया हो, पर उसका आधार भी गुजरात के स्तर पर मोदी की भूमिका से जुड़ा रहा. कांग्रेस से रिश्ता तोड़ चुकी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने हावड़ा लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहरा कर यह साफ़ कर दिया कि बंगाल में उसका वजूद आज भी ठोस है और उसे कांग्रेस के साथ न रहने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा. राज्य की खराब वित्तीय स्थिति, नक्सल समस्या और अन्य कई प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस राज्य में न तो वाममोर्चा और न ही कांग्रेस फिलहाल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सेहत बिगाड़ने के

सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि क्यों न अनाज को ग़रीबों में बांट दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था.



# खाद्य सुरक्षा बिल

# रोटी से खेलने वाला कौन है देश की संसद मौन है...

**ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट को भी पीछे छोड़ चुकी कांग्रेस सरकार दरअसल सरकार नहीं, परिवार चला रही है. भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इस सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा बिल 80 करोड़ लोगों की भूख का नहीं, बल्कि उनकी रोटी की लूट का मामला है. यह सरकार ग़रीबों एवं भूखों की रोटी से सियासत का एक भी मौक़ा नहीं छोड़ती, लेकिन येन-केन-प्रकारेण खाद्य सुरक्षा बिल पास कराकर फिर से सत्ता में आने का सपना देख रही इस पत्थर दिल सरकार की ज़ुबान पर इसकी लालची लार साफ़ झलकने लगी है.**

राजीव रंजन feedback@chauthiduniya.com

यूपीए और खासकर, कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल पर हो-हल्ला मचा रखा है. सवाल यह उठता है कि कहीं सरकार का यह उतावलापन और छटपटाहट किसी बड़ी लूट की साजिश का हिस्सा तो नहीं? मनरेगा की तरह कहीं सरकार इस बिल को पास कराकर इसमें बड़े पैमाने पर पैसों की बंदरबांट और लूट की संभावना तो नहीं तलाश रही है? यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे. दरअसल, मनरेगा के बूते लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली कांग्रेस हर हाल में आम चुनाव से पहले खाद्य सुरक्षा बिल को क़ानूनी जामा पहनाना चाहती है. कांग्रेस के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि इससे पार्टी का भाग्य फिर से चमक सकता है. मनरेगा और इसी तरह की कुछ अन्य लोक-लुभावन योजनाओं के बल पर वह पिछले चुनाव में सत्ता में आई. पूरे शासनकाल के दौरान उसने जमकर लूटपाट मचाई और अभी भी जनता को लूटने का काम ही कर रही है, लेकिन अब उसकी लूटपाट के दिन ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं. ऐसे में साफ़ है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर इतनी बेचैन क्यों है. सवाल यह उठता है कि वह पिछले चार सालों से क्या कर रही थी? आख़िर कांग्रेस को ग़रीब और भूखी जनता की चिंता चुनाव के पहले ही क्यों सताने लगती है? दरअसल, उसकी मंशा यह बिल लागू करके चुनाव में लाभ लेना और फिर उसके बाद सत्ता में आकर मनरेगा की तरह खुली लूट की है. निजी तौर पर कई सांसदों एवं पार्टियों को खाद्य सुरक्षा बिल पर आपत्ति है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए देश में आवश्यक ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं और साथ ही यह आशंका भी है कि इससे बड़े पैमाने पर बर्बादी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

यूपीए की सहयोगी एनसीपी के प्रमुख एवं कृषि मंत्री शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार के पास न तो यह योजना चलाने के लिए पैसा है और न ही इसे लागू करने के लिए पर्याप्त सरकारी ढांचा. उन्होंने यह भी दावा किया कि इसे लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अनाज भंडार हैं ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि क्यों न अनाज को ग़रीबों में बांट दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था. सच पूछिए, तो सरकार की असली मंशा बिल पास कराना नहीं, बल्कि विशेष सत्र है. जब अगस्त में मानसून सत्र होना सुनिश्चित है, तो सरकार इस बिल को लेकर इतनी उतावली क्यों है? सीधी सी बात है कि कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल पारित तो कराना चाहती है, लेकिन वह इसके क्रियान्वयन में होने वाली खामियां उजागर होने का ख़तरा नहीं उठा सकती. अगर आम चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में हुए, तो खाद्य सुरक्षा को लेकर मिलने वाली शिकायतें किसी भी वाहवाही को पीछे छोड़ देंगी. ऐसे में, बेहतर विकल्प यही है कि इसे पारित करा लिया जाए और नवंबर-दिसंबर में चुनाव की घोषणा कर दी जाए.

खाद्य सुरक्षा बिल लागू करना बड़ी बात नहीं है. दरअसल, इसके प्रावधानों का ईमानदारी से क्रियान्वयन और उसे बनाए रखना बड़ी बात है, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार के घोटालों और पिछली योजनाओं में लूट को देखकर इसकी नीयत पर संदेह होना लाजिमी है. झूठे वादे, लोक-लुभावन योजनाएं लाकर उन्हें चुनाव के समय लागू करने के लिए धींगामुश्ती करना, भोली-भाली जनता का वोट लेकर सत्ता में आने के बाद मामा, दामाद एवं भाई-भतीजावाद के माध्यम से अपने शासन के दौरान जनता को ही लूटना और सहयोगी दलों को भी खुले हाथों लूटने की खुली छूट देना, कांग्रेस की पहचान बन गई है.

क्या कांग्रेस के पास उन सवालों के जवाब हैं, जो अभी भी इस योजना को लेकर अनुत्तरित हैं. मसलन, केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में मनमाने ढंग से वृद्धि का खामियाजा अनाज खरीदने वाली राज्य सरकारों को भुगतना पड़ता है. यही वजह है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और यदि एफसीआई द्वारा अनाज की खरीदारी नहीं हुई, तो वह धीरे-धीरे बर्बाद हो जाता है. लाभार्थियों की सटीक पहचान में हेराफेरी हो सकती है. उन्हें खाद्यान्नों का समय पर वितरण हो पाना मुश्किल है, क्योंकि मनरेगा में इस तरह की गड़बड़ियां आम हैं. वितरण के लिए राज्यों द्वारा प्रयास में उदासीनता ज़रूर देखने को मिलेगी. प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित क्रियान्वयन होना ज़रूरी है, जो संभव नहीं दिखता. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क का कंप्यूटरीकरण ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं हो सका है. बायोमीट्रिक पहचान और खाद्यान्नों का स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण सुनिश्चित करना ज़रूरी है, जो इतना आसान नहीं है. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्यान्न वितरण पर जीपीएस ट्रैकिंग के तहत सटीक निगरानी भी ज़रूरी है, लेकिन जब अन्य क्षेत्रों में उक्त तकनीकें नहीं लागू की जा सकी हैं, तो इसके लिए लागू होना टेढ़ी खीर ही है. लाभार्थियों को एसएमएस एलर्ट भी मिलना चाहिए, जो संभव नहीं दिखता. सीसीटीवी निगरानी और मीडिया अभियानों के जरिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा नहीं की जा सकती, जो घपलों को रोक सकें. नौकरशाही की दखलंदाजी रोकना एवं प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना इतना आसान नहीं है और जब तक प्रशासन की लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक किसी भी बिल या योजना की सफलता में संदेह है. ■

## गंभीर सवाल

- बिल कहता है कि राज्य ग़रीबों की सूची प्रदान करेंगे, लेकिन राज्यों के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है. सरकार ने ग़रीबी रेखा निर्धारण के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया, लेकिन उनके आंकड़े भिन्न हैं.
- सरकार का ग़रीबों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) इस्तेमाल करने का इरादा है. पीडीएस का इस्तेमाल पहले से ही ग़रीबों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस तरीके से वितरित अनाज का क़रीब 52 फ़ीसद फिलहाल बर्बाद हो जाता है.
- क्या भारत इस बिल द्वारा उत्पन्न मांग के बराबर अनाज का उत्पादन कर सकता है?
- सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में क्या होगा?
- सब्सिडीकृत अनाज के बहुत कम दाम बाज़ार एवं उन किसानों को, जो सरकार द्वारा लागू कार्यक्रम के लिए अपना अनाज नहीं बेच सकते, विकृत कर देंगे. ऐसे किसान खुले बाज़ार में बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि दाम दबाव वश कम होंगे.
- खाद्य सुरक्षा विधेयक के क़ानून बन जाने की दशा में राशन प्रणाली समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 6.13 करोड़ टन अनाज की ज़रूरत होगी और इसके लिए सवा लाख करोड़ रुपये चाहिए.
- इस व्यापक कार्यक्रम के लिए भारी खाद्य सब्सिडी की ज़रूरत होगी. इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 फ़ीसद से 1.1 फ़ीसद हो सकती है. जब सरकार के पास ज़्यादा स्रोत नहीं हैं, तो यह एक गंभीर वृद्धि होगी.
- कुल मिलाकर खाद्य सब्सिडी लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये बैठ रही है. सूत्रों के अनुसार, खजाने की सेहत यह बोझ उठाने के काबिल नहीं है.
- सरकार कहती है कि वह इस बिल के तहत सालाना 62 मिलियन टन अनाज प्रदान करेगी और सब्सिडी का आकार अनुमानत: 24 बिलियन डॉलर होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ साबित होगा.
- बढ़ती आबादी की वजह से इस बात की संभावना है कि अनाज वितरण की मात्रा में भी वृद्धि होगी.
- अनाज की लदाई, ढुलाई, सस्ते गल्ले की दुकानों के संचालन, उनके लाभ मार्जिन और अन्य खर्च के लिए 24 हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त ज़रूरत होगी.
- सरकार प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण पर भी विचार कर रही है. उन मामलों में, जहां सरकार पीडीएस के तहत अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएगी, वहां वह लोगों के बैंक खातों में अनाज खरीदने के लिए नकद भुगतान करेगी. लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि लोगों के पास कैश होने पर उचित दर पर अनाज मिलेगा ही.
- योजना की बढ़ती लागत देखते हुए, इसकी निरंतरता सवालों के घेरे में है. ■

## सरकार की नीयत में खोट!

- खाद्य सुरक्षा बिल के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों?
- कहीं यह ग़रीब जनता को गुमराह करने की साजिश तो नहीं?
- मनरेगा की तरह यह योजना भी लूट की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी?
- पिछले चार सालों से इस बिल को लेकर क्या कर रही थी सरकार?
- इस योजना के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ?
- कहीं इस बिल का हश्र भी शिक्षा का अधिकार क़ानून जैसा तो नहीं हो जाएगा?
- खाद्य सुरक्षा बिल का मकसद कहीं आम चुनाव में वोट हासिल करना तो नहीं? ■

## प्रावधान

- दावा किया गया है कि इससे देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा.
- खाद्य सुरक्षा विधेयक का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के 63,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव.
- कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव.
- ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आबादी को इस विधेयक का लाभ दिया जाएगा, जिनमें से कम से कम 46 प्रतिशत प्राथमिकता श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा.
- शहरी इलाकों में कुल आबादी के 50 फ़ीसद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इनमें कम से कम 28 फ़ीसद प्राथमिकता श्रेणी के लोग होंगे.
- विधेयक के प्रावधानों के तहत देश की 63.5 फ़ीसद जनता को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
- गर्भवती या बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं, आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों एवं बुजुर्गों को पका हुआ खाना मुहैय्या कराया जाएगा.
- नया क़ानून लागू होने पर कम दाम में गेहूं और चावल पाना निर्धन लोगों का अधिकार बन जाएगा.
- स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे.
- अगर सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है, तो योजना के लाभार्थियों को उसके बदले पैसा दिया जाएगा. ■

## आगे हैं कई राज्य

**छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं उड़ीसा समेत तकरीबन आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने केंद्र सरकार के सोचने के साथ ही खाद्य सुरक्षा विधेयक के अधिकांश प्रावधान लागू कर दिए हैं, जबकि केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद से ही यूपीए सबको अति रियायती दर पर अनाज देने की घोषणा ही करता रह गया. इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं राजस्थान ने खाद्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ा दिया है. सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में पहले से ही सब्सिडी खाद्य कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां दोनों एक साथ कैसे चलेंगे अथवा क्या इससे दोनों कार्यक्रम अस्त-व्यस्त नहीं होंगे? ■**

डॉ. अंबेडकर की एक और चेतावनी पर ध्यान दीजिए. यह चेतावनी आज बिल्कुल सच साबित होती जा रही है. संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में वह कहते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

## संविधान, राजनीतिक दल और लोकतंत्र

# डॉ. अंबेडकर की चेतावनी सच साबित हो रही है

**25 नवंबर, 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था. संविधान सभा संविधान बनाने की अपनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी थी. हज़ारों विषयों पर बहस हुई. हज़ारों संशोधन आए. कुछ माने गए और कुछ नहीं माने गए. इसी दिन, यानी 25 नवंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था. अपने भाषण में बहुत सारी बातों के अलावा, उन्होंने न केवल कुछ ऐसी बातें कहीं, बल्कि कुछ ऐसी आशंकाएं भी जताई थीं, जो मौजूदा समाज, राजनीतिक हालात एवं लोकतंत्र के बारे में सही और सटीक साबित होती दिख रही हैं. आइए, ऐसी ही कुछ आशंकाओं एवं चेतावनियों पर एक नज़र डालते हैं और उन्हें मौजूदा परिदृश्य के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं.**

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में डॉ. अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी. उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल की एक उक्ति का उदाहरण देते हुए कहा था, भारतीयों को एक महान व्यक्ति के पैर में अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखनी चाहिए और उन शक्तियों के साथ उस महान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जिनसे वह संस्थाओं का नाश करने में सक्षम हो जाए. उन्होंने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम उन लोगों के प्रति आभारी बनें, जिन्होंने देश के लिए जीवन भर सेवाएं दीं, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होनी चाहिए. डॉ. अंबेडकर चिंता जताते हुए कहते हैं, भक्ति (किसी व्यक्ति की) या नायक पूजा लोकतंत्र के क्षरण और संभावित तानाशाही के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है.

बहरहाल, अगर 64 साल पहले दी गई इस चेतावनी पर नज़र डालें, तो हम पाएंगे कि आज भारतीय राजनीति में वही सब कुछ दिख रहा है. और सिर्फ़ आज की ही बात नहीं, नेहरू युग के वक्त और उसके बाद भी भारतीय राजनीति में भक्ति और नायक पूजा की जो परंपरा शुरू हुई, वह आज तक कायम है. इसी भक्ति परंपरा का ही परिणाम था कि इंदिरा गांधी के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने एक नारा दिया कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा. इसी भक्ति परंपरा का ही परिणाम रहा कि देश को आपातकाल के रूप में तानाशाही के दिन देखने पड़े. यानी भक्ति या कहें कि व्यक्ति पूजा के आगे देश का लोकतंत्र भी बौना पड़ गया. इसके बाद से भारतीय राजनीति में जिस वंश परंपरा की नींव पड़ी, वह आज तक जारी है. कांग्रेस में इंदिरा गांधी की विरासत को बढ़ाने के लिए आज भी राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी की भक्ति जारी है. आज कुल 20 से 25 ऐसे राजनीतिक दल इस देश में हैं, जो 120 करोड़ लोगों पर शासन करते हैं और क़रीब-क़रीब ये सारे दल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हैं. नेता बूढ़ा हो जाता है, तो उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है. पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं की अहमियत एक बंधुआ मज़दूर जैसी होती है. पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर भद्दा मजाक होता है. एक ही व्यक्ति आजीवन अध्यक्ष बने रहना चाहता है. उसके विरोध में कोई चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता. और अगर दिखाता भी है, तो समझिए कि उसका राजनीतिक करियर चौपट. कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद और सीताराम केसरी का उदाहरण सामने है. सीताराम केसरी सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाहते थे और जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था. आज इन दोनों नेताओं का नामलेवा तक आपको कांग्रेस में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. यह हाल है, राजनीतिक प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन भक्ति एवं नायक पूजा परंपरा ने जनता के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार का भी मजाक बनाकर रख दिया है.

डॉ. अंबेडकर की एक और चेतावनी पर ध्यान दीजिए. यह चेतावनी आज बिल्कुल सच साबित होती जा रही है. संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में वह कहते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यह बात मुझे चिंतित करती है. मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि जात-पात, पंथ जैसे अपने पुराने शत्रु के अलावा, आगे हमारे पास विविध एवं विरोधी मानसिकता के राजनीतिक दल होंगे. क्या भारतीय लोग उनके मत के ऊपर देश को जगह देंगे या वे लोग देश से ऊपर अपने मत को जगह देंगे? मुझे यह नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि अगर ये राजनीतिक दल देश के ऊपर अपने मत को रखते हैं, तो निश्चित ही हमारी स्वतंत्रता ख़तरे में दूसरी बार पहुंच जाएगी और शायद हम हमेशा के लिए इसे खो दें. इस स्थिति से बचने के लिए हम सबको सख्ती से उठ खड़ा होना होगा.

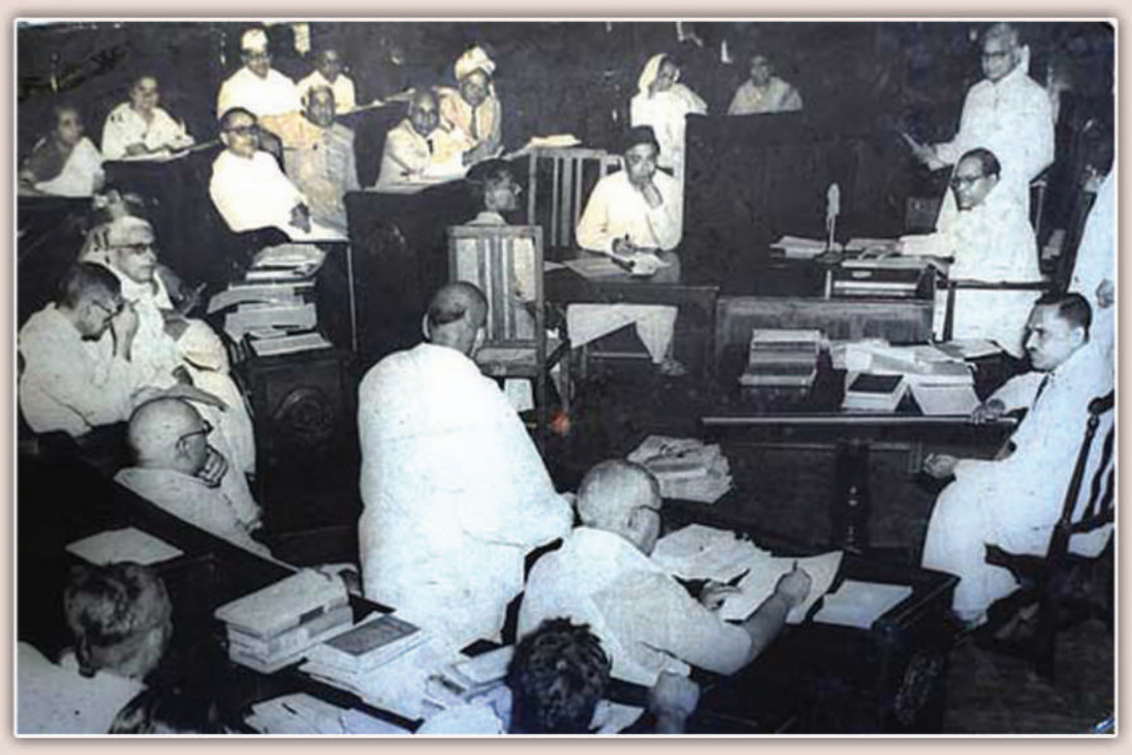

दलों के आंतरिक लोकतंत्र का. जब पार्टी के भीतर ही आंतरिक लोकतंत्र न हो, तो देश में किस तरह का लोकतंत्र होगा, इसकी सिर्फ़ कल्पना ही की जा सकती है.

इसके अलावा, आज हाईकमान की एक ऐसी थ्योरी राजनीति में आ चुकी है, जो आपको स्व-घोषित ईमानदार एवं पारदर्शी राष्ट्रीय पार्टियों में भी दिख जाएगी. राष्ट्रीय पार्टियों से अलग जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वहां भी सभी जगह क़रीब-क़रीब पार्टी से बड़ा एक व्यक्ति ही है. जद (यू) के अध्यक्ष भले ही शरद यादव हों, लेकिन जलवा, जादू और आदेश नीतीश कुमार का ही चलता है. जद (यू) के लोगों के लिए नायक नीतीश कुमार ही हैं. या फिर चाहे राजद हो, सपा हो, दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां हों, सबका एक ही हाल है. दिलचस्प रूप से बसपा, जो डॉ. अंबेडकर की नीति पर राजनीति करने की बात करती है, वहां भी नायक पूजा का क्या हाल है और इस वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या हाल है, इसे सब जानते हैं. किसी राज्य की जनता अमुक नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और वह चुनाव भी जीत जाता है, लेकिन पार्टी हाईकमान दिल्ली में बैठे-बैठे ही एक ऐसे मुख्यमंत्री की घोषणा कर देता है, जो सालों से अपने गृह-राज्य में गया भी न हो या जिसने चुनाव भी न लड़ा हो. लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के मुताबिक जनता अपना

अब जरा इस चेतावनी को आज के हालात से जोड़कर देखें, तो क्या लगता है? आज इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके अस्तित्व का आधार क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा. अपनी डफली-अपना राग. एक ही उद्देश्य. किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हो जाएं. कुकुरमुत्तों की तरह उग आए राजनीतिक दलों का एजेंडा भी अजीब है. कोई मुंबई से बिहारियों को भगाना चाहता है. किसी को हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से ऐतराज है. किसी को हर ग़रीब नक्सली नज़र आता है. कुछ दल ऐसे हैं, जो केंद्र सरकार से खुल्लमखुल्ला सौदेबाजी करते दिखते हैं. समर्थन के एवज में विशेष पैकेज की मांग! लेकिन इस सबके बीच जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, इसका ख्याल किसी को नहीं है. जाहिर है, डॉ. अंबेडकर ने जैसी आशंकाएं जताई थीं कि जैसे ही राजनीतिक दल अपने मत को देश के ऊपर लादेंगे, वैसे ही हमारी स्वतंत्रता ख़तरे में पड़ जाएगी, आज ठीक वैसा ही हो रहा है. सरकार की नीतियां जनाकांक्षाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि कॉरपोरेट हाउसेज और विदेशी कंपनियों के हितों के हिसाब से बन रही हैं. रिटेल में एफडीआई इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है. रिटेल में एफडीआई आने से लाखों लोगों के रोज़गार का क्या होगा, इसकी चिंता क्या सरकार में शामिल किसी राजनीतिक दल ने की? क्या आज ऐसा नहीं लगता कि सारे राजनीतिक दलों ने अपना-अपना मत देश के ऊपर लाद दिया है? बिल्कुल, आज यही हो रहा है. राजनीतिक दलों के मत के आगे जनता का मत मूल्यहीन हो चुका है. तो क्या ऐसे में, हमें डॉ. अंबेडकर की उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस सबसे हमारी स्वतंत्रता ख़तरे में पड़ सकती है?

डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए कहा था, सामाजिक स्तर पर हमारे पास भारत में असमानता के सिद्धांत पर आधारित एक समाज है, जिसका अर्थ है, कुछ के लिए विकास और कुछ का क्षरण. आर्थिक दृष्टि से, हमारे पास एक ऐसा समाज है, जहां कुछ लोगों के पास बहुत धन है, वहीं कुछ लोग घोर ग़रीबी में रहने को विवश हैं. 26 जनवरी, 1950 को एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाकर, भारत एक आदमी-एक वोट और एक वोट-एक मूल्य के सिद्धांत को सही ठहराएगा. हालांकि, कब तक हम एक व्यक्ति-एक मूल्य का सिद्धांत खारिज करते हुए चल सकेंगे? कब तक हम सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता से इंकार करते रहेंगे? अगर हम लंबे समय के लिए इंकार करते रहे, तो ऐसा हम सिर्फ़ अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ख़तरे में डालकर ही करेंगे. जल्द से जल्द संभव समय में इस विरोधाभास को दूर करना होगा, अन्यथा जो इस असमानता से पीड़ित है, वह उस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ख़त्म कर देगा, जिसे इस असेंबली (संविधान सभा) ने इतनी मुश्किल से बनाया है.

अब सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान में एक आम आदमी का मूल्य क्या है? मूल्य से अर्थ यह है कि एक आम आदमी की व्यक्ति होने की गरिमा क्या है? उस मानवीय गरिमा का क्या मूल्य है? इस संदर्भ में प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में लोग भूख यानी अन्न की कमी से नहीं मरते, क्योंकि देश में अन्न तो इतना है, जिसे रखने के लिए गोदामों में जगह तक नहीं है. सेन बताते हैं कि लोग इसलिए भूख से मरते हैं, क्योंकि जन वितरण प्रणाली के तहत अन्न को इन लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जिन अफसरों पर है, वे इन्हें आदमी (मानव) समझते ही नहीं. यानी नौकरशाहों की नज़र में इनकी मानव होने और मानवीय गरिमा का अर्थ ही ख़त्म हो चुका है. अन्यथा ऐसी कोई वजह नहीं है कि एक ओर देश के गोदामों में अन्न सड़ता रहे और दूसरी तरफ़ लोग भूख से मरते रहें. डॉ. अंबेडकर ने जो सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर असमानता की बात कही और चेतावनी दी कि एक दिन असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्या आज वह चेतावनी सही साबित होती नहीं दिखती? अभी छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ (नक्सली हमला), वह क्या था? वे क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? हो सकता है कि उन्हें कहीं बाहर से समर्थन मिलता हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें क्यों हाथ में बंदूक थामनी पड़ी? क्या कभी इस सवाल पर ईमानदारी से सोचने और विचार करने की ज़रूरत महसूस की गई?

बहरहाल, बिना किसी भक्ति या नायक पूजा के, यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉ. अंबेडकर ने आज से 64 साल पहले जो आशंकाएं जाहिर की थीं, वे आज अक्षरश: सही साबित हो रही हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 64 सालों में जितनी भी सरकारें आईं, सभी ने इन आशंकाओं को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे काम किए, जिनसे कि आज ये आशंकाएं सच साबित हो रही हैं. शायद बहुत देर हो चुकी है या फिर अब भी वक्त बाकी है? इस पर फ़ैसला आप सब ही करें. ■

**अब सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान में एक आम आदमी का मूल्य क्या है? मूल्य से अर्थ यह है कि एक आम आदमी की व्यक्ति होने की गरिमा क्या है? उस मानवीय गरिमा का क्या मूल्य है? इस संदर्भ में प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में लोग भूख यानी अन्न की कमी से नहीं मरते, क्योंकि देश में अन्न तो इतना है, जिसे रखने के लिए गोदामों में जगह तक नहीं है. सेन बताते हैं कि लोग इसलिए भूख से मरते हैं, क्योंकि जन वितरण प्रणाली के तहत अन्न को इन लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जिन अफसरों पर है, वे इन्हें आदमी (मानव) समझते ही नहीं.**

ग्रामीण उद्योगों को भी उचित ऋण मिलने लगेगा. दूसरे शब्दों में, गांवों की लक्ष्मी गांवों में ही रहे, तो कृषि सुधार और उद्योगों द्वारा ग्रामीण बुद्धि का विकास होगा.

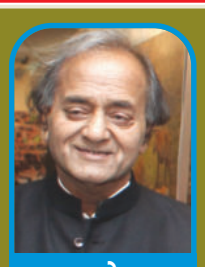

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

# क्षेत्रीय दल पहल कर सकते हैं

**उपचुनावों के ताजा परिणामों को लेकर चर्चा तेज है कि फलां शख्स की व्यक्तिगत जीत हुई और फलां शख्स की व्यक्तिगत हार. क्या वास्तव में यह सच है? इसी विषय पर पेश है यह विश्लेषणात्मक टिप्पणी.**

कुछ राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं और सभी उनका अपने-अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं. चुनाव परिणाम अख़बारों की सुर्खियां बने. किसकी हार और किसकी जीत हुई, इस पर बहस हुई. कहा गया कि यह मोदी के लिए एक बड़ी जीत है गुजरात में, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था. दूसरी ओर यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? उपचुनाव से पहले भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का ही इस सीट (महाराजगंज) पर कब्जा था. राजद ने फिर से यह सीट जीत ली. महराजगंज ठाकुरों के प्रभुत्व वाला निर्वाचन क्षेत्र है. प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के उम्मीदवार होने से पहले भी सांसद रह चुके थे और उन्होंने यह सीट जीती. अब इसमें क्या खास है, यह मुझे समझ में नहीं आता.

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे विभिन्न राज्यों की कई पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी नहीं हैं. वे अपने स्वयं के उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुनती हैं. कम से कम चार या पांच क्षेत्रीय पार्टियां यह तय करेंगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा? हां, नीतीश कुमार अभी एनडीए का हिस्सा हैं और अगर नरेंद्र मोदी को आगे करने की कोशिश की जाती है, तो वह एनडीए छोड़ देंगे और इसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा. दूसरी ओर, भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, 1999 को छोड़कर, कभी

भी पीएम पद को अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है. उसकी रणनीति यही होगी कि इस सबका फ़ैसला चुनाव परिणाम आने के बाद हो. प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा ने यही नीति अपनाई है. अगर भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फ़ैसला नहीं करती है, तो एनडीए जैसा है, वैसा ही रहेगा.

आज जो हालत है, जिस तरह से घोटाले सामने निकल कर आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन करने के अपने सभी नैतिक अधिकार खो दिए हैं. आज औसत मतदाता कांग्रेस पार्टी से निराश है. हालांकि भाजपा अपने आंतरिक क्लेश की वजह से इस स्थिति का फ़ायदा उठा पाने में अक्षम साबित हुई है. आडवाणी की तरह निर्विवाद नेता को अगर भाजपा आगे करती है, तो शायद सत्ता में आने की भी गुंजाइश बनेगी. इसलिए मोदी को सही समय का इंतज़ार करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है और भाजपा मोदी को आगे करती है, तो इसका लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा. अब समय आ गया है कि कांग्रेस के अलावा, अन्य सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक साथ आएं, मिलकर बैठें, एक रणनीति बनाएं और यह निश्चित करें कि वे एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन चाहती हैं या फिर राजग के साथ जाकर सरकार बनाना पसंद करेंगी?

इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, जयललिता, नवीन पटनायक एवं मायावती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है और न ही इस मामले में प्रारंभिक चर्चा के लिए वे बैठक कर रहे हैं. वैसे, एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव जीतने नहीं जा रही है, जो अक्टूबर–नवंबर 2013 या मई 2014 में होना है. अगर मई 2014 में चुनाव होता है, तब तो समय है, लेकिन अगर यह समय पूर्व होता है, तब वक्त बहुत कम है.■

feedback@chauthiduniya.com

# सरकार को पैसा कौन देता है

ठाकुरदास बंग

feedback@chauthiduniya.com

आख़िर सरकार भी पैसा कहां से लाती है? जनता से ही करों द्वारा यह रकम आती है न! करों द्वारा रकम वसूल करके उसे राजधानी तक पहुंचाने और उसे फिर से गांव-गांव कल्याणकारी कामों में ख़र्च करने यानी इस व्यवस्था में करों की क़रीब आधी रकम ख़र्च हो जाती है. इसके अलावा इसमें से भ्रष्टाचार में न जाने कितनी रकम चली जाती है. यह पैसा जनता के पास ही रखा जाए. किसानों को अपने माल के वाजिब दाम मिलने पर पैसा गांवों में ही रहने लगेगा. तब फिर क्या ग्रामवासी अपनी शाला, औषधालय, सड़क, तालाब आदि अपने पैसों से नहीं बना सकेंगे? इस व्यवस्था में किसान न केवल क़र्ज़मुक्त हो जाएगा, बल्कि चिंतामुक्त भी हो जाएगा. इन सब कामों के अलावा, यदि गांवों में इस मूल्य-नीति और कर-नीति के कारण पर्याप्त पैसा रहा, तो गांव में मध्यम या उचित तकनीकी का अवलंबन करके कृषि में सुधार होगा, ग्रामीण प्रक्रिया-उद्योग पनपेंगे, इन उद्योगों के औजारों में यथोचित सुधार होगा और ग्रामीणों को पूरा काम मिलेगा. कृषि प्रथम बार लाभकारी उद्योग बनेगी एवं मज़दूर को वाजिब मज़दूरी मिलेगी. खेती से संबंधित उद्योग भी गांवों में शुरू होंगे और पनपेंगे. कृषि-माल-संग्रह की व्यवस्था होगी, जिससे कि वाजिब क़ीमत मिलने पर ही उसे बेचा जा सके. उसी तरह कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को भी उचित ऋण मिलने लगेगा. दूसरे शब्दों में, गांवों की लक्ष्मी गांवों में ही रहे, तो कृषि सुधार और उद्योगों द्वारा ग्रामीण बुद्धि का विकास होगा. इससे न केवल गांव वाले काम-धंधे के लिए नगरों में जाना बंद करेंगे, बल्कि काम-धंधे के लिए नगरों से गांव की ओर बुद्धिमान लोग लौटेंगे, यानी गांव की सरस्वती गांव में ही रहेगी. इससे ग्रामवासियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, निराशा हटेगी और गांव खुशहाल होंगे. इस प्रकार गांवों का बल बढ़ा, तो नगरवासियों का भी बल बढ़ेगा. खुशहाल गांव में नगरों में निर्मित वस्तुओं के लिए स्थिर और व्यापक मांग पैदा होगी. घड़ी, अख़बार, साहित्य, ट्रांजिस्टर आदि नगरों में बनने वाली विविध वस्तुओं की मांग के कारण नगरों के कल-कारखाने और व्यापार चलने लगेंगे.

**आज देश में अंतर्विरोध की कई रेखाएं हैं. जैसे कि गांव में किसान मज़दूर का शोषण करता है, बड़ा छोटे का शोषण करता है, नगरों में मालिक मज़दूर का शोषण करता है, कई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार द्वारा सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं और केंद्रित अर्थ-नीति के कारण आज के नगर गांवों का शोषण कर रहे हैं. इन सबमें सबसे बड़ा अंतर्विरोध कौन सा है?**

इसलिए गांव और नगर, दोनों की भलाई की दृष्टि से कच्चे माल एवं अनाज को वाजिब दाम, यानी लागत-खर्च पर कितना मूल्य मिलना चाहिए?

आज देश में अंतर्विरोध की कई रेखाएं हैं. जैसे कि गांव में किसान मज़दूर का शोषण करता है, बड़ा छोटे का शोषण करता है, नगरों में मालिक मज़दूर का शोषण करता है, कई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार द्वारा सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं और केंद्रित अर्थ-नीति के कारण आज के नगर गांवों का शोषण कर रहे हैं. इन सबमें सबसे बड़ा अंतर्विरोध कौन सा है? आज नगराधिष्ठित केंद्रित अर्थ-व्यवस्था एवं उसकी सहायक केंद्रित राज्य व्यवस्था गांव के किसान, मज़दूर, कारीगर का जो शोषण कर रही है, उसकी मात्रा बहुत अधिक है. इस तुलना में गांव के अंदर ही अंदर चलने वाला शोषण कम है. शहरों में जो ग़रीब लोग हैं, वे सब दरअसल इस पीढ़ी में या फिर पिछले 50-100 वर्षों में गांवों से नगरों की ओर गए ग्रामीण भाई-बहन ही हैं. दूसरे शब्दों में, गांव से निर्यात की हुई जनता, यानी शहर के ये ग़रीब हैं. इसलिए नगरों द्वारा गांवों के होने वाले शोषण की रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा बन जाती है. यदि हम गांव में चलने वाले शोषण, यानी किसान के विरुद्ध मज़दूर का मुद्दा लें, तो मज़दूरों की संख्या 20-25 प्रतिशत है और इतने लोगों का ही समावेश इस आंदोलन में होगा. यदि हम शहर के अंदर चलने वाले शोषण का मुद्दा लेते हैं, तो भारत के 80 प्रतिशत ग्रामवासी अछूते रहेंगे. इसलिए रणनीति की दृष्टि से भी ग्रामीण उपज के वाजिब दाम का मुद्दा, यानी केंद्रित अर्थ-रचना द्वारा गांवों का शोषण का मुद्दा लेने से सबसे ज़्यादा लोगों का समावेश ऐसे आंदोलन में हो सकता है. दरअसल, सभी शोषकों से लड़ाई लड़नी है, लेकिन सभी को एक साथ दुश्मन बनाना उचित नहीं है. इसलिए आज के शोषण का सबसे बड़ा कारण, यानी गांवों का शोषण इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है. आज की भारत की ग़रीबी जिस शोषण से पैदा हुई है, उस अंतर्विरोध की रेखा इंडिया और भारत के बीच में है.

उपज के लागत-खर्च जितना वाजिब दाम मिलने से सब कुछ संभव हो जाएगा और गांव के सारे दु:ख-दर्द मिट जाएंगे, यह कोई नहीं मानता, लेकिन इसके बिना भी कोई प्रमुख आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ नहीं हो सकेगा. खेती घाटे में रहेगी, तो सिंचाई से घाटा कम नहीं होगा और कोई भी सुधार करने से मूल रोग नहीं मिटेगा. मान लीजिए, खून खराब हो जाने से शरीर पर तरह-तरह के फोड़े हो रहे हों. ऐसे में, हम इस या उस फोड़े पर मरहम भले ही लगाएं, लेकिन जब तक खून शुद्ध नहीं होगा, तब तक फोड़े-फुंसी मिटेंगे नहीं. एक फोड़ा मिटा, तो दूसरी जगह दूसरा होता है. इसलिए वाजिब दाम मिलना ही ग्राम-सुधार का प्रारंभिक कार्यक्रम है. यह एक ऐसी मुख्य चाबी है, जिससे अन्य ताले खुलने में सहायता मिलेगी और इसके हाथ आए बिना कोई ताला खुलेगा ही नहीं. वाजिब दाम मिलने पर सिंचाई, चकबंदी, कुशलता-वृद्धि आदि कई काम कृषि-सुधार के लिए करने होंगे. साथ ही साथ ग्रामोद्योग, शराब-बंदी, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक सुधार, राष्ट्र की एकरसता इत्यादि विविध आवश्यक कार्यक्रम भी चलाने होंगे. वाजिब दाम मिलने से लोगों में ऐसे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए उत्साह पैदा होगा, क्योंकि बुनियादी रोग तो नष्ट हो गया! इससे गांव एवं शहर के बीच का अंतर घटेगा, यानी आर्थिक विषमता कम होगी. इस प्रकार समूचा भारत बलवान और एकरस बनेगा. ■

## पाठकों की दुनिया

### काश! सभी संपादक भारतीय होते

चौथी दुनिया पढ़ने से मैं अपने आपको रोक नहीं सकता. खासकर, संतोष भारतीय का स्तंभ-जब तोप मुकाबिल हो, मेरी चिंतन शक्ति को आंदोलित कर देता है. मेघनाथ देसाई एवं कमल मोरारका की समीक्षात्मक टिप्पणियां पत्रकारिता जगत में एक मिसाल हैं. संतोष भारतीय देश की जनता पर बहुत भरोसा करते हैं, परंतु देश जागता तब है, जब सब कुछ लुट जाता है. मुझे भय सता रहा है कि संतोष भारतीय एवं उनके सहयोगियों ने देश के मीडिया, संसद, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, रक्षा सौदे में घोटाले एवं पूंजीपतियों के काले कारनामों पर अपनी कलम का कमाल चौथी दुनिया के माध्यम से दिखाया है. कहीं ऐसे राजनीतिज्ञों का शिकार न बन जाएं, क्योंकि संपादकों-पत्रकारों पर हमले आम बात हैं. अंबानी धनपत हैं और वह धन के बल पर देश की राजनीति अपने पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं. सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है, क्योंकि हमारा संसद भवन अब पूंजीपतियों के कब्जे में है. लेकिन संतोष जी, आपकी रक्षा कौन करेगा? बिहार में भी एक धनपत को कारबाइन वाला सुरक्षाकर्मी दिया गया था. नशे में धुत्त उक्त धनपत एक शादी समारोह में अपने सुरक्षाकर्मी की कारबाइन छीनकर फायर करना चाहते थे. जब सुरक्षाकर्मी ने विरोध किया, तो उन्होंने उसे चाकू मारकर जख्मी कर दिया. फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

वर्तमान में हर राजनीतिज्ञ दुर्योधन के साथ बगल में एक भीष्म पितामह भी होते हैं, परंतु पता नहीं, महाभारत का अंतिम परिणाम देखने के लिए वे दुर्योधन के साथ मंच पर क्यों बैठे रहते हैं? दरअसल, इसके पीछे एक तरफ़ उनकी वोट बैंक की लाचारी है और दूसरी तरफ़ सांसद या विधायक पद के प्रति मोह. यही वजह है कि उनका स्वच्छ चरित्र मंच पर बैठते ही मैला हो जाता है. इसलिए भारतीय जी, चौथी दुनिया के सपनों को साकार रूप देने के लिए कुर्बानी देनी होगी और जनता के बीच आना ही होगा. वैशाली ज़िले का बिठौली गांव कभी बिहार के ईमानदार राजनीतिज्ञ स्वर्गीय दीप बाबू की कर्मभूमि था. वैशाली ज़िले को जन का प्रतिपालक एवं प्रजातंत्र की माता जैसे विशेषण से नवाजा गया है. इस भूमि पर मैं चौथी दुनिया के चिंतकों को आमंत्रित करना चाहता हूं. यह लोक जागरण की मंशा है, नेतागीरी नहीं.

*-चंद्रिका प्रसाद सिंह, बिठौली, वैशाली, बिहार.*

### बलात्कारियों को कठोर सजा मिले

कहने को तो हमारे देश में महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन अब सब बातें कहने भर की रह गई हैं. दरअसल, आज महिलाएं पुरुषों के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गई हैं, जिनके शरीर से जब जो चाहे, खेल और फिर उसे फेंक सकता है. दरअसल, वे घर और बाहर, दोनों जगहों की ज़िम्मेदारी निभाने में पुरुषों से कहीं अधिक सक्षम हैं. फिर भी उन्हें समाज में पुरुषों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता. आज पांच साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है. सवाल यह है कि क्या अब बच्चियां घर से बाहर निकलना भी छोड़ दें? तो फिर कैसे संवरेगा उनका भविष्य? इसके लिए जितना ज़िम्मेदार बलात्कारी है, उससे कहीं ज़्यादा प्रशासन और सरकार है. एक पिता के दिल का टुकड़ा होती है उसकी बेटी, लेकिन उस बेटी के साथ हुई हैवानियत के बदले सरकार उस बेबस बाप को मुआवजे के रूप में कागज के चंद टुकड़े देकर अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है. लेकिन क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि अब तक जितने भी लोग बलात्कार के दोषी पाए गए हैं, उनके किए का हम सही-सही हिसाब करें और उन्हें कठोर से कठोर सजा दें?

*-शिक्षा पाटनी, झुमरी तिलैया, झारखंड.*

### फिक्सिंग पर रोक लगे

क्रिकेट इन दिनों एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा माध्यम बन गया है. हर कोई अपने आपको क्रिकेट के साथ जोड़े रखता है. भारत में आज क्रिकेट हर तरह से न केवल अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं में जा बसा है. सच तो यह है कि आज युवा वर्ग क्रिकेट खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानता है. दरअसल, कामयाब होने का हौसला और जज्बा कहीं से भी मिल सकता है, भले ही वह क्रिकेट ही क्यों न हो. लेकिन, दु:खद यह है कि क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी पैसों की चकाचौंध में अंधे हो रहे हैं. इसका नतीजा स्पॉट फिक्सिंग के रूप में दिख रहा है और रोल मॉडल कहे जाने वाले खिलाड़ी क्रिकेट के साथ देश का नाम भी खराब कर रहे हैं. ऐसे में, जितनी खेल की छवि बिगड़ती है, उतना ही प्रशंसकों को भी ठेस पहुंचती है. हम सब यह जानते हैं कि क्रिकेट और उससे जुड़ी गतिविधियों से खिलाड़ियों को अच्छी-खासी रकम मिलती है, तो फिर आख़िर फिक्सिंग के लालच में क्यों पड़ना? भविष्य में ऐसी गतिविधियां न हो पाएं, इसके लिए खेल संगठनों और सरकार को कड़े क़दम उठाने चाहिए.

*-विकास कुमार, झुमरी तिलैया, झारखंड.*

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

प्रारूप समिति 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी. प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त को हुई.

संतोष भारतीय

## जब तोप मुक़ाबिल हो

# राजनीति में संवादहीनता

राजनीति का दस्तूर भी अजीब है. दोस्त कब दुश्मन हो जाए, पता ही नहीं चलता और यही फ़र्क़ राजनीति के दुश्मनी में बदलती दोस्ती की तस्वीर के रूप में दिखाई देता है. राजनेता पहले भी थे और राजनेता आज भी हैं. आपको कुछ घटनाएं पहले के राजनेताओं से जुड़ी बताते हैं.

रफी अहमद किदवई और पंडित गोविंद वल्लभ पंत में बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी. नेहरू जी इस बात से परिचित थे, लेकिन जब कभी अकेले रफी अहमद किदवई या गोविंद वल्लभ पंत पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिलते थे, तो उनसे यही कहते थे कि मेरी राय यह है, लेकिन उनकी राय ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि वह शायद इस मसले पर ज़्यादा सही सलाह आपको दे सकते हैं. यह बड़प्पन रफी अहमद किदवई और पंडित गोविंद वल्लभ पंत का था. आपस में, चाहे वे कैबिनेट की बैठकें हों या पार्टी की मीटिंग, दोनों में वाकयुद्ध होता था, पर फ़ैसले के समय दोनों एक-दूसरे की राय का सम्मान करने की बात पंडित जवाहर लाल नेहरू से करते थे. दूसरा मशहूर उदाहरण आचार्य नरेंद्र देव का है. आचार्य जी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी, लेकिन पार्टी का संविधान और घोषणा-पत्र लिखने में देरी हो रही थी. कारण, आचार्य नरेंद्र देव काफी बीमार थे. उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं अपने मित्र पंडित संपूर्णानंद जी को संदेश भेजा कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का संविधान और घोषणा-पत्र लिख दें. पंडित संपूर्णानंद ने प्राथमिकता के आधार पर लगभग सात या बारह दिन लगाकर संविधान और घोषणा-पत्र लिखा और उसे आचार्य नरेंद्र देव जी के पास फैजाबाद भेज दिया. जब आचार्य जी के पास पंडित संपूर्णानंद जी की हस्तलिखित प्रति पहुंची, तो उन्होंने उसे सीधे प्रेस में छपने के लिए भेज दिया. आचार्य जी के साथियों ने कहा कि आचार्य जी, संपूर्णानंद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं. आपने उन्हें संविधान और घोषणा-पत्र सोशलिस्ट पार्टी का लिखने को कहा है. एक बार देख तो लीजिए कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें तो नहीं डाल दी हैं, जो आप नहीं चाहते हैं! आचार्य जी का जवाब था कि जब संपूर्णानंद जी ने लिखा है, तो सही ही लिखा होगा और उन्होंने बिना कॉमा, फुलस्टॉप बदले, छपने की अनुमति दे दी. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का संविधान और घोषणा-पत्र आज भी राजनीतिक दलों के लिए पढ़ने योग्य सामग्री है, क्योंकि उसमें रंचमात्र भी बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं. इसीलिए आज भी वह एक आदर्श संविधान और एक आदर्श घोषणा-पत्र के रूप में जाना जाता है.

तीसरा उदाहरण श्री चंद्रभानु गुप्ता का है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग उनके ख़िलाफ़ 10 हज़ार की संख्या में प्रदर्शन करने गए. उनका नारा था, गली-गली में शोर है, सीवी गुप्ता चोर है. दिन भर उन्होंने नारे लगाए. अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के पास पैसे नहीं थे. चंद्रशेखर जी उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे. वह अपने एक-दो साथियों के साथ चंद्रभानु गुप्ता से मिलने चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने के लिए कुछ पैसों के इंतजाम के लिए वह चंद्रभानु गुप्ता से कहें. जब ये लोग मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता से मिलने गए, तो उन्होंने इनसे कहा, आ जाओ फक्कड़ों, भूखों, क्या बात है? इन लोगों ने कहा कि गुप्ता जी, कार्यकर्ताओं को...बस, इतना ही बोला था. उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैंने 10 हज़ार लोगों के खाने के लिए इंतजाम करा दिया है, पूड़ी-सब्जी बन रही है. गेंदा सिंह जी उस समय चंद्रशेखर जी के साथ थे. चंद्रभानु जी ने कहा, गेंदा सिंह वहां चले जाओ, पूड़ी-सब्जी बन रही है, 10 हज़ार लोगों के लिए. उनके खाने के लिए ले आओ. यह था उस समय के राजनेताओं का बड़प्पन. जिस नेता को दिन भर गली-गली में शोर है, सीवी गुप्ता चोर है, की गाली सुननी पड़ी हो, उन गाली देने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी उन्होंने ही की. उस दौर के राजनेताओं में यही खास बात थी. वे अपने कार्यकर्ताओं का काम बाद में करते थे, लेकिन विपक्ष के लोगों का काम पहले करते थे. विपक्ष के लोगों से मिलकर समस्याएं पहले जानते थे और साथ ही अपनी पार्टी के लोगों को धैर्य रखने की सलाह देते थे.

यह दौर, ऐसा लगता है कि अब समाप्त हो गया है. प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हमें देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में दुआ-सलाम तक नहीं हुई. छोटी सी जगह पर आमना-सामना हुआ, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे को देखा भी नहीं. इस घटना के संकेत ये हैं कि राजनेताओं के मन की दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार निभाने के मामले में वे अपने साधारण कार्यकर्ताओं से भी कमतर नज़र आते हैं. अभी भी ज़िलों या प्रदेश में दो पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता मिलते हैं, तो वे आपस में राजनीति के अलावा, बहुत सारी बातचीत कर लेते हैं और कभी-कभी तो राजनीति की बात भी कर लेते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नेताओं में यह व्यवहार अब देखने को नहीं मिलता.

चंद्रशेखर जी संभवत: इस दौर के आख़िरी व्यक्ति थे, जिनके यहां हर पार्टी के लोग मिलने चले जाते थे और चंद्रशेखर जी भी जब कोई समारोह करते थे, तो वह हर पार्टी या हर विचारधारा के नेताओं को आमंत्रित ज़रूर करते थे. वहां जिस तरह का सौहार्द्र, सहिष्णुता और संवाद लोगों में देखने को मिलता था, उससे राजनीति की जमी हुई बर्फ दरक जाती थी. चंद्रशेखर जी के बाद इस काम को भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं किया. राज्यों में तो यह हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां तो वही हो रहा है, जो वे दिल्ली में होता हुआ देखते हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में नहीं मिलते. कांग्रेस के नेता भी आपस में मन में दुराव रखकर मिलते हैं और जब वे एक-दूसरे से मिलते हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं, तुझे कैसे उठा के ज़मीन पर पटकूं, का भाव रहता है. जब वे मिलकर बाहर निकलते हैं, तब उनकी प्रतिक्रिया और उनके शब्द बताते हैं कि जितनी देर उन्होंने बात की, दूसरे की बात सुनी ही नहीं, बल्कि अपने मन में यह सोचा कि इसकी राजनीतिक हत्या कैसे की जाए!

संसद का सेंट्रल हॉल एक बहुत बड़ा आईना है. संसद के सेंट्रल हॉल में जब भी देखा जाता है, तो एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर बैठे नज़र नहीं आते. हरेक का अपना-अपना दायरा होता है. लालू यादव के साथ आरजेडी के मौजूदा या भूतपूर्व सांसद बैठे दिखाई देते हैं. शरद यादव के साथ उनके दल के लोग दिखाई देते हैं. कांग्रेस के बड़े नेता वहां बैठते नहीं, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अहमद पटेल, कभी-कभी जब जाते हैं, तब उनके पास कांग्रेस के सांसदों की भीड़ होती है. सांसद भी जहां बैठते हैं, एक ही पार्टी के बैठते हैं. दक्षिण भारत के सांसद अलग बैठते हैं, उनका कोई संवाद उत्तर भारत के लोगों के साथ नहीं होता. पहली बार, एक महीने पहले सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी 15 मिनट के लिए बैठे थे, तो उनके पास कांग्रेस के सांसदों की भीड़ लग गई और जो दूर थे, वे वहीं से अपना चेहरा उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे थे. और जैसा कि राहुल गांधी का स्वभाव है, वह 90 प्रतिशत लोगों को न तो चेहरे से जानते हैं और न ही नाम से, पर वह इस क्रिया को उत्सुकता से देख ज़रूर रहे थे कि लोग कैसे उन्हें अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं. भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी एवं सुषमा स्वराज के नाम शामिल हैं, भी सेंट्रल हॉल में नहीं बैठते. हां, कभी-कभी अरुण जेटली ज़रूर बैठते हैं, पर अरुण जेटली हों या फिर शरद पवार, उनके आस-पास भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के सदस्यों की जगह पत्रकार ही ज़्यादा होते हैं.

यह दृश्य भारतीय राजनीति की विकृति का दृश्य है. हमारा मानना है कि अगर विभिन्न पार्टी के नेताओं के बीच एक चाय की प्याली पर भी बात होती रहे और यदि लोकसभा या राज्यसभा की बर्फ फिर भी न पिघले, लेकिन कोमल या मुलायम ज़रूर होगी. अफसोस! अब इसके लिए कोशिश करने वाले राजनेता ही नहीं बचे. अटल जी आख़िरी प्रधानमंत्री थे, जिनसे हर पार्टी का सांसद राजनीतिक धरातल पर भी मिलने की कोशिश करता था और अटल जी भी उसे देखकर जिस तरह मुस्करा कर संदेश देते थे, वह राजनीतिक अंतरंगता का बोध कराता था. पर मौजूदा प्रधानमंत्री ने तो इतिहास ही रच दिया. अपना पूरा समय राज्यसभा का सदस्य रहते हुए काट दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं की और एक भी दिन सेंट्रल हॉल में नहीं बैठे. अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है और अब तो हालत यह है कि उन सांसदों ने भी पीएम से मिलना छोड़ दिया. सोनिया गांधी भी सेंट्रल हॉल में नहीं बैठतीं, जहां कम से कम सांसद उन्हें अपना चेहरा तो दिखा सकें. सेंट्रल हॉल के पीछे की तरफ़ एक रास्ता नुमा गैलरी है, उससे निकल कर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज एवं लालकृष्ण आडवाणी बिना दाएं या बाएं देखे, सीधे चलते चले जाते हैं. कुछ नेता तो उनमें ऐसे भी हैं, जिन्हें लोग दूर से देखकर नमस्कार करते हैं, लेकिन वे जवाब तक नहीं देते. जब यह हालत सेंट्रल हॉल की हो, तो यह अपेक्षा करना कि दो विचारधाराओं या दो विभिन्न पार्टियों के लोग आपस में चाय या ढोकला के बहाने बैठकर देश को लेकर बात करेंगे, असंभव लगता है. शायद भारतीय राजनीति की विडंबना यही है कि यहां संवाद समाप्त हो गया है. ■

editor@chauthiduniya.com

## संविधान में राजनीतिक दल का ज़िक्र नहीं है

# कब और कैसे बना हमारा संविधान

**इस अंक से हम डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए आख़िरी भाषण के अंश प्रकाशित कर रहे हैं. अपने इस ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब ने न सिर्फ़ भारतीय संविधान के बारे में बताया है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर भी गहराई से प्रकाश डाला है. बाबा साहब के इस भाषण का एक-एक शब्द आज के समय में प्रासंगिक है.**

डॉ. बी आर अंबेडकर

महाशय, 9 दिसंबर, 1946 की पहली बैठक के बाद हम लोगों को संविधान सभा पर काम करते हुए 2 वर्ष, 11 माह और 17 दिन हो जाएंगे. इस अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र बुलाए गए. 11 में से पहले 6 सत्र मूल अधिकार, संघ के संविधान, संघ की शक्ति, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति जैसे मुद्दों पर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने और उद्देश्यों को पारित कराने में बीत गए. 7, 8, 9, 10 और 11वें सत्र में प्रारूप संविधान पर विचार करने पर विशेष ध्यान दिया गया था. संविधान सभा के इन 11 सत्रों में कुल 165 दिनों का समय लगा. इसके अतिरिक्त संविधान के प्रारूप पर विचार करने में सभा को 114 दिनों का समय लगा.

प्रारूप समिति 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी. प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त को हुई. 30 अगस्त से अगले 141 दिनों तक यह समिति प्रारूप संविधान बनाने में व्यस्त रही. संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाया गया प्रारूप संविधान प्रारूप समिति के लिए एक ऐसा विषय था, जिस पर प्रारूप समिति को काम करना था. इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं. प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के लिए बनाए गए पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं. अंत में प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 386 कर दी गई, लेकिन जब प्रारूप संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं. प्रारूप संविधान जब सामने लाया गया, तो इसमें लगभग 7,635 संशोधन हुए थे, लेकिन वास्तव में इन संशोधनों में से 2,473 को ही लिया गया था.

मैं इन तथ्यों को इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि सभा ने इस कार्य को करने में न केवल बहुत अधिक समय लिया, बल्कि जनता का धन भी खर्च किया. मैं अन्य देशों की संविधान सभाओं के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जिनका उस देश के संविधान निर्माण के लिए गठन किया गया था. संविधान निर्माण के लिए अमेरिकी सभा की 25 मई, 1787 की बैठक के बाद चार महीने लगे और उसने अपना काम 17 सितंबर, 1787 को पूरा किया. कनाडा की संविधान सभा की बैठक 10 अक्टूबर, 1867 को हुई और संविधान क़ानून के रूप में सामने आया मार्च, 1867 में. इसमें कुल 2 साल और पांच महीने लगे. ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा का गठन मार्च, 1891 में हुआ और संविधान क़ानून के रूप में सामने आया 9 जुलाई, 1900 को. इसमें नौ साल लग गए. दक्षिण अफ्रीकी संविधान सभा का गठन 20 सितंबर, 1908 को हुआ और संविधान क़ानून के रूप में सामने आया 20 सितंबर, 1909 को. इसमें एक साल लगा. यह सत्य है कि हमने अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की संविधान सभा की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन इस सत्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि संविधान के निर्माण में हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभाओं से काफी कम समय लिया. संविधान निर्माण में समय की खपत की बात हो रही है, तो इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. पहली यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान से काफी छोटे हैं और दूसरी यह कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं. अमेरिका के संविधान के पहले 4 अनुच्छेद विभिन्न भागों में विभाजित हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 21 हो जाती है. कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 भाग हैं. एक और बात, जो इस मामले में ध्यान देने वाली है, वह यह कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में संशोधनों की समस्या नहीं है. उन्हें उसी रूप में पारित कर दिया गया है. दूसरी तरफ़ देखा जाए, तो हमारी संविधान सभा को 2,473 संशोधनों पर काम करना पड़ा. इन सारे तथ्यों को देखने के बाद संविधान सभा पर लगने वाले सारे आरोप निराधार हैं. संविधान सभा के लोगों को कम से कम समय में यह जटिल कार्य पूरा करने के लिए बधाई देनी चाहिए.

प्रारूप समिति द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता को बदलने के लिए श्री नजीरुद्दीन अहमद ने इसकी निंदा करना अपना कर्तव्य समझा. उनकी राय में प्रारूप समिति का कार्य निंदा योग्य भी नहीं है. प्रत्येक व्यक्ति को प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी राय देने का अधिकार है. ऐसे में श्री नजीरुद्दीन की राय का भी स्वागत है. श्री नजीरुद्दीन का मानना है कि वह प्रारूप समिति के किसी भी सदस्य से ज़्यादा योग्य हैं. अगर संविधान सभा उनको इसके योग्य मानकर उनको नियुक्त करती है, तो प्रारूप समिति श्री नजीरुद्दीन का स्वागत करना चाहेगी. अगर श्री नजीरुद्दीन का संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं था, तो इसमें निश्चित तौर पर प्रारूप समिति का कोई दोष नहीं है. हालांकि श्री नजीरुद्दीन ने कभी भी प्रारूप समिति की प्रशंसा नहीं की, लेकिन मैंने हमेशा उनकी बातों को प्रशंसा के रूप में लिया. ■

***(अगले अंक में संविधान सभा और प्रारूप समिति के सदस्यों से जुड़ीं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां)***

**भाग-एक**

feedback@chauthiduniya.com

प्रेग्नेंट वुमेन की प्रेग्नेंसी को रोचक बनाने के लिए डॉल्फिन की सहायता ली जा रही है, ताकि दुनिया की निगाहें इस ओर आकर्षित की जा सकें.



# जानने का हक, जीने का हक

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है, वह क्या, कहां और कैसे काम कर रही है. यही नहीं, हर व्यक्ति सरकार चलाने के लिए टैक्स देता है, इसलिए भी उन्हें यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहां और किस रूप में खर्च किया जा रहा है. जनता को यह जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है. 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया. अनुच्छेद 19 के अनुसार, हर व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं, तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती. 2005 में देश की संसद ने एक क़ानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि नागरिक किस प्रकार सरकार से सूचना मांगेंगे और सरकार किस प्रकार जवाबदेह होगी. सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को निम्न अधिकार देता है:–

- वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है या कोई भी सूचना ले सकता है.
- वह किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सकता है और उसकी जांच कर सकता है.
- वह किसी भी सरकारी काम की जांच कर सकता है या उसमें इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सकता है.

सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं गैर सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाएं आदि इसमें शामिल हैं. पूर्णत: निजी संस्थाएं इस क़ानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी क़ानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांगना चाहे, तो वह ऐसा कर सकता है (धारा–2 क एवं ज). हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं. ये वे अधिकारी हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उन्हें आवेदनकर्ता को उपलब्ध भी कराते हैं. लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह 30 दिनों के भीतर (कुछ मामलों में 45 दिन) सूचना उपलब्ध कराए. अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है, साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी. लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे (धारा 6–2). सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क देना होगा. केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क तय किया है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. बीपीएल कार्डधारकों द्वारा सूचना मांगने पर उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता (धारा 7–5). दस्तावेज़ों की प्रति लेने के लिए भी शुल्क देना होगा. केंद्र सरकार ने यह शुल्क 2 रुपये प्रति पृष्ठ तय किया है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. अगर सूचना तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो सूचना मुफ्त दी जाएगी (धारा 7–6).

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह न केवल उस आवेदन को पांच दिनों के भीतर संबंधित विभाग को भेजे, बल्कि आवेदक को भी सूचित करे. ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी (धारा 6–3). यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इंकार करता है अथवा परेशान करता है, तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक शुल्क मांगने के ख़िलाफ़ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं. लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है. जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, उनका विवरण सूचना अधिकार क़ानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है, तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है. जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं या दी गई सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है. यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे संबंधित हो) के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं. ■

**यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:**

**चौथी दुनिया**

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

## ज़रा हट के

### पॉपकार्न विक्रेता ने लिखा नॉवेल

रेहड़ी लगाने, मूंगफली या पॉपकार्न बेचने वाला कोई शख्स अगर एक ऐसी कहानी या नॉवेल लिख दे, जिसकी चर्चा सबकी जुबान पर हो, साथ ही उस पर फिल्म भी बन जाए, तो अचरज होगा ही. स्टुअर्ट गैलप सिनेमा थिएटर में पॉपकार्न बेचने और सफाई का काम करते थे. वह इस काम में पिछले 10 वर्षों से लगे हुए थे और यह काम करते हुए उन्होंने एक साइंस फिक्शन नॉवेल लिख डाला. स्टुअर्ट की लेखनी और रुचि की दाद देनी होगी कि

उन्होंने एक ऐसा नॉवेल लिख डाला, जो फिल्म वालों को काफी पसंद आया. फिल्म मेकर्स ने उनके नॉवेल पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया है. स्टुअर्ट का फिल्म लेखक बनने का सफर सचमुच अकल्पनीय है, पर इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की. वह शुरू से ही फिल्मों के शौकीन रहे और इसलिए उन्होंने अपने घर के पास स्थित थिएटर में ही काम ढूंढा, ताकि फिल्मों के टच में रह सकें. समय निकाल कर वह फिल्में देख लेते थे और इस तरह उनका काम चलता रहा. अब गैलप की फिल्म के लिए निर्देशक की तलाश की जा रही है. निर्देशक मिलते ही फिल्म शुरू हो जाएगी. मान गए गैलप!

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

### डॉल्फिन के साथ प्रसव

आप अक्सर लोगों को डॉल्फिन के साथ चहलकदमी करते या खेलते हुए समीप से या तस्वीरों में देखते होंगे. दरअसल, इसे भी इंसानों के साथ मजा आता है, जो कि इसके व्यवहार से पता चल जाता है. यदि यह पता चले कि प्रेग्नेंसी में भी यह आपकी साथी बन रही है, तो आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है. प्रेग्नेंट वुमेन की प्रेग्नेंसी को रोचक बनाने के लिए डॉल्फिन की सहायता ली जा रही है, ताकि दुनिया की निगाहें इस ओर आकर्षित की जा सकें. इस क्रम में एक दंपति ने हिम्मत भी दिखाई है और उन्होंने तय किया है कि वे अपने बच्चे को जन्म डॉल्फिन की उपस्थिति में देंगे. जरा सोचिए, डॉल्फिन के साथ पानी वाली जगह प्रसव

जैसा कितना कठिन कार्य है, लेकिन हवाई में होने जा रहा है यह अजूबा. जरा दंपति का रोमांच तो देखिए, वह हवाई पहले ही पहुंच गया है. प्रेग्नेंट वुमेन हीथर बेरिंगटन की उम्र 27 साल है, जो अपने पति की रजामंदी से यह करने जा रही हैं. ■

### कुत्तों के लिए होटल

आज तक सिर्फ़ आप ही आलीशान होटल या रेस्तरां में ठहरते होंगे, लेकिन अब आपके पेट्स के लिए भी यह सुविधा, यानी होटल उपलब्ध है, जहां वे सुकून के साथ सारे मजे ले सकते हैं. वेल्स में पेट्स के लिए बना यह आलीशान होटल अपने आप में अनोखा है. यहां आपके पालतू कुत्ते के लिए केवल भव्य कमरे ही नहीं, बल्कि स्वीमिंग पूल भी है. वेल्स के मेरथल टेडफिल स्थित द रॉयवान पेट होटल खुलने के साथ ही सुर्खियों में है. जनाब, यह कोई साधारण होटल नहीं, बल्कि एक फाइव स्टार होटल है. कई बार आपको सैर के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आप नहीं जा पाते, क्योंकि आप अपने पालतू कुत्ते को किसके भरोसे छोड़ कर जाएंगे, यह समझ में नहीं आता, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है. इस होटल में श्वानों के लिए 29 पाउंड प्रतिदिन किराए पर कमरा उपलब्ध है. होटल का परिसर काफी बड़ा है, ताकि मेहमानों को घूमने–फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिले. होटल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनके समकक्ष शख्सियतों के पालतू श्वानों के लिए खास कमरे भी हैं, जहां सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. अब बताइए, आप कब पधार रहे हैं इस होटल में अपने श्वानों के साथ. ■

### बालों का गिनीज बुक रिकॉर्ड

**एविन का कहना है कि उन्हें लंबे बालों के कारण कार में बैठने से लेकर कई जगह परेशानी होती है, लेकिन इसका कोई मलाल भी नहीं है.**

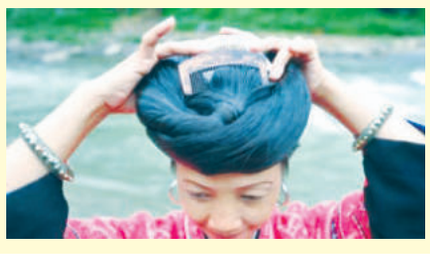

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को एड़ी–चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी जल्दी ऐसा संभव नहीं हो पाता. लेकिन एविन डुगास एक ऐसी महिला हैं, जिनके बालों की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. उनके बाल देखकर आपको लगेगा कि इनमें क्या खास बात है. खा गए न गच्चा! जनाब, अफ्रीकन लोगों के बाल सामान्य तौर पर इतने लंबे नहीं होते. उनके बाल घुंघराले एवं छोटे होते हैं और एविन के बाल 4 फुट की ऊंचाई तक बढ़ गए हैं और इसलिए वह चर्चित हो गई हैं. एविन का कहना है कि उन्हें लंबे बालों के कारण कार में बैठने से लेकर कई जगह परेशानी होती है, लेकिन इसका कोई मलाल भी नहीं है. उन्हें चिड़ियों से भी अपने बाल बचाकर चलना पड़ता है. एविन अपने घने बालों का एक फ़ायदा भी बताती हैं. वह कहती हैं कि मुझे नींद आने पर तकिए की ज़रूरत नहीं पड़ती. ■

## राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

**मेष** 21 मार्च से 20 अप्रैल

परिवारीजनों से स्नेह एवं सम्मान प्राप्त होगा. नौकरी–पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उन्नति का समाचार मिलेगा. व्यापारी अपने व्यवसाय में परिवर्तन के बारे में सोचेंगे. विद्यार्थी आगे की पढ़ाई को लेकर अपनी योजना में व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

**वृष** 21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह न चाहते हुए भी यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है. पारिवारिक दृष्टि से समय आपके अनुकूल रहेगा. व्यापारी लाभ हासिल करेंगे. कोई भी निवेश सोच–समझ कर करें. विद्यार्थी अध्ययन सुचारू रूप से करेंगे. संतान सुख अच्छा रहेगा. धार्मिक रुचि बढ़ेगी. अपने स्वास्थ्य की जांच ज़रूर करा लें.

**मिथुन** 21 मई से 20 जून

इस सप्ताह व्यस्तता की संभावनाएं प्रबल हैं. घर के लिए कोई नई वस्तु खरीदेंगे. आय बढ़ेगी और आप खुश रहेंगे. किसी के बहकावे में आकर कोई आर्थिक निर्णय न लें. विरोधियों का स्वर ऊंचा हो सकता है, आप जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें. रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे.

**कर्क** 21 जून से 20 जुलाई

विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें. व्यय में वृद्धि होगी. वाणी पर नियंत्रण रखकर ही कोई बात करें. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. किसी को उधार देने से पहले विचार अवश्य कर लें. बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

**सिंह** 21 जुलाई से 20 अगस्त

सुख–संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी. दिनचर्या में अनुशासन का ख्याल रखें, अन्यथा उसका कुप्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा. उधार दिया पैसा वापस मिलने में दिक्कत होगी. प्रशासन से सहयोग मिलेगा. संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी. अत्यधिक विश्वास में आकर कोई कार्य न करें.

**कन्या** 21 अगस्त से 20 सितंबर

पारिवारिक तनाव न बढ़ने दें. अनिश्चितता का वातावरण रहेगा, लेकिन विचलित न हों. थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा. सप्ताहांत में आमदनी बढ़ेगी. क़ानूनी मामलों में थोड़ा बचकर चलें. नौकरी–पेशा लोग कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहें. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे.

**तुला** 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

जनसंपर्क बढ़ेगा. व्यवसायियों की उलझनें बढ़ेंगी. नौकरी–पेशा लोगों को उन्नति के समाचार मिलेंगे. यात्रा में कष्ट का सामना करना पड़ेगा. मनोबल ऊंचा बनाकर चलें, उससे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे. वाहन सावधानी से चलाएं. विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है.

**वृश्चिक** 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी. व्यापारियों का ज़्यादातर समय अपने व्यापार के लिए रणनीति बनाने में गुजरेगा. उत्साह और प्रतिभा के बल पर सफलता मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. विदेश संबंधी कोई अच्छा समाचार मिलेगा. धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

**धनु** 21 नवंबर से 20 दिसंबर

आत्म–नियंत्रण बनाकर चलें, ताकि आवेश में आकर कोई गलती न कर बैठें. कोई नया मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा. आकस्मिक यात्रा के योग प्रबल हैं. नौकरी–पेशा लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है. व्यापारी पैसों के लेन–देन के मामलों को लेकर कुछ परेशान रहेंगे.

**मकर** 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह कठिन मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. नौकरी–पेशा लोग अपने सहकर्मियों पर नज़र रखें, अन्यथा कोई गलती आपको भारी पड़ सकती है. व्यवसायी उधार दी गई रकम की वसूली करेंगे. मेहमानों की आवाजाही लगी रहेगी. किसी नई जगह की यात्रा संभव है.

**कुंभ** 21 जनवरी से 20 फरवरी

आप नए विचारों के साथ बहुत मेहनत से कार्य करेंगे और सफल भी रहेंगे. आपका ज़्यादातर समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने में लगा रहेगा. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. संतान सुख मिलेगा. नौकरी–पेशा और व्यापारी दोनों आम तौर पर खुश रहेंगे. कोई नया शख्स मददगार साबित होगा.

**मीन** 21 फरवरी से 20 मार्च

आप पैसा कमाने में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. किसी की मदद करेंगे अथवा सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा. गुस्से से बचें, अन्यथा नुकसान होगा और स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा.

cshekhar_3@hotmail.com

भारत और चीन के बीच सीमा सहित विभिन्न मुद्दों पर कई उच्चस्तरीय वार्ताएं हुईं, लेकिन सभी का नतीजा सिफर रहा.



# ड्रैगन भरोसे के लायक नहीं होते

**धूर्त चीन आज भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है, जो हिंदी-चीनी भाई-भाई की आड़ में कब जहर बुझा खंजर भारत की पीठ में मार दे, यह कोई कह नहीं सकता. इसलिए सतत सावधान रहने की ज़रूरत है.**

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

चीन के सैनिकों द्वारा लद्दाख की देपसांग घाटी में 19 किलोमीटर तक घुसपैठ की घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन यात्रा पर गए. उन्होंने न तो चीन से उसकी सेना के लद्दाख में घुसने का कारण पूछा और न ही चीन ने खुद घुसपैठ के अपने दुस्साहस के पीछे कोई वजह बताई. सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हम इससे आगे जाना चाहते हैं, फिलहाल बाल की खाल निकालने की कोई वजह नहीं है. यह है सीमा अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक विदेश मंत्री का जवाब. सवाल यह उठता है कि आख़िर हमारा विदेश मंत्रालय करता क्या है? क्या उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उच्चस्तरीय वार्ताओं तक ही सीमित है और ऐसी वार्ताएं, जिनका अभी तक कोई ठोस या सर्वमान्य हल तक नहीं निकला है, बल्कि ऐसी वार्ताओं के बाद चीन की गुस्ताखियां और बढ़ ही जाती हैं. सवाल यह भी उठता है कि अभी तक सलमान खुर्शीद चीन के साथ किसी भी बिंदू पर अपनी समस्या को सुलझाने के मामले में कितना आगे बढ़े हैं? फिलहाल यही लगता है कि वह सिर्फ़ देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और खुद भी मुगालते में हैं. हो सकता है, वह इस उम्मीद में भी हों कि चीन खुद इन समस्याओं पर नज़र डालेगा और फिर उनसे आकर कहेगा कि हम आपकी सीमा का बहुत अतिक्रमण कर चुके, लेकिन और नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोग एक अच्छे और सच्चे पड़ोसी की तरह साथ-साथ रहेंगे, जो कि किसी सपने जैसा है और किसी भी क़ीमत पर संभव नहीं है. दरअसल, सच्चाई तो यह है कि भारत या भारतीय विदेश मंत्री किसी तरह का जोख़िम उठाना ही नहीं चाहते.

खुर्शीद के स्वदेश लौटने के कुछ ही दिनों बाद चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग भारत आए. भारत ने परंपरानुसार अतिथि का तहेदिल से स्वागत भी किया. भारत एवं चीन के प्रधानमंत्रियों ने न केवल सुबह-शाम जी भरकर बातें कीं, बल्कि ढेर सारे समझौते भी किए, लेकिन सीमा के अतिक्रमण जैसे मसले पर कोई बात नहीं की, जबकि यह मसला सबसे महत्वपूर्ण था. आख़िर करते भी क्यों? अगर सीमा के मुद्दे पर बात हो जाती, तो चीन को आगे भी अतिक्रमण करते रहने की खुली छूट कैसे मिलती, जो कि उसका स्वभाव बन चुका है. जाते-जाते चीनी प्रधानमंत्री भोले-भाले हिंदुस्तानियों को हिंदी-चीनी भाई-भाई का पाठ भी पढ़ा गए. उनके जाते ही पता चला कि चीन ने हिंदुस्तान की सीमा में फिर से पांच किलोमीटर तक घुसपैठ की है. चीन की इस धूर्तता से यही आभास मिलता है कि यह उसकी सोची-समझी चाल थी. चीनी प्रधानमंत्री इधर हिंदी-चीनी भाई-भाई की बात कहकर प्रेम एवं सौहार्द्र का झूठा वातावरण तैयार करते रहे और उधर उनकी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ करती रही. कहीं यह सब चीन की चाल तो नहीं? कहीं वह दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ पर खंजर तो नहीं भोंक रहा है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि चीन ने 1962 में भी हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा दिया था और उस समय उसने दोस्ती की आड़ लेते हुए न सिर्फ़ भारत पर हमला बोल दिया था, बल्कि संभलने का मौक़ा दिए बिना न जाने कितने भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया.

भारत और चीन के बीच सीमा सहित विभिन्न मुद्दों पर कई उच्चस्तरीय वार्ताएं हुईं, लेकिन सभी का नतीजा सिफर रहा. कभी घुसपैठ, तो कभी अरुणाचल पर अपनी दावेदारी, पाकिस्तान को न्यूक्लियर सहित हरसंभव सहायता, ग्वादर क्षेत्र को लीज पर लेकर भारत पर निगरानी रखना, श्रीलंका-म्यांमार-बांग्लादेश-नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों में निगरानी तंत्र और बंदरगाहों की स्थापना, सूडान एवं वियतनाम जैसे देशों में तेल और गैस खनन में अड़ंगा डालकर भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित करना और भारत पर साइबर हमले जैसे चीन के कई ऐसे कृत्य हैं, जो भविष्य में भारत के प्रति उसके ख़तरनाक मंसूबों को जाहिर करते हैं. चीन का यह रवैया कोई नया नहीं है, भारतीय हुक्मरानों का चीन की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखना भी कोई नई बात नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन सीमा विवाद को कूटनीतिक तरीके से हल नहीं करना चाहता है. पिछले तीन सालों में चीन ने छह सौ से भी अधिक बार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है. चीन नियंत्रण रेखा की स्पष्टता का हवाला देता है, लेकिन यह सवाल पचने लायक नहीं है, क्योंकि गलती एक-दो बार तो हो सकती है, लेकिन बार-बार कोई कैसे गलती करके सीमा का उल्लंघन करते हुए टेंट लगा सकता है. आख़िर घुसपैठ की कार्रवाई से वह किस बड़ी योजना को अंजाम देना चाहता है? अगर हम इस बात को समय रहते नहीं समझेंगे, तो चीन अपनी दोहरी नीति पर चलते हुए फिर पीछे से वार कर सकता है.

## भारत को घेरने की कोशिश

चीन हिंद महासागर स्थित सेशल्स द्वीप में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है. भारत की जल सीमा के बाहरी क्षेत्र में चीन ने क़रीब दो दर्जन पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं. हिंद महासागर के अलावा, चीन ने बांग्लादेश के चटगांव एवं सिटवे, म्यांमार के कोको द्वीप, श्रीलंका के हमबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के आसपास भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर इन सभी जगहों पर अपना निगरानी तंत्र और बंदरगाह स्थापित करके चीन भारत को समुद्र की तीन दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रहा है. भारत में नक्सल आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से हथियार और पैसा मुहैया कराने में भी चीन अहम भूमिका निभा रहा है, जो वर्तमान में भारत के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक समस्या है.

### टांय-टांय फिस्स

भारत की स्थिति यह है कि वह आज भी चीन से बड़ा शत्रु पाकिस्तान को समझता है, इसलिए वह चीन को लेकर सजग नहीं है, जबकि चीन आएदिन भारत को आंखें दिखाता है. 1962 के हमारे जख्म अभी भरे नहीं हैं. मंत्री या अधिकारी स्तर की वार्ताओं का फ़ायदा तभी हो सकता है, जबकि उनका कोई निष्कर्ष निकले. सवाल यह है कि आज तक की वार्ताओं का क्या हल निकला? आज भी चीन मनमानी करने से बाज नहीं आता और हम हमेशा उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं. कहना गलत नहीं होगा कि पूरे तामझाम के बीच भी भारत और चीन की वार्ताएं हमेशा टांय-टांय फिस्स ही साबित होती हैं.

## भारतीय रक्षा ठिकानों पर चीन की नज़र

नेपाल से लगी भारतीय सीमा पर चीन द्वारा दो दर्जन से अधिक चीनी अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिनके माध्यम से खुफिया सूचनाओं का संकलन और मधेश क्षेत्र को चीन का प्रभाव केंद्र बनाने का अभियान चलाने की योजना है. नेपाल की मासिक पत्रिका डिमालिनी के अनुसार, 300 करोड़ रुपये की लागत से भगवान बुद्ध के लुंबिनी में चीन का जासूसी अड्डा शीर्षक से प्रकाशित लेख को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियां चौंकन्नी हो गई हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन की खुफिया एजेंसी एवं लुंबिनी विकास संस्था के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर तक हो चुके हैं.

## साइबर हमला

चीन के हैकरों ने भारत की रक्षा मामलों संबंधी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हज़ारों फाइलों, मिसाइल विकास कार्यक्रम सहित भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान के हैदराबाद स्थित लैब में भी सेंध लगाई है. यहां तक कि चीन ने सुपर पावर अमेरिका के कंप्यूटरों में भी अभी हाल में सेंध लगाकर महत्वपूर्ण डिजाइन चुरा लिए.

## सुलगते मुद्दे

**हिंद महासागर :** चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में निगरानी तंत्र सहित बंदरगाह बनाकर अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं. पाकिस्तान, म्यांमार एवं श्रीलंका के साथ साझीदारी में परियोजनाएं शुरू करके वह भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है.

**पीओके :** पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बालटिस्तान में चीनी गतिविधियां तेज हुई हैं. पूर्व सेना प्रमुख वी के सिंह ने खुद कहा कि इन इलाकों में तीन से चार हज़ार चीनी कार्यरत हैं, जिनमें पीएलए के लोग भी हैं.

**दक्षिण चीन सागर :** ऊर्जा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर चीन दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है. यहां उसे वियतनाम, जापान एवं फिलीपींस से चुनौती मिल रही है. हाल में उसने वियतनाम की तेल ब्लॉक परियोजनाओं में शामिल भारतीय कंपनियों को चेतावनी दी कि वे दक्षिण चीन सागर से दूर रहें.

**अक्साई चिन सड़क :** चीन ने लद्दाख इलाके में इस सड़क का निर्माण किया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है. चीन जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग मानने में आनाकानी करता है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का भाग मानने में उसे कोई आपत्ति नहीं है.

**विवादित सीमा :** आज भी 3000 किलोमीटर की ऐसी विवादित सीमा है, जिसे लेकर भारत और चीन के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिसका इस्तेमाल चीन भारत को परेशान करने में हमेशा करता है, ताकि उसका ध्यान हमेशा इसी ओर लगा रहे.

**तिब्बत :** तिब्बत को चीन ने 1950 में हटा दिया, जो राजनीतिक एवं भौगोलिक रूप से बफर का काम करता था. भारत द्वारा तिब्बत को मान्यता हासिल है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों के बहाने चीन इस मसले पर राजनीति करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता.

**अरुणाचल :** चीन समय-समय पर अरुणाचल पर अपना दावा करता रहता है. अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को नत्थी वीजा भी देता है.

**ब्रह्मपुत्र :** ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध बनाने जैसे द्विपक्षीय मसले को भारत अक्सर बातचीत में उठाता रहता है, क्योंकि भविष्य में यह मुद्दा एक बड़े विवाद के रूप में उभर सकता है. चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहरों के जरिए अपने उत्तरी इलाकों में ले जाना चाहता है.

## क्या करें?

भारत का चीन के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते काफी तटस्थ हैं, जबकि हमें उनसे मधुर एवं मजबूत संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर चीन पर दबाव बनाया जा सके. हाल में जापान से भारत के समझौते पर चीन की बौखलाहट से यह साफ़ जाहिर हो जाता है कि वह अपने पड़ोसी देशों से भारत की नज़दीकी कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा उसके लिए आने वाले दिनों में नुकसानदेह साबित हो सकता है. एक तरफ़ चीन के साथ जो विवाद हैं, भारत को उन्हें कूटनीतिक तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरी तरफ़ सीमा से लगे दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार करना होगा कि भारतीय सेना अगर अपने हथियारों, रसद और साजो-सामान के साथ किसी इलाके में पहुंचना चाहे, तो उसे किसी तरह की परेशानी न हो. भारत को अंडमान-निकोबार एवं लक्षद्वीप समेत द्वीपीय क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य, नौसैनिक और हवाई ठिकाने मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. नौसैनिक ठिकानों, युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों की हिफाजत हर क़ीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए. नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए. ■

इस मंदिर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है. जहां का मनोरम दृश्य भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच ले आता है.

# श्री साई नाथ स्तवन मंजरी

साधु-असाधु सभी पा करुणा, दृष्टि समान सभी पर रखना.
पापी से कम प्यार न करते, पाप-ताप हर करुणा करते.

जो मलयुक्त है बहकर आता, सुरसरि जल में आन समाता.
निर्मल मंजूषा में रहता, सुरसरि जल नहीं वह गहता.

वही वसन इक बार था आया, मंजूषा में रहा समाया.
अवगाहन सुरसरि में करता, धुल कर निर्मल ख़ुद को करता.

सुदृढ़ मंजूषा है बैकुंठ. अलौकिक निष्ठा गंग तरंग.
जीवात्मा ही वसन समझिए, षड् विकार ही मैल समझिए.

जग में तव पद-दर्शन पाना, यही गंगा में डूब नहाना.
पावन इससे होते तन-मन, मल विमुक्त होता वह तत्क्षण.

दुःखद विवश हैं हम संसारी, दोष-कालिमा हम में भारी,
संत दरश केहम अधिकारी, मुक्ति हेतु निज बाट निहारी.

गोदावरी पूरित निर्मल जल, मैली गठरी भीगी तत्जल.
बन न सकी यदि फिर भी निर्मल, क्या न दोषयुक्त गोदावरी जल.

आप सघन हैं शीतल तरुवर, श्रांत पथिक हम डगमग पथ हम,
तपे ताप त्रय महाप्रखर तम, जेठ दुपहरी जलते भूकण.

ताप हमारे दूर निवारों, महा विपद से आप उबारों.
करों नाथ तुम करुणा छाया, सर्वज्ञात तेरी प्रभु दाया.

परम व्यर्थ वह छाया तरु है, दूर करे न ताप प्रखर है.
जो शरणागत को न बचाए, शीतल तरु कैसे कहलाए.

कृपा आपकी यदि नहीं पावें, कैसे निर्मल हम रह जावें,
पारथ-साथ रहे थे गिरधर, धर्म हेतु प्रभु पांचजन्य धर.

सुग्रीव कृपा से दनुज विभीषण, पाया प्राण तपाल रघुपति पद.
भगवत पाते अमित बड़ाई, संत मात्र के कारण भाई.

नेति-नेति हैं वेद उचरते, रूप रहित हैं ब्रह्म विचरते.
महामंत्र संतों ने पाएं, सगुण बनाकर भू पर लाएं.

दामा ए दिया रूप महार, रुक्मणि वर त्रैलोक्य आधार.
चोखी जी ने किया कमाल, विष्णु को दिया कर्म पशुपाल.

महिमा संत ईश ही जानें, दासनु दास स्वयं बन जावें,
सच्चा संत बड़प्पन पाता, प्रभु का सुजन अतिथि हो जाता.

ऐसे संत तुम्हीं सुखदाता, तुम्हीं पिता हो तुम ही माता.
सद्गुरु साई नाथ हमारे, कलियुग में शिरडी अवतारे.

लीला तिहारी नाथ महान, जन-जन नहीं पाएं पहचान.
जिव्हा कर न सके गुणगान, तना हुआ है रहस्य वितान.

तुमने जल के दीप जलाएं, चमत्कार जग में थे पाएं.
भक्त उद्धार हित जग में आए, तीरथ शिरडी धाम बनाए.

जो जिस रूप आपको ध्याए, देव स्वरूप वही तव पाए.
सूक्ष्म तत्व निज सेज बनाएं, विचित्र योग सामर्थ्य दिखाएं.

पुत्रहीन संतति पा जावें, रोग असाध्य नहीं रह जावें.
रक्षा वह विभूति से पाता, शरण तिहारी जो भी आता.

भक्तजनों के संकट हरते, कार्य असंभव संभव करते.
जग की चींटी भार शून्य ज्यों, समक्ष तिहारे कठिन कार्य त्यों.

साई सद्गुरु नाथ हमारे, रहम करो मुझ पर हे प्यारे.
शरणागत हूं प्रभु अपनाएं, इस अनाथ को न ठुकराएं.

प्रभु तुम हो राज्य राजेश्वर, कुबेर के भी परम अधीश्वर.
देव धनवंतरी तव अवतार, प्राणदायक है सर्वाधार.

बहु देवों का पूजन करते, बाह्य वस्तु हम संग्रह करते.
पूजा प्रभु की सीधी-साधी, बाह्य वस्तु की नहीं उपाधी.

जैसे दीपावली त्योहार, आए प्रखर सूरज के द्वार.
दीपक ज्योति कहां वह लाएं, सूर्य समक्ष जो जगमग होए.

जल क्या ऐसा भू के पास, बुझा सके जो सागर प्यास.
अग्नि जिससे उष्मा पाएं, ऐसी वस्तु कहां हम पाएं.

जो पदार्थ हैं प्रभु पूजन के, आत्मवश वे सभी आपके.
हे समर्थ गुरुदेव हमारे, निर्गुण अलख निरंजन प्यारे.

तत्व दृष्टि का दर्शन कुछ है, भक्ति भावना हृदय सत्य है.
केवल वाणी परम निरर्थक, अनुभव करना निज में सार्थक.

अर्पित करूं तुम्हें क्या साई, वह संपत्ति जग में नहीं पाई.
जग वैभव तुमने उपजाया, कैसे कहूं कमी कुछ दाता.

पत्रं-पुष्पं विनत चढ़ाऊं, प्रभु चरणों में चित्त लगाऊं.
जो कुछ मिला मुझे हे स्वामी, करूं समर्पित तन-मन वाणी.

प्रेम अश्रु जलधार बहाऊं, प्रभु चरणों को मैं नहलाऊं.
चंदन बना हृदय निज गारूं, भक्ति भाव का तिलक लगाऊं.

शब्दाभूषण-कफनी लाऊं, प्रेम निशानी वह पहनाऊं.
प्रणय सुमन उपहार बनाऊं, नाथ कंठ में पुलक चढ़ाऊं.

आहुति दोषों की कर डालूं, वेदी में वह होम उछालूं.
दुर्विचार धूम्र यों भागे, वह दुर्गंध नहीं फिर लागे.

अग्नि सरिस हैं सद्गुरु समर्थ, दुर्गुण-धूप करें हम अर्पित.
स्वाहा जलकर जब होता है, तद्रूप तत्क्षण बन जाता है.

धूप-द्रव्य जब उस पर चढ़ता, अग्नि ज्वाला में है जलता.
सुरभि अस्तित्व कहां रहेगा, दूर गगन में शून्य बनेगा.

प्रभु की होती अन्यथा रीति, बनती कुवस्तु जलकर विभूति.
सद्गुण कुंदन सा बन दमके, शाश्वत जग बढ़ निरखे-परखे.

निर्मल मन जब हो जाता है, दुर्विकार तब जल जाता है.
गंगा ज्यों पावन है होती, अविकल दूषण मल वह धोती.

साई के हित दीप बनाऊं, सत्वर माया मोह जलाऊं.
विराग प्रकाश जगमग होवे, राग अंध वह उर का खोवे.

पावन निष्ठा का सिंहासन, निर्मित करता प्रभु के कारण.
कृपा करें प्रभु आप पधारें, अब नैवेद्य-भक्ति स्वीकारें.

भक्ति-नैवेद्य प्रभु तुम पाओ, सरस-रास-रस हमें पिलाओ.
माता, मैं हूं वत्स तिहारा, पाऊं तव दुग्धामृत धारा.

मन रूपी दक्षिणा चुकाऊं, मन में नहीं कुछ और बसाऊं.
अहम भाव सब करूं समर्पण, अंत: रहे नाथ का दर्पण.

विनती नाथ पुन: दुहराऊं, श्री चरणों में शीश नवाऊं.
साई कलियुग ब्रह्म अवतार, करो प्रणाम मेरे स्वीकार. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

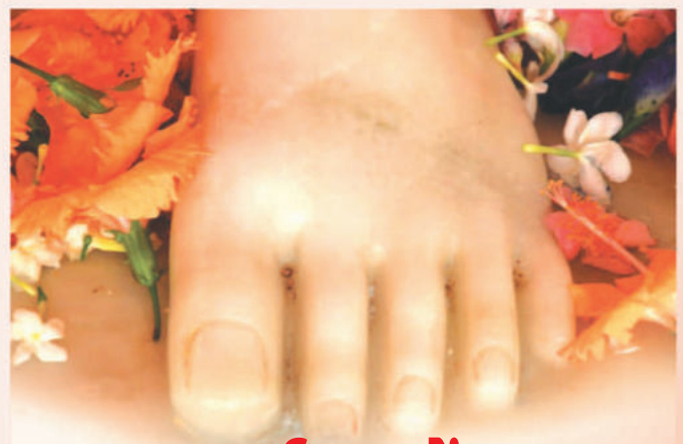

## साई भक्तों!

**आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.**

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर),
उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

आस्था

## मंगलनाथ मंदिर

# जहां धुल जाते हैं सारे पाप...

यहां का सान्निध्य पाकर लोग धन्य हो जाते हैं, और भक्तों के पाप भी स्वत: धुल जाते हैं. लोग अपनी झोली में न केवल अपार खुशियां लेकर लौट जाते हैं, बल्कि भक्तों के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं. क्या है विशेषता इस मंदिर की?

मंगलनाथ मंदिर की गिनती भारत के प्रमुख मंदिरों में की जाती है. मंदिर प्रमुख धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित है. इस मंदिर की महिमा अपरम्पार है. यहां आकर कोई भक्त निराश नहीं लौटता. उज्जैन को मंगल की जननी भी कहा जाता है. यह मंदिर भक्तों की सभी विपदाओं को हर लेता है. इसी कारण इस मंदिर का विशेष महत्व है. अपनी कुंडली में मंगल के भारी पड़ने पर भक्त मंगल की शांति के लिए यहां आते हैं.

इस मंदिर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है. जहां का मनोरम दृश्य भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच ले आता है. इस पवित्र धाम पर आना भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा से कम नहीं, जिसकी याद ताउम्र जेहन में बनी रहती है. मत्स्य पुराण तथा स्कंध पुराण में मंगल देव के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है. इन पुराणों के अनुसार, उज्जैन में ही मंगल भगवान की उत्पत्ति हुई थी. मंगलनाथ मंदिर ही वह स्थान है, जहां मंगल देव का जन्म स्थान है. इस कारण इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है. इस मंदिर को दैवीय गुणों से युक्त माना जाता है.

वैसे तो देश भर में मंगल भगवान के अनेक मंदिर हैं, परंतु मंगल का जन्म होने के कारण यह मंदिर देश के अन्य मंदिरों से अलग है. मंगल का जन्म होने के कारण ही इस स्थान को मंगल की जननी कहा गया. आप मंगल की पूजा देश के किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहां आकर मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. मंदिर में दूर-दूर से लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है. इसलिए इस मंदिर का खास महत्व है. सभी लोग, जिनके लिए मंगल की शांति की पूजा बताई जाती है, उन्हें इस स्थान पर आकर इस पूजा को करना चाहिए, ताकि उनके कष्ट का निवारण जल्द हो सके.

### ■ संरक्षक देवता हैं मंगल

मंगल भगवान को संरक्षक देवता कहा जाता है. इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये दक्षिण एशिया के संरक्षक हैं. इनका स्थान नव ग्रहों में आता है. इन्हें अंगारका और खुज नाम से भी जाना जाता है. वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार, मंगल ग्रह शक्ति, वीरता और साहस के परिचायक हैं तथा धर्म के रक्षक माने जाते हैं. मंगल देव को मंदिरों और तस्वीरों में चार हाथ वाले त्रिशूल और गदा धारण किए दर्शाया गया है. ये दुष्टों और असुरों के संहारक हैं. भगवान मंगल की पूजा से सारे कार्य मंगल होते हैं, साथ ही मन हमेशा शांत रहता है. कर्ज से मुक्ति और धन लाभ भी इनकी पूजा-अर्चना से प्राप्त होता है. दुष्ट ग्रहों के नाश के लिए मंगल के रत्न रूप में मूंगा धारण किया जाता है.

### ■ जन्म कथा

पुराणों में मंगल देव के जन्म की कथा के बारे में उल्लेख मिलता है. बताया गया है कि अंधकासुर नामक एक राक्षस था. वह बहुत आततायी था. इस राक्षस से सभी आक्रांत थे. अंधकासुर ने भगवान शिव की वर्षों तक कठोर तपस्या की. उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और राक्षस से आशीर्वाद मांगने को कहा. अंधकासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि मेरी रक्त की बूंदें जहां भी गिरें, वहां मैं फिर से जन्म लेता रहूं. भगवान शिव तथास्तु कहकर लुप्त हो गए. शिव से वरदान पाकर अंधकासुर मद में चूर होकर और भी आततायी हो गया और चारों ओर तबाही फैलाने लगा. शिव के वरदान स्वरूप कोई भी उसे हरा नहीं पाता, जिसके कारण सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें राक्षस के इस संकट से उबारें. भक्तों की पुकार सुन कर भगवान शिव अंधकासुर से युद्ध करते हैं. शिव और राक्षस के बीच भीषण युद्ध होता है. भगवान शिव जितनी बार भी अपने त्रिशूल से उसे मारते हैं, वह अगले ही पल पुन: जीवित हो जाता है. उसका रक्त गिरते ही अनेक अंधकासुर उत्पन्न हो जाते हैं. इस लम्बे युद्ध को करते-करते भगवान शिव थक जाते हैं और उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें उज्जैन की भूमि पर गिरती हैं और उन बुंदों के गिरने से पृथ्वी दो भागों में बंट जाती है, जिसमें से मंगल देव का जन्म होता है और इस बीच दैत्य का सारा रक्त मंगल में समा जाता है, जिससे उसका अंत होता है.

### ■ कैसे पहुंचें-
### सड़क मार्ग से

यहां नीचे दिए गए इन बस रूटों से आप मंगलनाथ मंदिर जा सकते हैं.

उज्जैन-आगरा-कोटा-जयपुर मार्ग, उज्जैन-बदनावर-रतलाम-चित्तौड़ मार्ग, उज्जैन-मक्सी-शाजापुर-ग्वालियर-दिल्ली मार्ग, उज्जैन-देवास-भोपाल मार्ग, उज्जैन-धुलिया-नासिक-मुंबई मार्ग.

### ■ रेल मार्ग-

उज्जैन से मक्सी-भोपाल मार्ग (दिल्ली-नागपुर लाइन), उज्जैन-नागदा-रतलाम मार्ग (मुंबई-दिल्ली लाइन), उज्जैन-इंदौर मार्ग (मीटरगेज से खंडवा लाइन), उज्जैन-मक्सी-ग्वालियर-दिल्ली मार्ग.

### ■ वायुमार्ग-

उज्जैन से इंदौर एअरपोर्ट लगभग 65 किलोमीटर दूर है.

### ■ कहां ठहरें

उज्जैन में अच्छे होटलों से लेकर आम धर्मशाला सब कुछ उपलब्ध है. इसके साथ-साथ महाकाल समिति की महाकाल और हरसिद्धि मंदिर के पास अच्छी धर्मशालाएं हैं. इन धर्मशालाओं में एसी, नॉन एसी रूम और डॉरमेट्री उपलब्ध है. मंदिर प्रबंध समिति इनका अच्छा रखरखाव करती है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

दरअसल

# जी मालिक...

अपने प्रिय नौकर को स्टेशन पर देखकर मालिक प्रसन्न हो गया. नौकर उन्हें लेने आया था. स्टेशन पर नौकर ने मालिक से पूछा,
घर पर सब कुछ कुशल है न!
जी मालिक, सब कुछ कुशल है. केवल आपका प्यारा, दुलारा कुत्ता 15 दिनों पूर्व गुजर गया.
हाय! कैसे मरा वह?
आपके तगड़े घोड़े की हड्डी उसके गले में अटक गई और कुत्ते ने जी जान से कोशिश की हड्डी को बाहर निकालने की, लेकिन यह संभव नहीं हो सका और वह मर गया.
मेरे घोड़े की हड्डी उसे कैसे मिल सकती है? क्या घोड़ा मर गया?
दरअसल, हुआ यह कि जब से आप गये हैं, घोड़े को भरपेट भोजन नहीं मिला. घर में दाना था ही नहीं!
दाना को क्या हुआ? अनाज तो भरा पड़ा था!
आपकी मां की चिता जलाने में सब कुछ खर्च हो गया.
हाय! क्या मेरी मां मर गई? वह कैसे मरी?
अपने इकलौते पोते की मृत्यु सहन नहीं कर सकी.
हाय! क्या मेरा बेटा मर गया?
जी, वह तब मरा, जब आपका घर गिरा?
क्या मेरा घर भी गिर गया?
दरअसल, पेट्रोल छिड़ककर जब आपकी पत्नी ने आत्महत्या की, तभी छत आपके लड़के पर ही गिर गई.
हाय! मैं बर्बाद हो गया, मेरे सभी सगे मर गये. फिर भी तुम कहते हो कि सब कुछ कुशल है.
जी मालिक, बाकी सब कुछ कुशल है.
मालिक बेहोश होकर, गिर जाता है.
शिक्षा : मूर्ख न अपनी रक्षा कर सकते हैं और न ही दूसरे की सेवा ■

मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं, जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल-पोस रहा है.

अनंत विजय

# स्टारडम की भूख!

**अंग्रेजी उपन्यासों को जो लोकप्रियता मिलती है, वह हिंदी उपन्यासों को नहीं मिल पाती. इसके बावजूद हिंदी लेखिकाओं में स्टारडम की भूख दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हिंदी के लिए अच्छा संकेत नहीं है. ऐसा क्यों?**

पिछले साल जब ई एल जेम्स का उपन्यास फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे छपा था, तब अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया में उसकी पचास लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक गई थीं. लाखों डॉलर में उसके फिल्म राइट बिके थे. तक़रीबन चालीस हफ्तों तक अमेरिका के अख़बारों में बेस्ट सेलर की सूची में पहले नंबर पर रहने के बाद इस उपन्यास की लोकप्रियता में थोड़ी कमी ज़रूर आई थी, लेकिन अब भी पाठक उसको लेकर उत्साहित हैं और सच तो यह है कि बिक्री भी जारी है. फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की सफलता के शोरगुल के बीच एक अन्य उपन्यास की सफलता ज़रा दब-सी गई थी. मनोरंजन और फ़िल्म पत्रकारिता करने वाली गिलियन फ्लिन का उपन्यास गॉन गर्ल तक़रीबन दस महीने पहले छपा था. गलियन फ्लिन के इस उपन्यास के छपने से लेकर अब तक सिर्फ़ अमेरिका में उसकी तीस लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और कई हफ्तों तक वह अमेरिकी अख़बारों की बेस्ट सेलर की सूची में भी रह चुका है. जब इस साल जनवरी में यह उपन्यास ब्रिटेन में रिलीज हुआ, तो दो महीने में इसकी साढ़े तीन लाख प्रतियां बिक गईं. एक बार फिर से इस उपन्यास ने आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. जब ई एल जेम्स का उपन्यास फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे प्रकाशित होकर धड़ाधड़ बिक रहा था, तब साथ ही साथ उस पर अश्लीलता का आरोप भी लग रहा था और कई आलोचकों ने उसे ममी पोर्न तक क़रार दे दिया था. उपन्यास में वर्णित सेक्स प्रसंगों की बहुतायत को उसकी ज़बरदस्त बिक्री का आधार बताया गया था. अमेरिका के पुस्तकालयों में उस किताब की ख़रीद को लेकर विवाद हुआ था. ई एल जेम्स के उपन्यास फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे और गिलियन फ्लिन के इस उपन्यास गॉन गर्ल में बुनियादी फ़र्क़ है. ई एल जेम्स का उपन्यास प्रेमी-प्रेमिका के बीच सेक्स के विभिन्न आयामों का विश्लेषण था, लेकिन फ्लिन के उपन्यास में पति-पत्नी के संबंधों के बारे में सूक्ष्मता से लिखा गया है. गॉन गर्ल के नायक और नायिका एमी और निक की शादी की पांचवीं सालगिरह पर एमी ग़ायब हो जाती है. ग़ायब होने के बाद जब जांच शुरू होती है, तो जांचकर्ताओं को उसकी हत्या होने का शक होता है. शक की सुई उसके पति निक की ओर घूमती है. इस उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती चली जाती है. एक थ्रिलर की तरह, पाठकों को बांधते हुए.

इसके पहले भी गिलियन फ्लिन के दो उपन्यास शॉर्प ऑब्जेक्ट्स और डॉर्क प्लेसेस प्रकाशित हो चुके हैं. उनका पहला उपन्यास शॉर्प ऑब्जेक्ट्स एक क्राइम थ्रिलर है, जो मिसौरी के एक सीरियल किलर के इर्द-गिर्द चलता है. फ्लिन का दूसरा उपन्यास डॉर्क प्लेसेस एक लड़की की कहानी है, जो अपने परिवार के सदस्यों की हत्या को इंवेस्टिगेट करती है. कहने का मतलब यह है कि अब तक क्राइम थ्रिलर लिखने वाली लेखिका गिलियन फ्लिन ने पहली बार पति-पत्नी के जटिल संबंधों पर लिखा है. लेखिका का मानना है कि शादी के बाद का जीवन एक ऐसा खेल है, जिसमें अपने साथी के आत्मविश्वास को ध्वस्त कर जीतने की कला में पारंगत होना होता है. इसमें थोड़ा-बहुत शक्ति प्रदर्शन, छोटे-मोटे झगड़े भी होते हैं, लेकिन अंतत: लक्ष्य तो जीत का ही होता है. लेखिका का यह वाक्य इस पूरे उपन्यास में दिखाई देता है, जब एमी और निक की बातें और क्रियाकलाप एक दूसरे को हराने जैसे होते हैं.

अमेरिका और यूरोप के आलोचकों का कहना है कि फ्लिन के इस उपन्यास में कई बार उसकी ज़िंदगी साफ़ तौर पर दिखाई देती है, जिसको उसने अपने अनुभवों को कल्पना के साथ मिलाकर पेश किया है. मसलन, इस उपन्यास की नायिका एमी भी नब्बे के दशक के अंत में न्यूयॉर्क आती है और लेखिका बनने के लिए संघर्ष करती है. लगभग यही समय होता है, जब लेखिका भी मौसुरी से न्यूयॉर्क आती है और एक पत्रिका में नौकरी करती है. साथ ही लेखिका बनने के लिए हाथ पांव भी मारती है. इस तरह

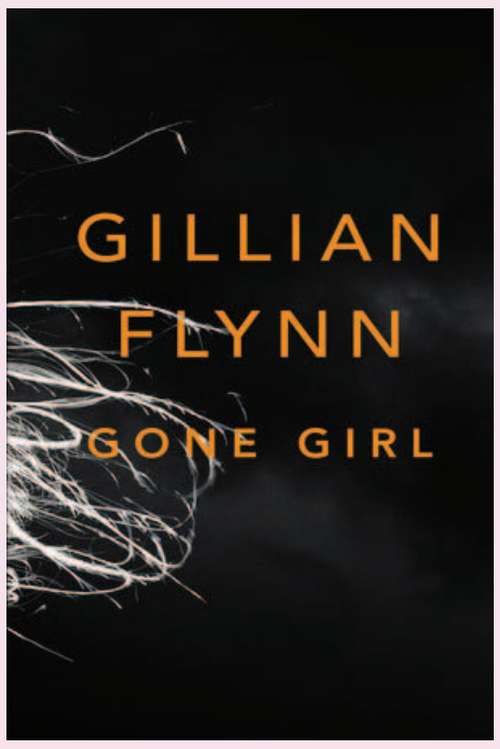


के कई प्रसंग हैं, जिनकी लेखिका की ज़िंदगी से समानता है. यह हो सकता है कि महज़ संयोग हो कि उपन्यास प्रकाशन के आसपास ही लेखिका ने अपनी शादी की पांचवीं सालगिरह भी मनाई थी. गॉन गर्ल की नायिका भी बिंदास है, जिसे फुटबॉल से प्यार है, जो अपने दोस्तों के साथ अश्लील जोक्स शेयर करती है, वीडियो गेम्स खेलती है, सस्ती बीयर पीती है, एक साथ दो-तीन लोगों से शारीरिक संबंध बनाने में भी नहीं हिचकती है, बल्कि उसे बेहतर ढंग से एंजॉय करती है. उपन्यास की लेखिका ने भी अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि एक वक़्त ऐसा था, जब वह भी बिंदास लड़की बनना चाहता थी और उसे मस्ती से ज़िंदगी जीना पसंद था. इसके अलावा, उसके इस उपन्यास में नायक निक का एक वकील होता है, जिसका चरित्र लेखिका के पति के वास्तविक जीवन से मेल खाता है. लेखिका का मानना है कि हम किसी के विश्वास को जीतकर उसके साथ रागात्मक संबंध बनाते हैं, लेकिन दरअसल, हमारे मन के किसी कोने, अंतरे में अपने लक्ष्य को हासिल करने की तमन्ना छुपी होती है. उस तमन्ना को हासिल करने के लिए हम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोशिश करते हैं. गॉन गर्ल की भी यही थीम है. पूरे उपन्यास में पति-पत्नी के बीच के संबंधों की कथा इतने रोचक तरीक़े से चलती है कि वह पाठकों को अंत तक बांधे रखती है. दरअसल, उन्नीस सौ बारह में छपे दो उपन्यासों को जिस तरह से प्यार मिला और दोनों किताबों की बिक्री को जोड़ दिया जाए, तो बहुत संभव है कि वह संख्या आने वाले एक-दो महीने में एक करोड़ को पार कर जाए. काश, ऐसा कभी हिंदी में भी संभव हो पाता! यहां तो एक संस्करण में छपने वाली पुस्तकों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन लेखकों का एटिट्यूड बढ़ता जा रहा है. आज हिंदी की महिला लेखिकाओं के अंदर जिस तरह की स्टारडम की भूख देखने को मिल रही है, वह हिंदी के लिए शुभ संकेत नहीं है. युवा लेखकों के नाम पर हिंदी में ढेर सारा कूड़ा कबाड़ा छप रहा है. छपते ही लेखकों को लगने लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली परीक्षा तो पाठकों की अदालत में ही होती है.■

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*
anant.ibn@gmail.com

## शिकागो में स्वामी विवेकानंद

# सभी धर्मों की सत्यता स्वीकार है...

**मुझे उस देश के देशवासी होने का गर्व है, जिस देश ने पृथ्वी के सभी धर्मों व सभी देशों के सताए हुए लोगों और शरणार्थियों को शरण दी है...**

महान मूल्यों, आदर्शों और सभी धर्मों के प्रति आस्था के कारण ही स्वामी विवेकानंद 150 साल बाद भी आज लोगों के बीच जीवित हैं. उनकी विद्वता का पूरा विश्व कायल है. उनका जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ था. बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. वे वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे. दरअसल, उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था. वेदान्त दर्शन को अमेरिका और यूरोप में फैलाने का श्रेय विवेकानंद को ही जाता है. वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे. उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी मौजूद है. विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने प्रेरणात्मक भाषण से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया. यहां पेश है, 1893 में शिकागो में दिया गया उनका महत्वपूर्ण भाषण...

अमेरिका के बहनोऔर भाइयो,

आपने जिस तरह से मेरा हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्वागत किया है, उसे देख कर मेरा मन अपार हर्ष से भर गया है. मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं. मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति, संप्रदाय के लाखों, करोड़ों हिन्दुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया. हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों की सत्यता को स्वीकार करते हैं.

मुझे उस देश के देशवासी होने का भी गर्व है, जिस देश ने पृथ्वी के सभी धर्मों व सभी देशों के सताए हुए लोगों और शरणार्थियों को शरण दी है. मुझे आपको यह बताने में गर्व है कि हमने उन पवित्र इजराइलियों को अपने कलेजे से लगाया है, जिन्होंने ठीक उसी वर्ष दक्षिण भारत में आकर शरण ली, जब रोमन अत्याचारियों ने उनके पवित्र मंदिर को ध्वस्त कर दिया था. मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं, जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल-पोस रहा है. जिस तरह अलग-अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग-अलग मार्ग चुनता है. वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े-मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं. वर्तमान सम्मलेन, जो आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताये गये एक सिद्धांत का प्रमाण है. किसी भी रूप में, जो मुझ तक आता है, मैं उस तक पहुंचता हूं, सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में है.

सांप्रदायिकता, कट्टरता और साथ ही इनसे उपजी धर्मांधता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है. इनके कारण पृथ्वी पर चारों तरफ हिंसा पनप चुकी है. न जाने कितनी बार यह पृथ्वी मानव रक्त में सनी और लाल हुई. इन अवगुणों ने सभ्यता को नष्ट किया है और समूचे राष्ट्रों को निराशा के अंधेरे में धकेल दिया है.

यदि ये राक्षसी कृत्य नहीकिए जाते, तो आज मानव समाज विकास की कोई और ही कहानी बयां करता, लेकिन ऐसे अवगुणों का समय अब पूरा हो चुका है. मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि इस सम्मेलन के सम्मान में सुबह जो शंखनाद हुआ था, वह सभी तरह की हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वह तलवार से हो या कलम से और जो एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात् सभी तरह के मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा. ■

**मैं एक ऐसे धर्म से हूं, जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल-पोस रहा है.**

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

किताब

# सकारात्मक सोच और अनुशासन की अहमियत

निर्मलेंदु
feedback@chauthiduniya.com

हाल में पेंगुइन बुक्स ने एक बुक प्रकाशित की है. 10 मिनट सोचें अपने लिए. लेखक हैं डॉ राजकुमार सिंह, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) में जंतुविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं. बचपन से ही चिंतन, अध्यात्म का शौक रहा है उन्हें. उन्होंने कहा कि जीवन जीना एक कला है. उनका मानना है कि यदि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सही दिशा में चल पाएंगे. यानी आप दूसरों से थोड़ा हटकर सोचें, क्योंकि ऐसा करने से आपका न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपमें एक अलग तरह की ऊर्जा भी पैदा होगी. मन प्रसन्न रहेगा और अंतरात्मा साफ हो जाएगी. उन्होंने किताब के माध्यम से यह सलाह दी कि आप 10 मिनट के लिए चिंतन-मनन में समय देने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश ही कामयाबी की सीढ़ी है. दरअसल, कोशिश से ही हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है.

वह अपने अनुभव को हमारे साथ बांटने की कोशिश करते हैं. कहते हैं कि हम यूं ही बेकार के ख्यालों का ताना-बाना बुनकर अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं. उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर दिन कुछ समय अपनी दिनचर्या से चुराकर कम से कम 10 मिनट अपने बारे में सोचने के लिए जरूर देना चाहिए. यानी, कल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा! सुबह उठें, विचारपूर्वक एवं योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करें और अनुशासन के साथ उसका अमल भी करें. उनका मानना यही है कि अनुशासन हमेशा सौ प्रतिशत ही हो, क्योंकि अनुशासन से ही कामयाबी मिलती है. जहां भी अनुशासन की बात आए, वहां किसी तरह का समझौता न करें. दरअसल, लेखक ने अपनी कक्षा के बच्चों को भी यही सीख दी. उन्होंने बच्चों को समझाया, अगर कभी आपकी कक्षा में कोई शिक्षक नहीं है, तो ऐसे में आप आराम से एक-दूसरे से बातें कर सकते हैं, दूसरा कोई भी काम निबटा सकते हैं. उस दौरान कोई और टास्क भी याद कर सकते हैं. और यदि समय बच जाता है, तो 10 मिनट के लिए सोचें कि आपके पास और क्या-क्या काम है. क्या वे काम स्कूल में बैठकर निबटाए जा सकते हैं. इसलिए केवल 10 मिनट सोचें.

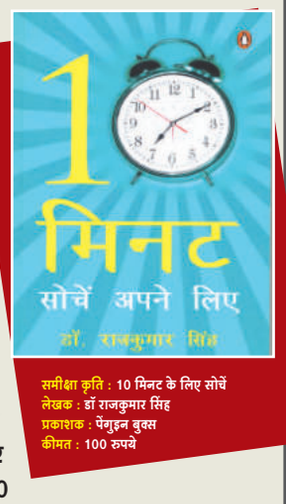


समीक्षा कृति : 10 मिनट के लिए सोचें
लेखक : डॉ राजकुमार सिंह
प्रकाशक : पेंगुइन बुक्स
कीमत : 100 रुपये

उन्होंने आत्मचिंतन की सलाह भी दी,यानी अगर हम अपने अंदर बदलाव के इच्छुक हैं, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा. उन्होंने हमें अपने आपको टटोलने की सलाह दी. उन्होंने कहा, अपने आपको निरंतर टटोलते रहने से ही हम आत्मसुधार कर पाएंगे और यही हमारे सच्चे सुख का आधार भी है. यानी आत्मसुधार के माध्यम से ही हम अपने आपको और ज्यादा सुधार सकते हैं. हालांकि यह एक विकास प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से ही सफल हो सकती है.

डॉ राजकुमार ने किताब के माध्यम से जो बातें बताईं, उनमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हमें जीवनपथ पर अंधाधुंध दौड़ लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें क्या पाना है और क्या हासिल करना चाहते हैं हम? और जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि क्या चाहते हैं हम, तभी हम अपनी दौड़ आरंभ करें. आगे बढ़ने की ललक में हर हथकंडा अपनाकर आप दूसरे साथियों से मीलों आगे जरूर निकल जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ पीछे जरूर छूट जाएगा. आप रास्ते में शायद ऐसी चीजों को छोड़ देंगे, जिनके कारण, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो लोग आपको याद करेंगे. अच्छा करेंगे, तो लोगअच्छा कहेंगे और बुरा करेंगे, तो बुरा कहेंगे. इसलिए अगर आपअभी तक कुछ लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए, तो जल्दी इस पर विचार शुरू कर दें, नहीं तो देर हो जाएगी. जीवन में कुछ नया करने की आदत डालें, कुछ हट कर करने की शुरुआत करें. कुल मिलाकर 98 पृष्ठ की यह किताब, जिसकी कीमत केवल 100 रुपये है, पढ़कर अच्छा लगेगा. दरअसल, इसे पढ़कर आप अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीख जाएंगे. ■

एयरसेल ने इंडिया में फेसबुक की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यह सुविधा शुरू की है. यह संभवतः पहली मोबाइल कंपनी है.



# मर्सिडीज 22 लाख में

लग्जरी कारों के लिए जानी जाने वाली मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भारत में कॉम्पैक्ट लग्जरी हैचबैक ए क्लास 21.93 से 22.73 लाख रुपए में लॉन्च की है. कंपनी के लिए देश में यह नया एंट्री लेवल प्राइस है. इसके डीजल वेरिएंट ए180 सीडीआई में 2.2 लीटर डीजल इंजन है. क़ीमत है 21.93 लाख रुपए. कंपनी का दावा है कि यह भारत में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली लग्जरी कार है. यह कार एक लीटर में 20.6 किलोमीटर चलती है. 1.6 लीटर पेट्रोल वर्जन ए180 स्पोर्ट का दाम 22.73 लाख रुपए है. यह 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा माइलेज देगी.

मर्सिडीज बेंज ए क्लास से देश के पैसेवाले युवाओं को टारगेट कर रही है. मर्सिडीज बेंज इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर केन ने कहा है कि ए क्लास के साथ मर्सिडीज बेंज भारत में कॉम्पैक्ट लग्जरी कार सेगमेंट पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है. यह सेगमेंट कस्टमर की पसंद में आए बदलाव को दिखाता है. नई पीढ़ी कॉम्पैक्ट लग्जरी पसंद करती है. इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है. ए क्लास की दुनिया भर में अच्छी डिमांड है. भारत में अभी ऐसी कुछ ही कारें बेची जाएंगी. शुरुआत में कार इंपोर्ट की जाएगी और अगले साल कंपनी इसे यहां असेंबल करना शुरू करेगी. केन का कहना है कि 2013 मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए काफी अहमियत रखता है. ए क्लास के लॉन्च के साथ कंपनी ने ग्लोबल पोर्टफोलियो से सबसे शानदार कारों को यहां लाने का इरादा फिर से जाहिर किया है. 2013 के पहले क्वार्टर में लग्जरी कार सेगमेंट में दूसरा स्थान हासिल करने वाली मर्सिडीज इस साल डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रही है. कंपनी को ए क्लास की महीने में 100–150 यूनिट बिकने की उम्मीद है. केन का कहना है कि आने वाले समय में मर्सिडीज बेंज इंडिया कई नई जेनरेशन की कॉम्पैक्ट कारें लाएगी. इनमें बी क्लास का डीजल वेरिएंट, सीएलए और जीएलए कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल होंगी. उन्होंने बताया कि हम फ्लैगशिप एस क्लास को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च करेंगे. हम भारत के लिए मीडियम साइज एसयूवी जीएलके के राइट हैंड ड्राइव वर्जन का इंतजार कर रहे हैं. उनका मानना है कि देश में 31,000 यूनिट का लग्जरी कार मार्केट अभी अपने शुरुआती दौर में है और 2020 तक इसके 2,80,000 यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है. हम कुल कार मार्केट में 4 फीसद की हिस्सेदारी रखेंगे. ■

**मर्सिडीज बेंज ए क्लास से देश के पैसेवाले युवाओं को टारगेट कर रही है. मर्सिडीज बेंज इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर केन ने कहा है कि ए क्लास के साथ मर्सिडीज बेंज भारत में कॉम्पैक्ट लग्जरी कार सेगमेंट पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है.**

## साइज में छोटा, काम बड़ा

**सीगेट केइस वीडियो डिस्क में 3.5 एचडीडी में 480 घंटे का हाई-डेफिनेशन (एचडी) वीडियो कंटेंट स्टोर किया जा सकता है.**

सीगेट ने नया सीगेट वीडियो 3.5 हार्ड डिस्क ड्राइव लॉन्च किया है. इसका हार्ड ड्राइव साइज सिर्फ 3.5–ईंच का है. सीगेट ने इस हार्ड डिस्क ड्राइव को खासतौर पर वीडियो एप्लीकेशन (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर या डीवीआर, सेट–टॉप बॉक्स या एसटीवी) और सर्विलांस सिस्टम में इस्तेमाल के मकसद से डिजाइन किया है. सीगेट के इस वीडियो डिस्क में 3.5 एचडीडी में 480 घंटे का हाई–डेफिनेशन (एचडी) वीडियो कंटेंट स्टोर किया जा सकता है. इतनी क्षमता वाला (खास कर वीडियो एप्लीकेशन के लिए) यह पहला ड्राइव है. सीगेट वीडियो 3.5 को ऐसा बनाया गया है, जो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर सकता है. इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है, जिससे इसे कम से कम बिजली और कुलिंग की आवश्यकता पड़ती है. ■

## आ रहा है सैमसंग गैलक्सी एस4 मिनी

सैमसंग ने गैलक्सी एस4 मिनी स्मार्टफोन का ऐलान कर दिया है. यह कंपनी के फ्लैगशिप फोन गैलक्सी एस4 का कॉम्पैक्ट वर्जन होगा. इसमें 4.3 इंच का क्यू–एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, जबकि गैलक्सी एस4 में 5 इंच का डिस्प्ले है. एस4 के 130 ग्राम वजन के मुकाबले इसका वजन 107 ग्राम होगा. इसमें 1.7 जीबी का ड्यूल कोर प्रोसेसर और 1.5 जीबी रैम होगी, जबकि एस4 में 1.9 गीगाहर्ट्ज क्वॉड कोर या 1.6 जीबी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है. यह ऐंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन 4.2.2 यानी जेली बीन पर चलेगा. गैलक्सी एस4 मिनी में पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे की तरफ 1.9 मेगापिक्सल कैमरा होगा, जबकि एस4 में मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है. एस4 के 2600 बैटरी के मुकाबले इसमें 1900 की बैटरी होगी. इसमें 8 जीबी इंटरनल मेमरी होगी, जिसमें यूज़र को इस्तेमाल के लिए लगभग 5 जीबी मेमरी मिलेगी, जबकि एस4 में 16, 32 और 64 जीबी के ऑप्शंस हैं. मेमरी को माइक्रो–एसडी कार्ड के जरिए 64 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा. एस4 मिनी दो रंगों–वाइट फ्रॉस्ट और ब्लैक मिस्ट–में मिलेगा. यह अलग–अलग मार्केट्स के मुताबिक 4जी एलटीई या 3जी एचएसपीए प्लस या 3जी ड्यूल सिम सपोर्ट करेगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

## सोनी का स्लिम टैबलेट

सोनी ने अपनी एक्सपीरिया रेंज को बढ़ाते हुए एक्सपीरिया टैबलेट जेड को भारत में लॉन्च किया. कंपनी का दावा है कि 6.9 मिलीमीटर पतला यह टैबलेट दुनिया का सबसे पतला टैबलेट है. इसकी क़ीमत 46,990 रुपए रखी गई है. डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट वाले इस टैबलेट में 1920 से 1200 पिक्सल वाला 10.1 ईंच का डिस्प्ले है. इसमें मोबाइल ब्राविया इंजन 2 है. यह स्नैपड्रैगन एस4 प्रो प्रोसेसर पर चलता है. यह 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वाड–कोर प्रोसेसर है. इसमें एड्रिनो 320 जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) और 2 जीबी रैम है. यह ऐंड्रॉयड 4.1 (जेली बीन) पर चलता है और 4.2 पर अपग्रेड किया जा सकता है. इसमें पीछे की तरफ 8.1 मेगापिक्सल और आगे की तरफ 2.2 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसकी इंटरनल मेमरी 16 जीबी है और इसमें 16 जीबी का मेमरी कार्ड भी लगाया जा सकता है. 495 ग्राम वजन वाला यह टैबलेट एचएसपीए प्लस और वाई–फाई वर्जन में काले रंग में उपलब्ध है. ■

## महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास ऐप

यह ऐप आपके एंड्रॉएड मोबाइल के 2.2 वर्जन और हाइयर वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसे आप फ्री में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं. इस ऐप को इंस्टॉल करने पर आप अपने मोबाइल को मात्र हिला कर इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं. इसके हॉट की में आप अपने भरोसे के लोगों का नंबर सेव कर एक साथ सभी को अलर्ट भी भेज सकते हैं. इतना ही नहीं, यह ऐप आपके जीपीएस लोकेशन को भी आपके भरोसे के कॉन्टैक्ट्स के पास भेज देता है. हां, ऐसे में आपको अपने फोन का जीपीएस फंक्शन ऑन रखना जरूरी हो जाएगा.

**फाइट बैक ऐप:** यह ऐप अपने आप में सबसे खास है. किसी भी खतरे के समय, यह ऐप जीपीएस, एसएमएस, लोकेशन मैप, जीपीआरएस, ईमेल और फेसबुक सभी अकाउंट का यूज कर एक साथ अलर्ट भेज देता है. इस ऐप का पैनिक बटन दबाते ही आपका अलर्ट आपके नजदीकी कॉन्टैक्ट्स के पास भेज दिया जाता है. ■

## बैटरी की लाइफ बढ़ाएगा बैटरी सेवर ऐप

आजकल के स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन, बहुत सारे ऐप्स, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ब्लूटुथ सब कुछ होता है. सब कुछ ओपन और यूज भी किया जाता है. लोग मल्टी–फंक्शनल होते जा रहे हैं. ऐसे में स्मार्टफोन यूजर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है– बार–बार बैटरी चार्जिंग की, लेकिन अब आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी ड्यू बैटरी सेवर एप्प फ्री ऐप से. इसे स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने से आप अपनी बैटरी लाइफ और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं. इस ऐप में तीन मोड दिए गए हैं–जेनरल मोड, लॉन्ग स्टैंड–बाई और स्लिप मोड.

जेनरल मोड– फोन के बेसिक नेटवर्क फंक्शन को खुला रखता है. इस मोड में नॉर्मल बैटरी सेव कर सकते हैं.

लॉन्ग स्टैंड– बाई–फोन डायलिंग और एसएमएस के अलावा, सभी फंक्शन को बंद कर बैटरी के स्टैंड–बाई टाइम को बढ़ा देता है.

स्लिप मोड– सोते समय स्मार्टफोन की घड़ी के अलावा, सभी फंक्शन बंद. इससे बैटरी के स्टैंड–बाई टाइम को मैक्सिमम बढ़त मिलती है. ■

## फेसबुक से करें मोबाइल रिचार्ज

अगर आप एयरसेल उपभोक्ता हैं, तो फेसबुक पर भी अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको एयरसेल के फेसबुक पेज पर जाना होगा. एयरसेल ने इंडिया में फेसबुक की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यह सुविधा शुरू की है. यह संभवतः पहली मोबाइल कंपनी है, जो फेसबुक को रिचार्ज प्लेटफार्म की तरह यूज कर रही है. ■

## जीएम-एसएआईसी का शेवरले लॉन्च

सेल युवा और सेल सेडान के बाद जीएम ने अपने जॉइंट वेंचर जीएम–एसएआईसी का तीसरा प्रोडक्ट शेवरले एंज्वॉय पेश किया है. पहली नज़र में ही यह बड़ी एमपीयू आपको पसंद आ जाएगी. हालांकि, इसके डिजाइन में कुछ भी अनूठा नहीं है. मोनो–बॉक्स डिजाइन में कोई फैंसी क्रीज नहीं है. फ्रंट को देख आपको किसी यूरोपीय गाड़ी का एहसास होता है. अट्रैक्टिव इंटीरियर दरवाजा चौड़ा हो, तो अंदर दाख़िल होना आसान होता है. बैठने पर आपको इसका स्पेशियस और हवादार केबिन आरामदेह लगेगा. इसके अंदर के पार्ट्स को ब्लैक लुक देने की कोशिश की गई है, जो आपको पसंद आएगी. फ्रंट सीट्स बहुत ही आरामदायक हैं. स्पीड कंसोल बेसिक है. लार्ज स्पीड के लेफ्ट में रेव काउंटर है, जबकि राइट में फ्यूल–कम–टेंपरेचर गेज है. तीसरी रो की सीट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच वाली सीट पूरी तरह से फोल्ड नहीं होती है. हालांकि, सीट्स काफी चौड़ी हैं. वहीं, पीछे की फ्लोर ऊंची होने से लंबे पैसेंजर्स को परेशानी हो सकती है.

**फ्रंट को देख आपको किसी यूरोपीय गाड़ी का एहसास होता है. अट्रैक्टिव इंटीरियर दरवाजा चौड़ा हो, तो अंदर दाख़िल होना आसान होता है.**

फैमिली ट्रांसपोर्टर एंज्वॉय में इंजन के दो ऑप्शंस हैं, पेट्रोल और डीजल. डीजल इंजन सीधे तौर पर सेल सेडान/हैच से लिया गया है. पेट्रोल ऑप्शन में 1.4 लीटर डीओएचसी यूनिट है, जिसका मैक्सिमम टॉर्क 131एन4400 आरपीएम है. इंजन काफ़ी रिफाइंड लगता है. इंजन को देखते हुए आपको बार–बार गीयर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है. ऐसे में पहाड़ी इलाक़ों में इसे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हालांकि, एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी. पेट्रोल के मुक़ाबले स्मार्टेक 1.3 लीटर यूनिट 77.5 पीएस4000 आरपीएम देती है. इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे 1750 के कम आरपीएम पर भी मैक्सिमम 188 का टॉर्क मिलता है. डीजल एंज्वॉय आपको ज़्यादा जीवंत लगेगी. सड़क उबड़–खाबड़ होने पर यह थोड़ी बंपी लग सकती है. इसकी ऊंचाई और वजन ठीक है. इसमें 175/70 आर14 का इस्तेमाल किया गया है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

### पैसे और ग्लैमर का खेल

# बुकी पास क्रिकेट फेल







नवीन चौहान
navinchaouhan@chauthiduniya.com

**भारतीय क्रिकेट जगत आज एक मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि फिक्सिंग के जाल में क्रिकेट एक बार फिर फंस गया है. इसीलिए खिलाड़ियों एवं खेल प्रशासन, दोनों की विश्वसनीयता पर इन दिनों सवाल खड़े हो गए हैं. एक और सवाल भारत में धर्म समझे जाने वाले क्रिकेट के अस्तित्व का भी पैदा हो गया है, इसलिए मामले की गंभीरता और ज़्यादा बढ़ जाती है.**

वर्ष 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, तब बीसीसीआई ने क्रिकेट को फुटबॉल की तरह प्रोफेशनल बनाने की बात कही थी. यहां क्रिकेट में ग्लैमर का तड़का लगाया गया था. फटाफट क्रिकेट के इस नए अवतार में मैदान में चीयरलीडर्स के साथ-साथ ऐसा बहुत कुछ था, जिसका क्रिकेट से कुछ लेना-देना ही नहीं था और न ही उससे क्रिकेट का कुछ भला होने वाला था. इसके बावजूद वे सारी चीजें क्रिकेट का हिस्सा बन गईं, खेल से ज़्यादा ध्यान उन्हीं पर दिया जाने लगा और यही सब धीमे जहर की तरह क्रिकेट को मारता रहा. कुछ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई, जो नई चकाचौंध एवं मस्ती के माहौल के चलते नक्कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हुई.

पिछले आईपीएल सीजन में एक समाचार चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कुछ खिलाड़ियों के नाम फिक्सिंग में सामने आने के बावजूद बीसीसीआई ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. परिणामस्वरूप, छठवें सीजन के आते-आते फिक्सिंग के आकाओं की पहुंच रणजी क्रिकेटरों से होते हुए एस श्रीसंत जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तक हो गई. ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने की चाह और लालच की वजह से नए खिलाड़ियों ने अपने जमीर से समझौता करना शुरू कर दिया. दरअसल, बीसीसीआई को आईपीएल के पदार्पण के बाद जितनी तेजी से अरबों रुपये का फ़ायदा हुआ, उससे भी ज़्यादा तेजी से क्रिकेट अपनी विश्वसनीयता खोता चला गया. भले ही आईपीएल के रास्ते क्रिकेट घर-घर तक पहुंच गया है, लेकिन क्रिकेट की जेंटलमेंस गेम वाली पहचान उससे कोसों दूर हो गई है. आईपीएल से पूर्व एवं वर्तमान क्रिकेटरों को कई तरह के फ़ायदे ज़रूर हुए हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि उनकी तुलना में क्रिकेट को अपनी साख ज़्यादा खोनी पड़ी. आईपीएल के आने के बाद खेल के अलावा, दूसरी वजहों से भी क्रिकेट सुर्खियों में रहने लगा. कभी मामला खिलाड़ियों एवं टीमों की खरीद-फरोख्त का रहा, तो कभी चीयरलीडर्स के कपड़ों का, लेकिन नुकसान हमेशा क्रिकेट का ही हुआ.दिल्ली पुलिस ने जब राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी एस श्रीसंत, अजीत चंदेलिया एवं अंकित चव्हाण सहित 26 लोगों को आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया, तो भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर भूचाल आ गया. उस वक्त आईपीएल का फाइनल होना बाकी था, उसके पहले इस तरह का विवाद उठना और उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एवं बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को मुंबई पुलिस द्वारा स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार करना बहुत ही शर्मसार करने वाला था. बात यहीं आकर नहीं रुकी, क्योंकि एन श्रीनिवासन पर बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने का दबाव पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा देने से साफ़ इंकार कर दिया. इसके बाद जब दबाव ज्यादा बढ़ा, तो जांच चलने तक जगमोहन डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया. हालांकि श्रीनिवासन ने अपना पद फिर भी नहीं छोड़ा. अंतरिम अध्यक्ष भी ऐसे व्यक्ति को चुना गया है और क्रिकेट की विश्वसनीयता वापस लाने की ज़िम्मेदारी दी गई है, जिस पर 1996 एवं 2006 के विश्वकप टूर्नामेंट में वित्तीय हेरफेर करने का आरोप लगा था और उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष थे. ऐसे में, निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम ही नज़र आती है. जैसा कि डालमिया के मामले में हुआ, वह सभी आरोपों से बरी हो गए थे. बाद में डालमिया ने उसे राजनीतिक रंजिश बताया था. मतलब यह है कि इसी तरह एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप के दौर के बाद आम क्रिकेट प्रेमी ही बेवकूफ बनेगा और क्रिकेट के ठेकेदार एक बार फिर अपना भला करने में जुट जाएंगे.

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम क्रिकेट प्रशासकों ने ही किया है. आज भी वे अपना कद क्रिकेट से बड़ा समझते हैं, जबकि उनकी पहचान ही क्रिकेट की वजह से है. 1983 में विश्वकप विजय के बाद भारत में क्रिकेट की तस्वीर ही बदल गई और इस बदलाव का असर सबसे ज़्यादा क्रिकेट प्रशासन पर पड़ा. दरअसल, इस दौरान ऐसा हुआ कि देश के क्रिकेट प्रशासन पर राजनीति हावी हो गई. नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के लोग देश में क्रिकेट के प्रशासक के रूप में सामने आने लगे और धीरे-धीरे खेल से ज़्यादा ध्यान व्यवसायिकता एवं आर्थिक पहलुओं की ओर हो गया. यह असर इतना ज़्यादा था कि 1983 में बंगलुरू में हुई बीसीसीआई की वार्षिक बैठक से बड़ौदा के महाराज फतेहसिंह गायकवाड़ सिर्फ़ इसलिए बाहर आ गए थे, क्योंकि बैठक में एक घंटे से ज़्यादा समय गुजरने के बावजूद वहां क्रिकेट पर कोई चर्चा ही नहीं हुई. इस घटना को तीस साल हो गए हैं, लेकिन बीसीसीआई फिर भी नहीं बदला. आज भी बीसीसीआई की कमान देश के राजनीतिक और उद्योग जगत के जाने-माने चेहरों के हाथों में है, जिन्होंने हमेशा शौकिया तौर पर ही क्रिकेट खेला. हैरानी की बात तो यह है कि क्रिकेट की तरक्की की कमान ऐसे लोगों के हाथों में थी, जिन्होंने कभी प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेला. ऐसे लोगों में एन श्रीनिवासन एवं शरद पवार का नाम सबसे ऊपर है, जिन्हें क्रिकेट के अच्छे-बुरे या उसकी छवि से कोई लेना-देना ही नहीं है. इस तरह के लोगों ने मिलकर क्रिकेट को मनोरंजन के साधन में बदल डाला और उसकी आत्मा (खेल भावना) को उससे अलग कर दिया. बहुत सारे लोगों के लिए क्रिकेट बहुत ही मनोरंजक और लुभावना ज़रूर हो गया है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बहुत घृणित हो गया है. भारतीय क्रिकेट अब किस ओर जा रहा है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. जिन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, वे अब भी मुंह बंद किए बैठे हैं. क्या पैसा और सिर्फ़ पैसा उनके द्वारा मुंह बंद रखने की वजह है? बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद की गिरफ्तारी की वजह से परिस्थितियां और भी घातक हो गई हैं. वहीं राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक राज कुंद्रा पर अपनी ही टीम पर सट्टा लगाने का आरोप लगने से दाल में काले की जगह, पूरी दाल ही काली दिखाई पड़ने लगी है.

हमारे देश की सरकार आग लगने के बाद ही कुआं खोदने का काम करती है. जब दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो उसके तुरंत बाद सरकार ने स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए नया क़ानून बनाने की बात कही. क्या सरकार अब तक भारतीय क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की जड़ें जमने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि 2010 में पहली बार स्पॉट फिक्सिंग का मामला इंग्लैंड में सामने आया था, जिसमें सलमान बट्ट समेत तीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम आए थे, जिन्हें इंग्लैंड की अदालत ने मुजरिम करार दिया था, लेकिन विडंबना यह है कि भारत सरकार तीन सालों तक कोई क़दम ही नहीं उठा सकी. दूसरी तरफ़ फिक्सिंग के इस खेल में अंडरवर्ल्ड का हाथ होने के प्रमाण भी दिल्ली पुलिस के पास हैं. इसी को देखते हुए आरोपियों के ख़िलाफ़ मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) लगा दिया गया है, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके. सरकार ने आज तक भारतीय ओलंपिक संघ की तरह बीसीसीआई को अपने ज्यूरीडिक्शन में लाने की पहल क्यों नहीं की? आज भी बीसीसीआई सूचना अधिकार क़ानून के दायरे में नहीं है. सरकार इस दिशा में कड़े क़दम क्यों नहीं उठा रही है. बीसीसीआई में भी बहुत गड़बड़ है, लेकिन क्रिकेट की पिच पर देश का सत्तारूढ़ पक्ष एवं विपक्ष, दोनों एक टीम में दिखाई देते हैं, इसी वजह से राज अंततः राज ही रह जाते हैं.

एक दौर था, जब भारत की जीत देश में कभी भी दीपावली वापस ले आती थी. खेलप्रेमी भारत की जीत का इंतज़ार करते थे. भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर सारा देश जश्न में डूब जाता था, लेकिन अब वैसा देखने को नहीं मिलता. 2011 की विश्वकप की जीत के बाद लोग जिस तरह घरों से बाहर निकले थे, मानो हर किसी ने दुनिया फतह कर ली हो, लेकिन किसी को उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है. क्रिकेट पैशन से प्रोफेशन में बदल गया है. यहां अब पैसा ही सब कुछ है. पैसे से ही खिलाड़ियों एवं टीमों की खरीद-फरोख्त होती है. क्रिकेट के रास्ते में फिक्सिंग की ऐसी दीवार आ खड़ी हुई है, जिससे पार पाना आसान नहीं दिख रहा है. सच तो यह है कि पैसे और ग्लैमर के इस खेल में बुकी पास और क्रिकेट फेल हो गया है. ■

## ग्लैमर वर्ल्ड भी बदनाम

**आईपीएल सट्टेबाजी की गंगा में न जाने किस-किस ने डुबकी लगाई. बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियों, बिंदु दारा सिंह और शिल्पा शेट्टी ने भी पैसा बनाने का मौक़ा नहीं छोड़ा. बिंदु दारा सिंह के बाद शिल्पा शेट्टी का नाम सट्टेबाजी में उछला और दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद अब उनके पति राज कुंद्रा ने भी सट्टेबाजी की बात स्वीकार की है. संभव है, आने वाले दिनों में फिल्म जगत की कुछ और बड़ी मछलियों के नाम सामने आएं, लेकिन इस खुलासे के बाद यह तो तय हो गया है कि बॉलीवुड की इन नामी हस्तियों का कद हकीकत में कितना छोटा है. हो सकता है, इन्हें लगता हो कि बदनाम हुए, तो क्या, नाम न हुआ!** ■

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

अभिनेत्री ज़िया ख़ान ने 3 जून की रात लगभग 11 बजे अपने मुंबई केजुहू स्थित फ्लैट में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली.



## तन्हाई मौत है या सब

# ज़िया खां की नि:शब्द खुदकुशी

**बोल्ड, ब्यूटिफुल, बिंदास और मॉडर्न खयालात वाली इस कम उम्र की अदाकारा ने खुदकुशी क्यों की और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसी की पड़ताल कर रही हैं प्रियंका तिवारी.**

**शायद दर्द ए गम और तन्हाई रास नहीं आई ज़िया खां को!**

आज पूरा बॉलीवुड ज़िया खान की मौत पर दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर एक सवाल यह भी उठता है कि आख़िर ज़िया जैसी बिंदास और मॉडर्न खयालात वाली लड़की, जो ज़िंदगी से प्यार करती थी, जिसके कुछ सपने थे, जिसने पहली फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ किया, जिसे अपने से दुगने से भी ज़्यादा उम्र के पुरुष के साथ इंटीमेंट सीन देने में भी कोई ऐतराज नहीं था, वह अचानक डिप्रेशन में क्यों आ गई. और वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण उन्हें अंतत: खुदकुशी करनी पड़ी. दरअसल, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उन्होंने खुदकुशी करने से पहले शराब पी रखी थी. उन्होंने पफोन पर सुरज पंचोली से बात भी की थी.

गौरतलब यह है कि वर्ष 2007 में अमिताभ बच्चन के साथ जिया की पहली फिल्म आई थी नि:शब्द. इसके बाद वह आमिर के साथ गजनी और 2010 में और अक्षय कुमार के साथ फिल्म हाउसफुल में दिखीं. उन्होंने कुल तीन फिल्में कीं और तीनों ही बड़े स्टार्स के साथ. हालांकि वर्ष 2010 के बाद वह किसी फिल्म में नहीं दिखीं. ऐसा नहीं था कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठी थीं, बल्कि इस बीच वह फिल्मों के लिए जी-जान से कोशिश कर रही थीं. और इसीलिए लगातार ऑडिशन भी दे रही थीं, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा था. हालांकि अचानक उन्हें मौका मिला केन घोष की फिल्म चांस पे डांस में शाहिद कपूर के अपोजिट काम करने का. इस फिल्म के मिलने के बाद वह काफ़ी उत्साहित थीं. वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन यह फिल्म भी उनके हाथ से निकल गई. उनकी जगह जेनेलिया डिसूजा को ले लिया गया.

अब सवाल यह उठता है कि क्या काफ़ी कम उम्र में स्टार कलाकारों के साथ काम करने की वजह से जिया के नखरे तो नहीं बढ़ गए थे! वह रोल में तोल-मोल करने लगी थीं, क्योंकि हाल ही में जिस फिल्म का ऑडिशन देने वह हैदराबाद में गई थीं, उसमें उनकी भूमिका के लिए वेट बढ़ाने को कहा गया था, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं हुईं. यह हम सभी जानते हैं कि फिल्मों में रोल के हिसाब से लुक्स चेंज करना ही पड़ता है. अमिताभ से आमिर तक सभी ने यह किया है. या फिर बात कुछ और थी! फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को फिल्मों में रोल देने के बहाने कई तरह से शोषण किया जाता है. आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समझौते करने ही पड़ते हैं. यह इंडस्ट्री का दस्तुर है. हम तो सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं ज़्यादा घिनौनी है. आख़िर क्या वजहें थीं कि जिया को फिल्में नहीं मिल रही थीं. हालांकि यदि उनकी फिल्मों को देखा जाए, तो नि:शब्द के बाद अपनी बाकी दोनों ही फिल्मों में वह सहायक अभिनेत्री की भूमिका में थीं. यह भी हो सकता है कि जिया रोल्स को लेकर बहुत डिमांडिंग नहीं थीं. एक कारण यह भी हो सकता है कि इंडस्ट्री में काम न मिलने से वह बुरी तरह निराशा से घिर गई थीं. उनकी मां ने बातचीत के दौरान कहा कि वह इतनी मायूस हो गई थी कि वह इस प्रोफेशन को बदलने के लिए भी तैयार थी और इसीलिए कुछ समय से वह इंडस्ट्री छोड़कर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने की प्लानिंग कर रही थीं.

एक और बात गौर करने लायक यह भी है कि वर्ष 2007 में कई और अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री में दस्तक दी, जिनमें सोनम कपूर ने सांवरिया और दीपिका ने ओम शांति ओम से अपना करियर शुरू किया. ये दोनों आज टॉप पर हैं, लेकिन इनके रहते भी ज़िया को नोटिस किया गया और उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फिमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला. ज़ाहिर है, उन्हें न सिर्फ नोटिस किया गया, बल्कि उनके काम को सम्मानित भी किया गया. तात्पर्य यह है कि वह एक अच्छी अभिनेत्री थीं. उनके काम को सम्मान दिया गया और फिल्म फेयर अवॉर्ड देकर उनकी उम्मीदें और बढ़ाई गईं. इतनी तेजी से ऊपर जाने वाली जिया के करियर का ग्राफ बाद में इतना कैसे गिर गया कि उन्हें फिल्में ही नहीं मिल रही थीं, यह बताना फिलहाल मुश्किल है.

कहा जाता है कि प्रतिभाशाली होने के साथ ही साथ सामाजिक होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है. फिल्मों में भाई भतीजावाद काफ़ी चलता है, यह तो जग जाहिर है, लेकिन जिया जैसी लड़की जिसका अपना अलग अंदाज़ था, ज़िंदगी को जीने का, वह कभी बहुत चर्चा में नहीं रहीं, न ही वह अपने आप को चर्चा में रखने के लिए कभी बढ़ चढ़ कर सामने आईं. दरअसल, उन्होंने एक तरह से गुमनाम ज़िंदगी से समझौता कर लिया. उनके साथ की ही अभिनेत्रियों का कई पुरुष कलाकारों के साथ नाम जोड़ा जाता रहा, लेकिन जिया के साथ कभी इस तरह की कोई गॉसिप नहीं रही. हालांकि एक दो विवाद उनके साथ भी जुड़े, लेकिन उन्होंने बहुत ही सरल तरीक़े से उनका खंडन भी कर दिया. वह अलग थीं और उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था. वह एक अच्छी डांसर और एक अच्छी सिंगर भी थीं.

**अभिनेत्री ज़िया ख़ान ने 3 जून की रात लगभग 11 बजे अपने मुंबई केजुहू स्थित फ्लैट में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली. उस वक्त जिया घर में अकेली थीं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मात्र 25 साल की उम्र में ज़िया द्वारा उठाए गए इस क़दम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.**

अभिनेत्री ज़िया ख़ान ने 3 जून की रात लगभग 11 बजे अपने मुंबई केजुहू स्थित फ्लैट में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली. उस वक्त जिया घर में अकेली थीं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मात्र 25 साल की उम्र में ज़िया द्वारा उठाए गए इस क़दम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने अपनी मौत से कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि कभी भी आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता और उसी वक्त की तलाश में आप भटकते रहते हैं. मुझे अपने विचार और सपनों को बटोरने के लिए छुट्टी की ज़रूरत है. उनके इस ट्वीट से लगता है कि जेहनी तौर पर बेहद भावुक थीं वह. उनका नाम आदित्य पंचोली के बेटे सूरज से जोड़ा जा रहा है. अपनी मौत से पहले काफ़ी समय तक उन्होंने सूरज से बात की थी. उनके रिश्ते में कुछ तनाव चल रहा था. मतलब साफ़ है कि उनके जीवन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था.

ज़िया ने बॉलीवुड के लिए अपना बहुत कुछ खोया, लेकिन अफसोस! बॉलीवुड ने ज़िया को नहीं अपनाया. सबसे पहले उन्होंने अपना नाम खोया. जिया का असली नाम नफीसा खान चौधरी था. उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था और शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में. वह न्यूयॉर्क के फिल्म इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रही थीं, तभी उन्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्म नि:शब्द का ऑफर मिला. उन्होंने फिल्म के लिए अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी. हालांकि महेश भट्ट ने उन्हें सबसे पहले फिल्म तुम सा नहीं देखा का ऑफर दिया था, लेकिन रोल काफी मैच्योर होने के कारण ज़िया ने ठुकरा दिया, जिसे फिर बाद में दिया मिर्जा ने किया. वे अपनी मां केसाथ मुंबई केएक घर में पिछले तीन साल से रह रही थीं.

जिया के डिप्रेशन की कई वजहें हो सकती हैं. दरअसल, वह जुहू स्थित सागर संगीत अपार्टमेंट में रहती थीं. जिस फलैट में थीं, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. वह तीन साल से मुंबई में रह रही थीं और काफी समय से उनके पास काम नहीं था. ऐसे में फाइनांशियल क्राइसिस में भी चल रही थीं वह. इसके अलावा, वह अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से भी काफी डिप्रेशन में थीं. गुस्सैल मिजाज की थीं वह. काम न मिलने के कारण पिछले कुछ समय से उनका चिड़चिड़ापन बढ़ गया था.

## आमिर की स्टेप सिस्टर जिया

जब ज़िया ने बॉलीवुड में क़दम रखा था, तब यह चर्चा आम थी कि जिया आमिर की स्टेप सिस्टर हैं. ऐसा इसलिए भी कहा जाता था, क्योंकि जिया की मां अभिनेत्री राबिया आमिन और आमिर के पिता ताहिर हुसैन काफ़ी क़रीबी मित्र हैं. हालांकि इस बात का खंडन करते हुए ताहिर हुसैन ने कहा था कि वे और राबिया सिर्फ़ अच्छे दोस्त हैं. ज़िया ने भी इस बात का खंडन कर दिया कि आमिर से उनका कोई रिश्ता नहीं है. बाद में वह फिल्म गजनी में आमिर के अपोजिट दूसरी अभिनेत्री के रूप में दिखीं.

## नाम के साथ विवाद

फिल्मों में आने से पहले जिया ने अपना नाम ज्योतिषी से बाकायदा संपर्ककर के बदल लिया था. उन्होंने अपना नाम नफीसा ख़ान से बदल कर ज़िया ख़ान कर लिया था. तब ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी थी कि वह दुबारा अपना असली नाम प्रयोग नहीं करेंगी. लेकिन बॉलीवुड में फिल्में न मिलने के कारण कुछ समय से वह अपना असली नाम नफीसा दुबारा प्रयोग करने लगी थीं.

## ग्लैमर वर्ल्ड के और भी सितारों ने की खुदकुशी

टॉप मॉडल विवेका बाबाजी ने भी वर्ष 2010 में अपने अपार्टमेंट में सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली. वह भी अपनी मौत से कुछ समय पहले डिप्रेशन में चल रही थी. साउथ की जानी मानी अभिनेत्री सिल्क स्मिता ने कम उम्र में ही काफ़ी नाम और पैसा कमाया, लेकिन बाद में इंडस्ट्री के दोहरे रवैए के कारण उन्हें फिल्में मिलनी कम होने लगीं. पैसे की कमी और घोर निराशा के बीच एक दिन सिल्क ने अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली. जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस कुलदीप रंधावा ने भी अपने जुहू के अपार्टमेंट में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह जीवन के मुश्किलों के साथ समझौता कर पाने में असमर्थ हैं. मॉडल और वीजे नफीसा जोजफ ने भी वर्ष 2004 में सुसाइड कर ली. उनकी मौत के बाद उनके घरवालों ने बताया कि वह कुछ समय से डिप्रेशन में चल रही थीं. ■

# चौथी दुनिया

## बिहार झारखंड

17 जून–23 जून 2013

www.chauthiduniya.com

### यह नीतीश के अहंकार की हार है

# टूट गया तिलिस्म

***महाराजगंज में जनता ने जात पात से ऊपर उठ कर वोटिंग किया और प्रभुनाथ सिंह को जिताया. इससे अब साफ़ हो गया है कि जनता अब विकास चाहती है...***


सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com


महाराजगंज की जनता ने प्रभुनाथ सिंह को अपना नया महाराज चुन लिया है. जिस सामाजिक और राजनीतिक ताने–बाने के तहत प्रभुनाथ सिंह के सिर पर यह ताज रखा गया है, वह बिहार में आगे होने वाली राजनीति की दशा एवं दिशा बहुत हद तक दिखा रही है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि महाराजगंज उपचुनाव महज एक सीट के लिए जनादेश पाने की कवायद भर नहीं थी, बल्कि इस चुनाव ने यह तय कर दिया है कि काल्पनिक सोशल इंजीनियरिंग और झूठ की बड़ी–बड़ी कहानियों के दिन अब लद चुके हैं. जनता ज़मीन पर विकास चाहती है, इज्जत और सम्मान चाहती है. जिस पर भरोसा कर जनादेश दिया, अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो जनता लाख नाराज़गी के बावजूद दूसरे विकल्प को आजमाने से भी नहीं चूकेगी. महाराजगंज की जनता ने 1 लाख, 37 हज़ार वोटों से राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के माथे पर विजय तिलक लगाकर यह ऐलान कर दिया कि अगर विकास और आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, तो जनता किसी का भी घमंड तोड़ कर रख देगी.

विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनावों में एनडीए की लगातार जीत ने बिहार में विपक्ष को लगभग पस्त करके रख दिया था. कल्याणपुर में कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन वह भी टूट गई. ऐसे में महाराजगंज ही वह मैदान था, जहां से दरअसल, विपक्ष की संजीवनी की तलाश पूरी हो सकती थी. गांधी मैदान में सफल रैली के बाद लालू प्रसाद के लिए महाराजगंज की लड़ाई में अपना सबकुछ झोंकने का वक्त था. लालू ने भी जनता के मिजाज को समझने में कोई चूक नहीं की और अपनी और अपनी पार्टी की पूरी ताक़त इस चुनाव में लगा दी. प्रभुनाथ सिंह जैसे प्रत्याशी ने लालू का काम काफ़ी आसान कर दिया.

दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार ने पीके शाही को प्रत्याशी बनाकर बड़ी रणनीतिक भूल कर दी. यह बात साबित भी हो गई, क्योंकि भूमिहार बहुल इलाक़ों में भी पीके शाही पिछड़ गए. वहां के स्थानिय लोगों का मानना है कि भूमिहारों में पीके शाही घुलमिल नहीं पाए. नीतीश के इस कदम से दूसरा नुक़सान यह हुआ कि राजपूत वोटों का जबर्दस्त ध्रुवीकरण राजद के पक्ष में हो गया. हुआ यह कि जो राजपूत प्रभुनाथ सिंह को पसंद भी नहीं करते थे, उनकी सहानुभूति उनके प्रति हो गई. दूसरी सबसे बड़ी बात जो जदयू के ख़िलाफ़ गई, वह यह थी कि नीतीश कुमार से लेकर दूसरे एवं तीसरे लाइन के नेता भी यहां घमंड और अहंकार की भाषा बोलने लगे. सीन यह था कि जदयू ने पहले दिन से ही यह मान लिया था कि पीके शाही यहां डेढ़ से दो लाख वोट से जीतेंगे. भरोसा प्रशासनिक एवं सोशल इंजीनियरिंग पर किया जा रहा था. इसके अलावा, विपक्ष के पस्त हौंसले ने भी जदयू में अहंकार भर दिया.

एक नेता हैं, शैलेंद्र प्रताप, जो हाल ही में लोजपा से जदयू में गए हैं. उन्होंने बयान दे दिया कि मैं ललकार दूंगा, तो प्रभुनाथ सिंह हार जाएंगे. एक दो मुक़दमे भी प्रभुनाथ सिंह पर किए गए. जिन लोगों पर आज तक कोई मुक़दमा भी नहीं हुआ, उन्हें भी ज़िलाबदर कर दिया गया. यानी एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक तानाशाही के माहौल में जदयू यहां चुनाव लड़ रहा था. सैकड़ों विधायक एवं मंत्री यहां तीन दिन तक लगातार नीतीश कुमार के साथ प्रचार में लगे रहे, लेकिन जनता ने लगता है यह ठान ही लिया था कि इस बार घमंड तोड़ देना है, तो उन्होंने तोड़ ही दिया. इस चुनाव को जातीय गोलबंदी के आइने में देखना पूरी तरह ठीक नहीं होगा. मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि राजपूत, यादव, मुसलमान एवं पासवान ने मिलकर वोट दिया और राजद को जीता दिया, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. आकंड़े बताते हैं कि प्रभुनाथ सिंह अलग अलग कारणों से सभी समुदायों का अधिकांश वोट पाने में सफल रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो वह छह के छहों विधानसभा में लीड करने में सफल नहीं होते. गोरेयाकोठी में राजद को 71813 तो जदयू को 41637 वोट ही मिले. इसी तरह महाराजगंज में राजद को 54556, एकमा में 55770, मांझी में 67915, बनियापुर में 68715 और तरैया में 62667 यानी कि कुल 381436 वोट मिले. जदयू को महाराजगंज में 48904, एकमा में 41176, मांझी में 37641, बनियापुर में 41943, तरैया में 33023 यानी कुल 244324 वोट मिले. मतलब भूमिहार, कुशवाहा और अतिपिछड़ा बहुल इलाक़ों में भी प्रभुनाथ सिंह का दबदबा रहा.

**विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनावों में एनडीए की लगातार जीत ने बिहार में विपक्ष को लगभग पस्त करके रख दिया था. कल्याणपुर में कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन वह भी टूट गई. ऐसे में महाराजगंज ही वह मैदान था, जहां से दरअसल, विपक्ष की संजीवनी की तलाश पूरी हो सकती थी. गांधी मैदान में सफल रैली के बाद लालू प्रसाद के लिए महाराजगंज की लड़ाई में अपना सबकुछ झोंकने का वक्त था.**

नीतीश कुमार, जो अतिपिछड़ा एवं महादलित वोटों का दावा करते आए हैं, इसकी पोल महाराजगंज की जनता ने खोल दी. यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह भी बन गई है. सहयोगी भाजपा सवाल कर रही है कि कहां गए अतिपिछड़ा और महादलित के वोट महाराजगंज में. मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि एनडीए की बैठक बुलाई जाए और हार की समीक्षा भी की जाए. दूसरी तरफ़ पीके शाही कहते हैं कि गठबंधन पर हमें फिर से विचार करना होगा, लेकिन इन सबके बीच उत्साहित लालू प्रसाद कहते हैं कि यह नीतीश कुमार के अहंकार की हार है. महाराजगंज की जनता ने जो संदेश दिया है, वह पूरे बिहार में जाएगा और राजद गठबंधन लोकसभा की सभी चालीस सीटों पर जीत दर्ज करेगा. यह सही है कि महाराजगंज की जीत ने लालू प्रसाद और उनके गठबंधन में जोश भर दिया है, लेकिन जोश के साथ अगर होश बरक़रार रहेगा, तभी उनका दावा ज़मीन पर उतर पाएगा. वरना जनता तो किसी का घमंड तोड़ने की ताक़त रखती है. ■

# भूख से मर रहे लोग, सड़ रहा है अनाज


ज्योति कुमारी

feedback@chauthiduniya.com


**लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन दरभंगा में एक लाख, छह हज़ार क्विंटल धान सड़ रहा है. विभागीय मंत्री श्याम रजक से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जल्द ही जांच होगी...**

दरभंगा ज़िले में कोसी, कमला और बागमती जैसी नदियों के कारण कुछ ऐसे इलाक़े बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां सरकार की विकास योजनाएं फेल हैं. अंत्योदय और अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं के तहत बेहद ग़रीब लोगों तक पीडीएस के माध्यम से पहुंचने वाला अनाज भ्रष्टाचार की सुरसा के मुंह में चला जाता है. ऐसे में इन इलाक़ों में सरकार के दावों की हवा निकल जाती है. सच तो यह है कि यहां लोग पेट की आग बुझाने के लिए लोग घोंघा–सितुआ पर निर्भर हैं. विडंबना यह है कि घोंघा–सितुआ पकड़ने के लिए भी ग़रीब जान को ख़तरे में डालकर पानी में उतरते हैं. उसी ज़िले के हायाघाट प्रखंड के सुरहाचट्टी में लापरवाही और बेइंतजामी का एक दूसरा ही तस्वीर देखने को मिला. यहां एसएफसी के अधिकारियों की लापरवाही से एक लाख, छह हज़ार क्विंटल धान खुले खेत में सड़ रहा है और बोरों में ही धान अंकुरित भी हो रहा है. जब चौथी दुनिया ने मामले की गहराई से पड़ताल की, तो एसएफसी के अधिकारियों के कई कारनामे उजागर हुए. मामला सूबे के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक तक पहुंचा है. मंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा को जांच के निर्देश दे दिए हैं.

राज्य सरकार ने पिछले साल हर प्रखंड में गोदाम बनाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन कई कारणों से अधिकतर प्रखंडों में गोदाम नहीं बन सके. ऐसे प्रखंडों के लिए किराए पर गोदाम लेकर हर हाल में अनाज को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी एसएफसी को दी गई. दरभंगा का हायाघाट एक ऐसा ही गोदामविहीन प्रखंड है. स्थानीय सिधौली पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र राय कहते हैं कि ये अनाज पैक्सों के माध्यम से किसानों से ख़रीदा गया था. सरकार गोदाम का किराया भुगतान करती है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज रखने के लिए यहां कभी गोदाम बना ही नहीं. इस धान को चावल मिलों में भेजा जाना था, वहां से चावल वापस आता और और एफसीआई को भेज दिया जाता है. एफसीआई से यही चावल पीडीएस के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचता है. योगेंद्र राय ने सवाल खड़ा किया कि सड़े हुए और अंकुरित धान का चावल कैसे बनेगा? सिधौली गांव के कई किसानों ने एसएफसी में फैले बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. यहां के लोगों का कहना है कि जिस स्थानीय व्यक्ति से गोदाम समेत यह ज़मीन किराए पर ली गई है, उसके पास गोदाम के नाम पर दो कमरों का एक निर्माण है. दिखावे के लिए कुछ अनाज उन कमरों में रखा जाता है और बाक़ी का अनाज बाहर खुले में ही पड़ा रहता है. इस साल का यह एक लाख, छह हज़ार क्विंटल धान पिछले तीन महीनों से पड़ा सड रहा है. यह धान किसानों के ख़ून–पसीने से उगाया गया है. इन तीन महीनों में यह धान चार बार से ज़्यादा भीग चुका है. खुले खेत में रखे होने की वजह से ज़मीन से यह नमी सोखता है और ऊपर की बारिश भी इसे बुरी तरह से भिगो रही है. ऐसे में अगर कुछ दिन और धान भीगेगा, तो अनाज का पूरी तरह से सड़ जाना तय है. लोगों ने यह भी बताया कि हर साल ज़िले में भूख से मरने वालों की संख्या अच्छी ख़ासी होती है. अगर उन तक छटाक भर अनाज भी यदि पहुंचा दिया जाए, तो वे मरने से बच जाएंगे. लेकिन जब भूख से मरने की कोई घटना मीडिया के माध्यम से सामने आती है, तब अधिकारी उसे सामान्य मौत साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं. दरअसल, हद तो तब हो जाती है, जब अनाज बांटने के काम को भी सरकारी अधिकारी–कर्मी एक दूसरे पर टाल कर अपनी जान छुड़ा लेते हैं और इसीलिए ग़रीबों तक अनाज नहीं पहुंच पाता. ऐसे ही अधिकारियों–कर्मियों की वजह से अनाज सड़ जाता है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि भ्रष्ट तंत्र इतना ढीठ है कि उसे किसी कार्रवाई का डर नहीं, क्योंकि अनाज को सुरक्षित रखने की जवाबदेही जिन लोगों पर है, वे ख़ुद ही लापरवाह और भ्रष्ट हैं. इस बारे में जब एसएफसी की ज़िला प्रबंधक रंजना कुमारी से पूछा गया, तो उनका जवाब अवाक कर देने वाला था. उन्होंने विभाग को भेजी जा चुकी एक रिपोर्ट हमें दिखाई, जिसमें यह दर्ज़ था कि यह एक लाख, छह हज़ार क्विंटल धान चावल मिलों को भेजा जा चुका है, मतलब अनाज सुरहाचट्टी में है ही नहीं. आपको बता दें कि ये वही प्रबंधक हैं जिनके कार्यकाल में ख़ुद


(शेष पृष्ठ 20 पर)


**राज्य सरकार ने पिछले साल हर प्रखंड में गोदाम बनाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन कई कारणों से अधिकतर प्रखंडों में गोदाम नहीं बन सके. ऐसे प्रखंडों के लिए किराए पर गोदाम लेकर हर हाल में अनाज को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी एसएफसी को दी गई. दरभंगा का हायाघाट एक ऐसा ही गोदामविहीन प्रखंड है.**

चौथी दुनिया



गांधीवादी अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया ने उनसे मुलाकात की और महात्मा गांधी एवं आश्रम से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी.

## » एक नज़र «

### शांतनु ने मारी बाजी

सीतामढ़ी ज़िले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में रहने वाले चिकित्सक डॉ. सुजीत कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा शर्मा के पुत्र शांतनु ने ओलंपियाड परीक्षा में बाजी मार ली. उनकी सफलता पर चिकित्सकों के अलावा, स्थानीय लोगों में भी हर्ष है. शांतनु स्थानीय डीएवी स्कूल में कक्षा 9 के छात्र हैं. उन्होंने कठिन परिश्रम की बदौलत जहां कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं राज्य स्तर पर उन्हें 67वां स्थान प्राप्त हुआ. शांतनु की सफलता पर उनकी मां सह लायंस क्लब एक्टिव पुपरी की अध्यक्ष अपर्णा शर्मा समेत आसपास के लोग भी खुश हैं.

### सभापति के ख़िलाफ़ मोर्चा

सीतामढ़ी : पिछले एक साल का समय गुजर जाने के बाद भी नगर परिषद की बोर्ड में पारित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब को उप सभापति समेत तक़रीबन आधा दर्जन वार्ड पार्षदों ने गंभीरता से लिया है. पार्षद नगीना देवी के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए नगर परिषद के उप सभापति युगल किशोर प्रसाद ने सभापति की कार्य प्रणाली पर जमकर प्रहार किया. कहा कि अगर समय रहते कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया गया, तो शहर के विकास को लेकर आंदोलन किया जाएगा. मौक़े पर पार्षद डॉ. अमरनाथ गुप्ता, धनंजय कुमार, मंजू देवी एवं इंदिरा गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे. *-गोविंद कुमार*

### लड़कियों का सहारा आर्या संस्थान

आर्या संस्थान धनबाद ने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र में पूरे धनबाद में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. सैकड़ों हुनरमंद बच्चियों के सपनों के उड़ान को अमलीजामा पहनाने के लिए संस्थान ने कई काम किए हैं. संस्थान की निदेशिका रीना कोठारी की कर्तव्यनिष्ठा एंव कंप्यूटर शिक्षा के साथ-साथ हस्तकला, साड़ियों की एम्ब्रॉयडरी एवं पिको फॉल लगाने के आधुनिक तरीक़े, कपड़ों पर आकर्षक कढ़ाई के एक से बढ़कर एक लाजवाब प्रस्तुतिकरण अभिभावकों को काफ़ी पसंद आ रहा है. रीना कोठारी साढ़े तीन साल से इस मिशन में लगी हुई हैं. *-हैदर अली*

## सलाखों के पीछे पहुंचा बब्लु दुबे

# आमजनों को राहत

**ख़ौफ़ का पर्याय बन चुके बब्लु दुबे को पुलिस ने आख़िरकार काफ़ी मशक्कत के बाद सलाखों के पीछे भेज ही दिया, लेकिन कैसे संभव हुआ यह?**

इंतेजारुल हक/डीएन कुशवाहा feedback@chauthiduniya.com

उत्तर बिहार एवं नेपाल में आतंक मचाने वाले दुर्दांत अपराधी बबलु दुबे ने अपने चाचा की हत्या कर अपराध की दुनिया में क़दम रखा था. इसके बाद गांव के ही एक दबंग एवं संपन्न कुमुद सिंह नाम के एक व्यक्ति को उसने अपनी बहन की शादी के लिए ज़मीन बेचा, लेकिन रजिस्ट्री के बाद तयशुदा राशि नहीं मिलने पर बौखलाए बब्लु दुबे ने कुमुद सिंह की बोलेरो लूट ली और उसके बाद उन पर जानलेवा हमला भी किया. इसके बाद बब्लु दुबे और खुंखार होता गया. उसने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज के साथ-साथ न केवल नेपाल में अपना जाल बिछाया, बल्कि एक के बाद एक आपराधिक गतिविधियों को अंजाम भी देता गया. कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत सिसवा खरार गांव निवासी कुख्यात अपराधी बब्लु, उसके दोस्त एवं मिस्त्री कमालुद्दीन के बीच मोबाइल पर बातचीत ने पुलिस की राह और आसान कर दी. बताया जाता है कि कमालुद्दीन को बब्लु दुबे के नेपाल यात्रा की जानकारी होते ही फोन पर बात होने लगी और दोस्ती हो गई. पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान विनय कुमार एवं रक्सौल के डीएसपी जितेंद्र पांडेय तथा नेपाल पुलिस की संयुक्त दबिश की जानकारी शायद कमालुद्दीन को नहीं थी. इस कारण बब्लु दुबे के नाम पर वे काठमांडू में अपना धाक जमाने लगे. इसकी भनक नेपाल पुलिस को लगी और कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर काठमांडू जेल भेज दिया गया. जानकार बताते हैं कि जेल जाने के बाद भी उसका टेलीफोनिक संपर्क बब्लु दुबे से होता रहा. उक्त फोन कॉल लोकेशन डिटेल्स के आधार पर बब्लु दुबे को नेपाल पुलिस द्वारा काठमांडू स्थित सानोपाइला से पांच मोबाइल एवं 5 नेपाली सीम के अलावा, 1,77,000 नेपाली तथा 60,000 भारतीय रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. जानकार बताते हैं कि जेल में रहने के दौरान ही उसने बिहार पिपुल्स लिबरेशन आर्मी नामक संगठन की स्थापना की और ज़िले भर से चुनिंदा लुटेरों को अपने संगठन का सदस्य बनाया. बीते 28 अप्रैल, 2013 को रामगढ़वा के तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर गोलीबारी एवं संगठन के नाम से पर्चे फेंके. रामगढ़वा स्थित अमन ईंट उद्योग के संचालक नूरुल्लाह हाफी के मुंसी तथा रामगढ़वा के भलुवहिया गांव निवासी 65 वर्षीय जंगबहादुर हाजरा पर 18 मई की सुबह गोली चलाकर दहशत फैला दी गई. पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर किराना व्यवसायी राजकिशोर सिंह एवं पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाने के पूर्व मुखिया जय नारायण प्रसाद की हत्या, पिछले साल बेतिया, गोपालगंज के बीच गंडक पर पूर्व निर्माण में लगी कंपनी के दो कर्मियों को दिन-दहाड़े भून डालने और हत्या करने की ज़िम्मेदारी ख़ुद उसने ली थी. पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाना

> **»» जेल जाने के बाद भी उसका टेलीफोनिक संपर्क बब्लु दुबे से होता रहा. उक्त फोन कॉल लोकेशन डिटेल्स के आधार पर बब्लु दुबे को नेपाल पुलिस द्वारा काठमांडू स्थित सानोपाईला से पांच मोबाइल एवं 5 नेपाली सीम के अलावा, 177000 नेपाली तथा 60000 भारतीय रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.**

क्षेत्र के पूर्व मुखिया जवाहर प्रसाद को सरेआम गोलियों से भून डाला था. दुबे ने पूर्वी चंपारण के कई प्रखंड के व्यवसायियों, अधिकारियों तथा सभ्रांत लोगों से नेपाल के मोबाइल नंबर से रंगदारी की मांग की थी, जिनमें 28 नवंबर, 2012 को कोचिंग संचालक सुबोध कुमार से 10 लाख, 29 नवंबर 2012 को आंगनशूट हाउस के मालिक निखिल कुमार अग्रवाल से 10 लाख, 13 फरवरी, 2013 को डॉ. अशोक कुमार गिरी से 10 लाख, 4 फरवरी 2013 को डुमरियाघाट हुसैनी के शिक्षक शिवपूजन प्रसाद से 10 लाख, 16 फरवरी 2013 को डॉ. दिलीप कुमार से 10 लाख, 18 फरवरी, 2013 को अरेराज के सीडीपीओ किरण बाला से 10 लाख, 19 फरवरी, 2013 को पहाड़पुर के सीडीपीओ मीरा कुमारी से 10 लाख, 20 फरवरी, 2013 को पहाड़पुर के प्रमुख मधुबाला सिंह के पुत्र कुमार मनीष उर्फ निक्कू सिंह से 10 लाख, 13 फरवरी को ही सुगौली के सीडीपीओ पल्लवी से 10 लाख, 29 मार्च 2013 को डुमरियाघाट के ईंट भट्ठा व्यवसायी अमरेंद्र सिंह से 10 लाख, 13 अप्रैल 2013 को ढाका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से 15 लाख, 21 अप्रैल 2013 को रक्सौल हिरो बाइक एजेंसी के मालिक मो. कलाम से 20 लाख, 13 मई 2013 को आदापुर के राइस मिल के मालिक मदन प्रसाद से 25 लाख, 15 मई 2013 को रामगढ़वा अमन ईंट उद्योग के मालिक मो. नूरुल्लाह हाफी से 5 लाख रंगदारी की मांग की थी.

गौरतलब है कि बब्लु दुबे मोतिहारी न्यायालय में पेशी के दौरान 1 जुलाई, 2010 को दो सिपाहियों में एक सिपाही उपेंद्र शर्मा को लेकर नौ दो ग्यारह हो गया था. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी. 1 अगस्त, 2010 को छतौनी बस स्टैंड के समीप से बब्लु दुबे पुन: दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया और क़रीब दो वर्ष बाद 2012 में केंद्रीय कारावास से जमानत पर रिहा होने के बाद से नेपाल को सेफजोन समझकर राजधानी काठमांडू से लेकर सीमावर्ती जलेश्वर, बारा रोहतहट, विराट नगर तथा बीरगंज आदि ज़िलों में रहकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपहरण, रंगदारी एवं हत्या की घटनाओं को अंजाम देता रहा. बहरहाल, बिहार सरकार के द्वारा 50 हज़ार का ईनामी हत्यारा एवं रंगदार बब्लु दुबे की गिरफ्तारी से भारतीय पुलिस और आमजनों ने राहत की सांस ली है. ■


## मसालेदार खाने से परहेज करें



ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. बी.एन. कुमार

दिल की बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। कई बार बच्चों में दिल में छेद की बीमारी देखी जाती है जिसे समय पर सही से देखभाल करने और डॉक्टर की मदद से ठीक की जा सकती है। लेकिन बड़ों में अगर दिल में छेद की शिकायत हो जाए तो इसे बिना सर्जरी के ठीक नहीं किया जा सकता है।

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
MENSOSET
Her. Tonic with Ashoka 1800 mg
MUSTAL
Levocetirzine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.

डॉ. ब्रजेश नंदन कुमार पूर्णिया के रहने वाले हैं। लगभग 12 साल के अनुभव से वह कहते हैं कि दिल की बीमारी खान-पान में लापरवाही के कारण होती है। वह कहते हैं कि हम सबको ज्यादा बाहर की तली गली चीजें खाने से परहेज करना चाहिए अगर खान-पान में परहेज न हो तो 40 पार करते ही किसी को भी दिल की बीमारी की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को छाती में दर्द की शिकायत है, चलने में तकलीफ होती हो और निमोनिया की भी शिकायत है, घबराहट भी होती हो तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से ईलाज कराना चाहिए ।




ऐसे मरीजों से डॉ ब्रजेश नंदन कहना चाहते हैं कि ज्यादा भाग-दौड़ न करें, भारी चीजें न उठाएं और मौसम के बदलने पर अपने उपर खास ध्यान दें।

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

फरहाना आलमगीर


## भितिहरवा आश्रम

# यहां बापू की कांस्य प्रतिमा तक नहीं

**पूरे चंपारण में महात्मा गांधी से जुड़ी कई ऐतिहासिक स्थले हैं, जिनमें भितिहरवा आश्रम प्रमुख है. दु:ख की बात यह है कि अब तक इस आश्रम में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा तक नहीं लगाई जा सकी है...**

अवधेश कुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

कभी निलहों से संघर्ष का गवाह बना पश्चिम चंपारण ज़िले का नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत गौनाहा प्रखंड का भितिहरवा आश्रम इन दिनों न केवल सरकारी उपेक्षा का शिकार है, बल्कि अपना वज़ूद बचाने के लिए संघर्ष भी कर रहा है. इसकी बेहतरी के लिए राजनेताओं एवं अधिकारियों द्वारा की गई अब तक की तमाम कार्रवाई हवा-हवाई ही साबित हुई है. पूरे चंपारण में महात्मा गांधी से जुड़ी कई ऐतिहासिक स्थलें हैं, जिनमें भितिहरवा आश्रम प्रमुख है. अफसोस की बात तो यह है कि अब तक इस आश्रम में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा तक नहीं लगाई जा सकी है. यहां यह बता दें कि भितिहरवा आश्रम का दौरा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, राहुल गांधी, रामविलास पासवान समेत



लगभग सूबे के सभी नेता कर चुके हैं.

वर्ष 1988-89 में भितिहरवा आश्रम के जीर्णोद्धार एवं प्रतिमा स्थापना के लिए क़रीब 25 लाख रुपये का आवंटन हुआ, जिनमें राजभवन पटना ने कॉन्सेप्ट कमिटी के माध्यम से 20 लाख रुपये तत्कालीन ज़िला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया. वास्तुविद् संदीप कुमार झा ने विकास का मॉडल बनाया और कार्य प्रारंभ हुआ. तत्कालीन संग्रहालय प्रभारी दुर्गानंद मिश्र की देख-रेख में कार्य संपन्न ज़रूर हुआ, लेकिन आश्रम में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकी और मिश्र 2004 में सेवानिवृत्त भी हो गए. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एनएचपीसी के सौजन्य से महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 2004 में किया. उन्होंने भितिहरवा में कार्यरत कस्तुरबा कन्या विद्यालय को इंटर स्तर तक कराने की घोषणा की थी.

वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो भितिहरवा के लोगों की उम्मीदें जगीं, लेकिन इस सरकार में भी कोई ठोस पहल नहीं की गई. पिछले 18 अप्रैल, 2013 से तीन दिवसीय चंपारण दौरे पर आए नीतीश कुमार भी भितिहरवा आश्रम गए और केवल घोषणाएं कर निकल गए. इस दौरान उन्होंने उस कुएं को देखा, जिसके पानी का उपयोग कस्तुरबा और महात्मा गांधी किया करते थे. उन्होंने कस्तुरबा गांधी द्वारा दैनिक उपयोग में लाए जाने वाली जनकल्याण चक्की को स्पर्श कर अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ की. गांधीवादी अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया ने उनसे मुलाकात की और महात्मा गांधी एवं आश्रम से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी. भितिहरवा आश्रम में गाड़े गए चापाकल पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्रम परिसर में खंडहर में तब्दील अतिथि गृह को देखा. इसके विकास की रूपरेखा तय करने का आश्वासन भी दिया था. इतना सब होने के बावजूद कोई ठोस पहल सरकारी स्तर पर नहीं की गई, जिस कारण गांधीवादियों के साथ-साथ आम जनता का भी सरकार एवं राजनेताओं से भरोसा उठने लगा है.■






### अधिकारी बेच रहे हैं ग़रीबों के निवाले

चतरा ज़िले में ग़रीबों को मिलने वाला अंत्योदय, बीपीएल एवं अतिरिक्त बीपीएल खाद्यान्न की खुलेआम कालाबाज़ारी का मामला प्रकाश में आया है. इस मामले का ख़ुलासा हंटरगंज प्रखंड स्थित गोदाम पर लगे ट्रक से खाद्यान्न बेच रहे खलासी एवं ड्राइवर को हंटरगंज थाना प्रभारी मोहन पांडेय ने पकड़ कर किया. पकड़े गए ड्राइवर ने बताया कि गोदाम पर प्रति गाड़ी छह हज़ार रुपये की मांग की जाती है, तब ट्रक खाली की जाती है. गोदाम मैनेजर और उनके द्वारा अवैध रूप से कार्यरत व्यक्ति द्वारा वसूली की जाती है.






### कांग्रेस का धरना

चतरा ज़िला कांग्रेस की तरफ़ से समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया. इस धरने से संबंधित एक ज्ञापन झारखंड के राज्यपाल को चतरा उपायुक्त के माध्यम से दिया गया. इसमें ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सुस्ती का मामला उठाया गया. बैठक में चतरा ज़िले के कांग्रेस प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद साहू, ओबीसी के चेयरमैन प्रदीप कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष मो. साबिर अली आफताब



आलम, रौनक देव सिंह, चंद्रदेव यादव, विष्णु गुप्ता आदि शामिल थे. *-अमरेंद्र सिंह*

## » एक नज़र «

### पुलिस और क़ैदी साथ-साथ



समस्तीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से क़ैदियों के भाग जाने के कई मामले उजागर हो चुके हैं. इसके बावजूद आज तक प्रशासन सतर्क नहीं है, जिसका जीता-जागता उदाहरण समस्तीपुर कोर्ट परिसर में देखा गया. समस्तीपुर जेल हो या फिर दलसिंहसराय एवं रोसड़ा उप कारा, जब क़ैदियों को हाजिर होने के लिए कोर्ट लाया जाता है, तो दबंग क़ैदी पुलिस की मिलीभगत से होटल में मुर्गा एवं दारू का सेवन करते देखे गए हैं. वहीं कई क़ैदी पान-मसाले और सिगरेट भी दुकानों पर पीते हुए देखे गए हैं. क़ैदी ख़ुद भी खाते-पीते हैं और पुलिस कर्मियों को भी खिलाते-पिलाते हैं. कोर्ट कैंपस से क़ैदी का भागना अब आम बात है. सूत्रों की मानें, तो समस्तीपुर जेल से दर्जनों क़ैदी वर्षों से फ़रार हैं, जिन्हें पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है. *-प्रमोद प्रभाकर*

### साजिश पर सवर्ण मोरचा सख्त

बिहार प्रदेश सवर्ण मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सीतामढ़ी-शिवहर ज़िले के प्रभारी राजीव कुमार मिश्र (राजू) ने कहा है कि अब किसी भी सूरत में सवर्णों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संपन्न राष्ट्रीय चिंतन शिविर की चर्चा करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के बाद पूरे सवर्ण समाज के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव और शोषण किया जा रहा है. सवर्ण समाज के उत्थान के लिए एक पैसे का आवंटन नहीं किए जाने पर रोष जताते हुए उन्होंने कहा है कि अब किसी भी सूरत में सवर्णों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. राजू ने समाज के लोगों से चिंतन-मनन कर पिछड़ते जा रहे सवर्ण समाज को बचाने और आगे लाने में सहयोग की अपील की है. *-ब्रजेश*

ईशान डायग्नोस्टिक इमेर्जिंग सेंटर में रोज काफ़ी मरीज आते हैं, लेकिन मरीज अनुपम का अनुभव इस जांच घर को लेकर अच्छा नहीं रहा.

# रिक्त शिक्षक पद के लिए राजनीति

**वासुदेव सिंह के निधन से रिक्त हुए पद के लिए काफ़ी दावेदार हैं. इनमें से कुछ योग्य हैं, तो कुछ को बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. ऐसे में अब देखना यह है कि इस पद के लिए किसे चुना जाता है!**

कुमार मनीष

feedback@chauthiduniya.com

वासुदेव सिंह के निधन से रिक्त हुए दरभंगा शिक्षक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र के विधान परिषद के लिए संभावित उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के पूर्व ही ज़िले की शिक्षक राजनीति में सरगर्मी तेज होने लगी है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चारों ज़िले दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी में शिक्षक राजनीति की निर्णायक भूमिका वर्षों से रही है. माकपा के वासुदेव सिंह लगातार 17 वर्षों से इस सीट पर काबिज रहे, लेकिन 7 मई, 2014 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है. वर्तमान में उनके व्यक्तित्व को देखते हुए दूसरा प्रत्याशी खोजना मशक्कत का काम है. निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार विधान परिषद की रिक्ति के 6 माह के अंदर उपचुनाव अनिवार्य है. दरअसल, निर्वाचन क्षेत्र के सभी अंगीभूत कॉलेज, वित्त रहित संबद्ध कॉलेज, संबद्ध डिग्री कॉलेज, प्लस टू हाई स्कूल में न्यूनतम तीन वर्ष से कार्यरत शिक्षक मतदाता 6 वर्षों के कार्यकाल के लिए अपना नेता चुनते हैं. माध्यमिक, वित्त पोषित, नियोजित शिक्षक संगठनों और राजनीतिक दलों से पोषित भावी प्रत्याशियों ने अभी से चुनाव की तैयारियों को लेकर संपर्क अभियान एवं बैठकों के माध्यम से चुनावी रणनीति शुरू कर दी है. संभावित चुनाव को लेकर सभी शिक्षक संघों एवं राजनीतिक दलों में मंथन का दौर भी जारी है.

ज़िले के जिन भावी प्रत्याशियों के नामों की चर्चा है, उनमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कल्याण कोष के संयोजक डॉ. सुरेश प्रसाद राय, बिहार विश्वविद्यालय के दयालपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश राय, माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व ज़िला सचिव गणेश प्रसाद सिंह, दरभंगा के शिक्षक नेता सिकंदर राय, डॉ. हरिनारायण सिंह, नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश नेता डॉ. नवीन कुमार नवीन, प्रो. अमरेश शांडिल्य और प्रो. शालीग्राम सिंह के नामों की चर्चा जोर–शोर से हो रही है. वहीं शिक्षक राजनीति के विश्लेषक दिवंगत वासुदेव बाबू के पौत्र राहुल कुमार में भी उम्मीदवारी की संभावना तलाश रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वासुदेव बाबू के द्वादश कर्म के मौक़े पर आयोजित शोक सभा में राहुल की सेवा के तारीफ के पुल बांधे, जिससे कयास यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आगामी उपचुनाव में वासुदेव बाबू के पोते को समर्थन देकर शिक्षकों के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल करने की गोटी चल सकते हैं. डॉ. सुरेश राय ने तो बाक़ायदा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के व्यापक समर्थन के बल पर उम्मीदवारी और जीत के बाद की प्राथमिकताओं की घोषणा भी कर दी है. बेगूसराय के अलावा, तीनों ज़िले के माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं कई अन्य वित्त रहित शिक्षक नेताओं के समर्थन प्राप्त होने के दावों के बीच उनकी दावेदारी सुनिश्चित है. राय को भाजपा से समर्थन मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं. मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेता रह चुके प्रो. अमरेश शांडिल्य सत्ताधारी भाजपा से जुड़े हैं. दरअसल, अगर उनकी उम्मीदवारी होगी, तो डॉ. सुरेश राय के लिए भाजपा का समर्थन मिलना मुश्किल हो जाएगा.

कांग्रेस में सक्रिय नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के

प्रवक्ता नवीन कुमार सूबे की सरकार और पुराने शिक्षक संगठनों की मिलीभगत से नियोजित शिक्षकों का शोषण के ख़िलाफ़ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए क्षेत्र के 3500 नियोजित शिक्षकों को गोलबंद करने में लगे हैं. नियोजित शिक्षकों की मतदाता संख्या को वह निर्णायक मानते हैं. 2 वर्ष पूर्व हुए गया के चुनाव में नियोजित शिक्षक नेता श्याम सिंह की जीत से उत्साहित बेगूसराय के नियोजित शिक्षक भी निर्णायक भूमिका बनाने का मूड बना रहे हैं.

ज़िला माध्यमिक शिक्षक संघ ने डॉ. सुरेश प्रसाद राय के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उनके संगठन और नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग विरोध के मूड में भी है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह भी ज़िला इकाई द्वारा प्रत्याशी की घोषणा को परंपरा के विरोध में मानते हैं. प्रदेश के संयुक्त सचिव सह गया के शिक्षक नेता पन्ना लाल कहते हैं कि प्रत्याशी के चयन और घोषणा करने का अधिकार ज़िला इकाई को नहीं है. ज़िला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव सुधाकर राय पूछने पर बताते हैं कि ज़िला अध्यक्ष सर्वोपरि होने का भ्रम पाले बैठे हैं. उनकी नज़र में बाक़ी निष्ठावान कार्यकर्ता कुछ भी नही हैं. वे अपने फ़ैसले को प्रदेश कार्यालय जमाल रोड का फ़ैसला समझने की भूल कर रहे हैं.

ज़िला माध्यमिक शिक्षक संघ के 13 वर्षों तक सचिव रहे गणेश प्रसाद सिंह वासुदेव बाबू की राह पर चलने की बात करते हुए ज़िला माध्यमिक शिक्षक संघ के औचित्य पर ही सवाल उठाते हैं. वे संघ के कोष का केंद्रीयकरण करने और स्वयंभू नेता के पक्ष में ग़लत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं. उनका कहना है कि संघ में सचिव के अधिकार को जब्त कर गाड़ी ख़रीद एवं कैलेंडर बांटकर कोष का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि एक गबन का मामला है.

राय समर्थक ज़िला माध्यमिक शिक्षक संघ की मंझौल अनुमंडल सचिव बेनुजा कुमारी सहज, सुलभ उम्मीदवार के समर्थन और संघ की घाषणा के समर्थन में हैं, वे ज़िला सचिव राय के बयान को आपसी मनमुटाव एवं संघ के अंदरूनी कलह का नतीजा मानती हैं. जब संघ के अंदर ही ऐसा विरोधाभास है, तो बाहर का भगवान ही मालिक है.

दयालपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ओमप्रकाश राय दिवंगत वासुदेव बाबू को अपना प्रेरणास्त्रोत मानते हैं और संबद्ध कॉलेज शिक्षकों के कल्याण, नियोजित शिक्षकों के बक़ाया भुगतान, प्रोन्नति, माध्यमिक, उच्च विद्यालयों एवं कॉलेजों में पदरिक्तता को लेकर वे वर्तमान शिक्षा नीति की असफलता मानते हुए सुधार का रास्ता तलाश रहे हैं. इधर, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बाक़ी तीन ज़िलों के शिक्षक नेता भी इस सीट को बेगूसराय के खाते से झटकने के लिए जोर–शोर से लगे हुए हैं. मतदाताओं को बेसब्री से अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का इंतज़ार है. ■

# ग़लत जांच रिपोर्ट से आफत में जान

**बिहार में फ़र्ज़ी डॉक्टरों और जांच सेंटरों में मरीज इलाज़ के नाम पर अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें यहां कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है...**

नीरज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में पटना के बाद सबसे अधिक चिकित्सक पूर्णिया के लाइन बाज़ार में बसते हैं. लाइन बाज़ार सीमांचल में चिकित्सकों की मंडी के नाम से जाना जाता है. यहां प्रतिदिन स्थानीय मरीजों के अलावा हज़ारों की संख्या में मरीज पड़ोसी देश नेपाल से सटे राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी पहुंचते हैं. लाइन बाज़ार में जहां हज़ारों की संख्या में चिकित्सक मौजूद हैं, वहीं इतनी ही संख्या में पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक्सरे और जांच घर वाले भी हैं. मरीज काफ़ी भरोसे के साथ यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कभी–कभी ऐसी घटना भी हो जाती है कि मरीजों का भरोसा इन जांच घरों से उठने लगता है. ईशान डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर लाइन बाज़ार के बिहार टॉकिज रोड में स्थित है. यहां अल्ट्रासाउंड के अलावा, एमआरआई और एक्स–रे की सुविधा भी उपलब्ध है. हर दिन काफ़ी संख्या में मरीज यहां जांच कराते हैं, लेकिन मरीज कुमारी अनुपम का अनुभव इस जांच घर को लेकर अच्छा नहीं रहा.

8 अप्रैल, 2013 को पूर्णिया के स्थानीय गुलाब बाग़ की रहने वाली कुमारी अनुपम के पेट में अचानक दर्द हुआ. आनन–फानन में घरवालों ने मरीज को प्रसिद्ध फिजीशियन डॉ. बीपी साह को दिखाया. डॉ. बीपी साह ने मरीज को अल्ट्रासाउंड और एक्स–रे कराने की सलाह दी. मरीज का अल्ट्रासाउंड और एक्स–रे 8 अप्रैल को ही लाइन बाज़ार के ईशान डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर में कराया गया, जहां एक्स–रे जांच नॉर्मल निकला, वहीं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एब्डोमेन में अत्यधिक गैस के गोले की छाया के साथ पेल्विक रीजन में इंटरोपेरिटोनियल ल्यूड का इंप्रेशन रिपोर्ट दिया गया. उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर डॉ. बीपी साह ने दवा पर्ची पर लिखकर दी, लेकिन दवा खाने के बाद भी मरीज के पेट का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा था. अंतत: महिला मरीज के भाई विभाष कुमार सिंह ने मरीज को डॉ. ए के गुप्ता के यहां ले जाने का निर्णय लिया. डॉ. ए के गुप्ता ने मरीज को देखने के बाद पेट में सिस्ट होने की आशंका जाहिर की और किसी अन्य जगह से नया अल्ट्रा साउंड कराने की सलाह दी. वहीं दूसरी तरफ़ मरीज की हालत नाजुक होती जा रही थी. 10 अप्रैल,

2013 को मरीज का दूसरा अल्ट्रासाउंड पूर्णिया न्यूरो एवं स्कैन सेंटर में कराया गया, जिसके रिपोर्ट में ओवरी में बड़ा सिस्ट निकला. दोनों अल्ट्रासाउंड सेंटर की भिन्न रिपोर्ट को देखकर डॉ. एके गुप्ता असमंजस में पड़ गए, वहीं तीसरा अल्ट्रासाउंड कराने की बात भी कही जाने लगी. मरीज की हालत देखकर सर्जन डॉ. एके गुप्ता ने खुद लेप्रोस्कोपिक उपकरण की सहायता से बिमारी का पता लगाकर ईलाज करने का निर्णय लिया. 11 अप्रैल, 2013 को मरीज का लेप्रोस्कोपिक जांच करके लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ, जिसमें बाईं ओवरी पर एक बड़े सिस्ट को ओवरी के साथ ही लेप्रोस्कोपिक विधि से काटकर निकाला गया. इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना था कि मरीज के जीवन पर बन आई थी. कुछ और देर होने पर मरीज की जान भी जा सकती थी. ईशान डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर पर सवाल खड़ा करते हुए स्थानीय लोगों एवं बुद्धिजीवियों का कहना है कि जब स्थानीय मरीजों का फ़र्ज़ी और ग़लत जांच ईशान डायग्नोस्टिक सेंटर में हो रहा है तो नेपाल, बंगाल और पड़ोसी अररिया, कटिहार, किशनगंज जिले से आने वाले मरीजों का ईशान डायग्नोस्टिक में जांच करवाने से क्या फ़ायदा होगा. मालूम हो कि डॉ. मुकेश कुमार ने ईशान डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर खोला है, उनके साथ यहां दो जूनियर डॉक्टर्स संगीता कुमारी एवं डॉ. क्षितिज कुमार भी जांच करते हैं. दूसरी तरफ़ पीड़ित मरीज के अभिभावक ने ईशान डायग्नोस्टिक को वकील के माध्यम से 10 लाख हर्जाने का नोटिस भेजा है और 15 दिनों की मोहलत देकर उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर दिया है.

# » एक नज़र «

## वैश्य समाज एकजुट हो

नीतीश–मोदी के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हुआ है. पूरे सूबे में भयमुक्त, अमन–चैन एवं शांति का वातावरण है. इसलिए व्यवसायी वर्ग बेधड़क पूंजी का निवेश कर रहा है. इसके अलावा, भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सह अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद चौरसिया ने खगड़िया परिसदन में कहा कि वैश्य की हत्या होने पर सरकार मुआवजा के रूप में दो लाख रुपये देगी. चौरसिया ने कहा कि बिहार में 22 से 23 प्रतिशत वैश्य हैं और उनके 60 उपजाति भी हैं. मौक़े पर पूर्व जिलाध्यक्ष सह भाजपा प्रभारी शशिभूषण प्रसाद ने कहा कि पार्टी वैश्य समाज के हित एवं एकजुटता के लिए लगातार मुहिम चलाकर काम कर रही है. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी, राजकुमार विद्यार्थी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार राणा, रमाकांत रजक, ज़िला महामंत्री रवीश चंद्र, नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, कुंदन सिंह समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे.

## छात्रवृत्ति राशि का वितरण

विद्यालयों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से शिक्षा के प्रति बच्चों के झुकाव के साथ अभिभावक भी सजग हुए हैं. सन्हौली ग्राम पंचायत की मुखिया रानी देवी ने सीताराम मेमोरियल उच्च विद्यालय में मुख्यमंत्री साइकिल एवं पोशाक योजना की राशि वितरण के दौरान ये बातें कहीं. मौक़े पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुकांति कुमारी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2012–13 के कक्षा नौ में अध्ययनरत 75 प्रतिशत मार्क्स वाले छात्र–छात्राओं के बीच साइकिल एवं कल्याण विभाग से प्राप्त छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया जा रहा है. इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष सुधीर राम सहित विद्यालय के शिक्षक विवेकानंद झा, शैलेंद्र चौधरी, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार, कविता कुमारी, निभा कुमारी, रंजू कुमारी के सहयोग से राशि वितरण किया गया.

## किसान प्रकोष्ठ की बैठक

जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्षों एवं ज़िला संगठन पदाधिकारी की बैठक खगड़िया में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता किसान प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने की. बैठक में आगामी 3 जून को ज़िला सम्मेलन की तैयारी पर विचार–विमर्श किया गया. वहीं बैठक में ज़िला अध्यक्ष द्वारा किसानों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई. इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सोनेलाल मेहता, ज़िला उपाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह, श्रीकांत सिंह, पंकज कुमार गुप्ता, ज़िला सचिव मो. औरंगजेब, अलौली प्रखंड अध्यक्ष रामदुलार राय, वेद प्रकाश सिंह, मानसी के अवधेश सिंह, लाल बिहारी चौरसिया, डॉ. पुरुषोत्तम नारायण सिंह, धीरज सिंह, रवींद्र झा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे. *–नंदकिशोर शर्मा*

## डॉ. शमीमुल अध्यक्ष बने

मोतिहारी: आयुष विकास संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक गांधी संग्रहालय के सभागार में हुई, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और संघ का विस्तार किया गया. बैठक में सर्वसम्मति से डॉ. शमीमुल हक़ को अध्यक्ष, डॉ. शारदा कुमार को महासचिव, डॉ. एच शाहीद को कोषाध्यक्ष चुना गया. उपाध्यक्ष पद पर डॉ. एमएच इक़बाल, डॉ. इरफ़ान, डॉ. विवेक गौरव, डॉ. दिलशाद आलम को चुना गया. संयुक्त सचिव के पद पर डॉ. जावेद आलम, डॉ. मोतिउल्लाह एवं डॉ. शन्नी विक्रम चुने गए. डॉ. प्रभात सभासम को प्रवक्ता निर्वाचित किया गया. इसी तरह डॉ. खालीद अंजुम, डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. उमेश चंद्र सिंह, डॉ. तबरेज आलम, डॉ. शगुफ्ता जमाल, डॉ. शबनम आशिफ, डॉ. फैजल परवेज खां, डॉ. शैलेश कुमार, डॉ. पंकज कुमार सिंह, डॉ. एमएस अंजुम को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया. मौक़े पर अधिवक्ता मो. ज़मील अंजुम को विधि सलाहकार के रूप में चुना गया. बैठक की अध्यक्षता डॉ. मो. एचएम इक़बाल ने की, जबकि संचालन डॉ. शारदा कुमार ने किया. धन्यवाद ज्ञापन डॉ. उमेश चंद्र सिंह ने किया. *–इंतेज़ारुल हक़*

## झारखंड में चुनाव ही विकल्प

कामरेड वृंदा करात ने हंटरगंज में कहा कि झारखंड राज्य में भाजपा एवं कांग्रेस द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, वह हद पार कर गई है. यहां चुनाव ही एकमात्र विकल्प है. उन्होंने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस एवं भाजपा की सरकार है, वहां क़ानून व्यवस्था लचर है. अब तक झारखंड में 13 वर्षों में क़रीब सभी मुख्यमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं. यहां अपना विकास ज़्यादा और राज्य का विकास कम हुआ है. इस अवसर पर संजय पासवान, रामदेव सिंह, बनवारी सिंह एवं राजेंद्र सिंह उपस्थित थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

## नहीं थमेगा विकास

रुन्नीसैदपुर जदयू विधायक गुड्डी देवी ने क्षेत्र के मानिक चौक महारानी स्थान से वैशाली बैंक हुए कमलदह टोला तक जाने वाली पीसीसी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. 82 लाख, 52 हज़ार रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्य के शिलान्यास के मौक़े पर विधायक ने कहा कि सीतामढ़ी ज़िले में विकास की गति थमने का कोई उपाय नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्य चरम पर है. सीतामढ़ी ज़िले के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में सर्वोपरि रहेगा. कार्यक्रम के मौक़े पर श्रीनाथ झा, सुबोध कापड़, नवल चंद्रवंशी, सरपंच वंशीधर झा, सोनफी साह, राधाकांत झा, योग नारायण साह, बबलू झा, जितेंद्र पटेल, चंदन कुमार, भरत महतो एवं वासुदेव शर्मा समेत कुछ और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित अन्य थे. ***–विभा सिन्हा***

## राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन

शिवहर : पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शिवहर ज़िला मुख्यालय स्थित नवाब उच्च विद्यालय प्रांगण में तीन दिवसीय राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन योजना पार्षद के उपाध्यक्ष सह पूर्व विदेश राज्य मंत्री हरि किशोर सिंह ने की. कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि स्थानीय भाजपा सांसद रमा देवी भी मौजूद थीं. ज़िला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ज़िला कबड्डी संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में कुल 33 ज़िले की टीम ने भागीदारी की. इनमें 18 बालक एवं 15 बालिका वर्ग की टीम शामिल हुई. उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक मो सरीफुद्दीन, अंगेश कुमार सिंह, कांग्रेस के ठाकुर दिवाकर सिंह, जदयू के अनील कुमार, कमलेश पांडेय, प्रधानाचार्य राजेश्वर सिंह, कमोद मिश्रा, पवन कुमार, भोला सिंह एवं मो तमन्ना समेत अन्य लोग भी शामिल थे. ***–हेमंत कुमार***

शिवहर को ज़िला तक का सफ़र तय कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद रघुनाथ झा ने ज़िले में शिक्षा के विकास को लेकर कई योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कराया था.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467



# समस्तीपुर

# लोकसभा चुनाव में होगा त्रिकोणीय संघर्ष

***महाराजगंज उपचुनाव और कल्याणपुर विधानसभा चुनाव के परिणामों का समस्तीपुर के आगामी लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस, जदयू और लोजपा में टक्कर दिलचस्प होगा...***

प्रमोद प्रभाकर
feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर के आगामी लोकसभा चुनाव पर महराजगंज उपचुनाव एवं कल्याणपुर विधानसभा चुनाव का प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है. इस लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई होती रही है. समस्तीपुर 23 अनुसूचित जाति क्षेत्र से पिछली बार जदयू के उम्मीदवार महेश्वर हजारी को 2,59,458, लोजपा गठबंधन से रामचंद्र पासवान को 1,55,082 एवं कांग्रेस से डॉ. अशोक कुमार को 91,655 मत प्राप्त हुआ था. महेश्वर हजारी इस सीट से विजयी घोषित किए गए थे, लेकिन पिछली बार की हार–जीत में कुछ अलग कारण भी थे. जैसे रामचंद्र पासवान पूर्व लोकसभा सीट रोसड़ा से चुनाव जीतते थे और उनके लिए यह नई सीट होने के कारण उन्हें मेहनत नए तरीक़े से करनी पड़ी थी. अब इस क्षेत्र से वह पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं. इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में मुक़ाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है.

डॉ. अशोक कुमार की बात करें, तो वह हमेशा से विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे थे और तीन बार कांग्रेस की टिकट पर जीत भी चुके थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार कर सोचने–समझने का मौक़ा भी नहीं दिया, फिर भी वह संघर्ष कर लगभग एक लाख वोट लाकर तीसरे स्थान पर बने रहे. अब अगर इस चुनाव में ये भी चुनाव लड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ करने की क्षमता रखते हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या

**समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में दरभंगा जिले के दो विधानसभा कुशेश्वर स्थान 78 अनुसूचित जाति एवं हायाघाट 84 सहित कल्याणपुर 131 अनुसूचित जाति, वारिसनगर 132, समस्तीपुर 133, रोसड़ा 139, विधानसभा सहित समस्तीपुर लोकसभा में छह विधानसभा के वोटर अपने मत का प्रयोग करते हैं.**

रामचंद्र पासवान

महेश्वर हजारी

डॉ. अशोक कुमार

13,12,570 एवं सर्विस मतदाता की संख्या 891 थी. इस बार वोटरों की संख्या लगभग दो प्रतिशत बढ़ने की बात निर्वाचन विभाग द्वारा बताई जा रही है.

समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में दरभंगा ज़िले के दो विधानसभा कुशेश्वर स्थान 78 अनुसूचित जाति एवं हायाघाट 84 सहित कल्याणपुर 131 अनुसूचित जाति, वारिसनगर 132, समस्तीपुर 133, रोसड़ा 139, विधानसभा सहित समस्तीपुर लोकसभा में छह विधानसभा के वोटर अपने मत का प्रयोग करते हैं. रामचंद्र पासवान एवं डॉ. अशोक कुमार पूर्व के दोनों उम्मीदवारों ने चौथी दुनिया को बताया कि आगामी चुनाव में हम लड़ने जा रहे हैं. वहीं जदयू के सांसद महेश्वर हजारी का पार्टी से रिश्ते में मनमुटाव भी देखा गया है. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सब कुछ निर्भर करता है. जो भी हो, आगामी चुनाव के लिए मुख्य रूप से जदयू, लोजपा एवं कांग्रेस तीनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी–अपनी शक्ति मतदाताओं के बीच झोंकने का काम करेंगे. प्रचार की बात करें, तो एनडीए एवं राजद गठबंधन को छोड़ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केंद्रीय नेता का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिहार में उनके पास प्रचारक के रूप में एक भी नेता नहीं है. सुरक्षित सीट होने के कारण रामविलास पासवान की पैनी नज़र इस सीट पर लगी हुई है और इसीलिए वह अपनी टीम के साथ लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. रामचंद्र पासवान भी लोगों के संपर्क में हैं. जदयू में उम्मीदवार को लेकर अभी स्थिति साफ़ नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि महश्वेर हजारी को नीतीश कुमार की हरी झंडी मिल गई है. कहा जाए, तो तीनों दलीय प्रत्याशी अभी से ही जनता का मिजाज भांपने में जुट गए हैं. देखना है, जनता इस बार किसे अपना आशीर्वाद देती है. ■

# जर्जर भवन में पढ़ने के लिए विवश हैं बच्चे

**शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने की बात करने वाली सरकार अब तक विद्यालय के लिए अपना भवन भी उपलब्ध नहीं करा पाई है. क्यों?**

प्रमोद प्रभाकर
feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने की सरकारी घोषणा अब भी सरजमीं पर कोसों दूर है. सरकार ने प्रायोजित योजनाओं के तहत भले ही इस दिशा में क़दम बढ़ाया है, लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति एवं प्रशासनिक महक़मे की लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों को अब तक अपना भवन नसीब नहीं मिल सका है. इसका जीवंत उदाहरण शिवहर ज़िला मुख्यालय स्थित नवाब उच्च विद्यालय परिसर में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर है, जिसे स्थापना के क़रीब एक दशक बाद भी अपना भवन नहीं मिला है. ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में पहल नहीं हुई है. सच्चाई यह है कि तक़रीबन सात साल पूर्व शुरू कराए गए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी अधर में लटका हुआ है. स्थानीय भाजपा सांसद रमा देवी को हाल ही में जब उक्त संस्थान की याद आई, तब उन्होंने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री एमएम राजू को एक पत्र प्रेषित कर समुचित क़दम उठाने के लिए आग्रह किया. पिछले मार्च माह में प्रेषित पत्र में सांसद ने वर्ष 2005 से शुरू निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने के साथ ही बरती गई लापरवाही के लिए दोषी एजेंसी एवं पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है. बताया जाता है कि वर्ष 2003 में शिवहर में शिक्षा के विकास को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई गई, लेकिन अपना भवन नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय का संचालन स्थानीय नवाब उच्च विद्यालय के 4 खपरैल कमरे में कराया जाने लगा. वर्ष 2005 में ज़िला मुख्यालय से क़रीब 7 किलोमीटर दूर बिसाही गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का निर्माण लगभग 10 करोड़ की लागत से शुरू कराया गया. कार्य योजना के प्रति बरती जा रही लापरवाही व उदासीनता का आलम यह है कि निर्मित विद्यालय भवन उद्घाटन से पूर्व ही जर्जर होने लगा है. इसलिए निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है. खिड़की में लगाए गए ग्रिल भी कुछ लोगों ने ग़ायब करना शुरू कर दिया है, वहीं बिछाए गए होम पाइप भी कई स्थानों पर ध्वस्त हो गया है. अति महत्वपूर्ण चहारदिवारी निर्माण का कार्य भी अब तक अधर में ही लटका है. लगभग 10 एकड़ ज़मीन पर शुरू हो रहे निर्माण कार्य में बिलंब का खामियाजा यहां शिक्षा पाने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है. विद्यालय प्रबंधन की मानें, तो भवन के अभाव में निर्धारित क्षमता से आधा बच्चों का ही प्रति वर्ष विद्यालय में नामांकन हो पा रहा है. वहीं दूसरी ओर पूर्व राजद विधायक अजित कुमार झा ने कहा कि शिवहर को ज़िला तक का सफर तय कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद रघुनाथ झा ने ज़िले में शिक्षा के विकास को लेकर कई योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कराया था. बाद में विधानसभा का सदस्य रहते स्वयं अजित ने भी उक्त विद्यालय भवन का उद्घाटन कराने को लेकर प्रयास किया, लेकिन इस दिशा में सार्थक पहल नहीं किए जाने का नतीजा आज सामने दिख रहा है. फिलहाल, येन–केन प्रकारेण खपरैल विद्यालय में क़रीब सवा दो सौ बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए विवश हैं. बच्चों की उक्त विवशता सरकारी घोषणा की हक़ीक़त के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता एवं प्रशासनिक तंत्र की मनमानी कार्यशैली का उदाहरण बना है. अब देखना है कि सांसद के पहल पर भी विद्यालय भवन का उद्घाटन हो पाता है, अथवा यह सेहरा किसी और को नसीब होने वाला है. ■

**पेज एक का शेष**

# भूख से मर रहे लोग, सड़ रहा है अनाज

एसएफसी के गोदाम में सैकड़ों क्विंटल सड़ा अनाज पाया गया था. पिछले साल ही राज्य की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने दरभंगा में एसएफसी–एफसीआई के बीच चल रही अनाज की हेराफेरी का मामला पकड़ा था. कई ट्रक जब्त किए गए थे और कहा गया था कि जिन ट्रकों से अनाज लादकर भेजा जाता है, वे ट्रक मुक़ाम तक नहीं पहुंचते. इसके बावजूद काग़ज़ पर अनाज का वितरण बिल्कुल दुरुस्त है. इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज़ हुआ, लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवरों को छोड़कर कोई भी क़ानूनी शिकंजे में नहीं फंस सका. लोगों ने बताया कि काग़ज़ पर गोदाम का संचालन, अनाज को सड़ाना, अनाज की हेराफेरी जैसे कारनामे एसएफसी और प्रशासनिक अमला के आपसी सामंजस्य की बदौलत हमेशा चलता रहता है. विभागीय मंत्री श्याम रजक से जब पूछा गया कि खुले में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज क्यों रखा गया, तो उनका जवाब था कि धान को खुले में रखने से कोई नुक़सान नहीं होता. जब उन्हें बताया गया कि धान के बोरों में अंकुरण तक हो चुका है और अधिकतर बोरों में रखा अनाज सड़कर बर्बाद होने के क़गार पर है, तो उन्होंने तुरंत बयाना बदला और कहा कि विभाग के प्रधान सचिव मामले की जल्द ही जांच करेंगे.

पूरे प्रकरण में संतरी से लेकर मंत्री तक की उदासीनता सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां उड़ाती हैं, जिनमें अनाज को हर हाल में सुरक्षित रखने की जवाबदेही सरकार को दी गई है. अनाज के संरक्षण के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही और एसएफसी में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री ने जांच के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन जांच का क्या नतीज़ा आएगा, और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह तो समय ही बताएगा. आम आदमी की तरफ़ से तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सुरहाचट्टी में बड़ी मात्रा में जो अनाज सड़कर बर्बाद हो गया, उसकी क्षति पूर्ति कैसे संभव होगी? ■

# चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

17 जून–23 जून 2013

www.chauthiduniya.com

## मुलायम ने दी अखिलेश को नसीहत

# बेटे से नाराज हैं पिता

**सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव समाजवादी सरकार में क़ानून व्यवस्था के बुरे हाल को लेकर मुख्यमंत्री को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन मुलायम को उन वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों पर भी पैनी नज़र रखनी चाहिए, जो वरीय होने का फ़ायदा उठाकर मुख्यमंत्री को उल्टी-सीधी नसीहतें देते हैं.**


अजय कुमार

feedback@chauthiduniya.com


एक तरफ़ सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव समाजवादी सरकार के तौर-तरीक़ों को लेकर मुख्यमंत्री को फटकार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूबे की जनता सीएम को जीत का तोहफा दे रही है. फरवरी में भाटपार रानी और अब हंडिया विधान सभा सीट पर सपा की जीत के आंकड़े यही बयां कर रहे हैं. इन दो विजयों के आधार पर सपा की सफलता की गाथा तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इतना तय है कि जनता अभी भी अखिलेश सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रही है. हंडिया सीट पर सपा का ही क़ब्ज़ा था. सपा विधायक महेश नारायण सिंह की मौत के बाद यह सीट रिक्त हुई थी और सपा ने महेश के बेटे प्रशांत को चुनाव में उतारा था. इसलिए, यह तय माना जा रहा था कि सपा को सहानुभूति का फ़ायदा मिलेगा. वहीं वोटों का ध्रुवीकरण भी देखने को मिला.

समाजवादी सरकार जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए लगातार दाना फेंक रही थी, इसी का नतीजा था कि मुस्लिम मतदाता न केवल बड़ी तादात में वोटिंग करने निकले, बल्कि सपा के पक्ष में खुल कर वोटिंग भी की, जबकि अन्य पार्टियों के वोटरों ने मतदान केंद्र तक जाने की जहमत तक नहीं उठाई थी. इस बात का एहसास कम मतदान प्रतिशत से होता है. देखने में यह आता है कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम रहता है, तो कांग्रेस और भाजपा को नुक़सान उठाना पड़ता है, वहीं सपा को फ़ायदा होता है. बसपा के वोटरों ने थोड़ा उत्साह ज़रूर दिखाया, लेकिन वह भी सपा प्रत्याशी को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दे पाए. लगता है कि सपा का मुस्लिम कार्ड तो खूब चला, लेकिन बसपा का ब्राह्मण कार्ड थोथा साबित हुआ. हां, इतना ज़रूर तय हो गया कि प्रदेश की राजनीति अभी भी दो ध्रुवों सपा और बसपा के बीच ही बंटी है.

इस जीत के बाद सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री की पीठ तो ज़रूर थपथपाई होगी, लेकिन इससे सपा सरकार की नाक़ामयाबी पर पर्दा नहीं पड़ सकता है. प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का बुरा हाल है. जनता के हितों की तरफ़ ध्यान देने वाला कोई नहीं है. विकास के काम रुके हुए हैं. इस सबसे हटकर बात हाल में दिये गये मुलायम के इस बयान की कि जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता, तो 15 दिन में क़ानून व्यवस्था सुधार देता, जबकि सब जानते हैं कि 2007 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी क्यों हारी थी और बसपा को जनता ने क्यों सिर आंखों पर बैठाया था. इस बात का एहसास आम जनता के साथ-साथ सपा के बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता को अच्छी तरह से है. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ़ बस एक ही बात थी, वह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान क़ानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगा पाये थे. प्रदेश में जंगलराज था. सपा के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी खुले आम भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी कर रहे थे, लेकिन मुलायम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के ग़लत आचरण के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के बजाए हाथ पर हाथ धरे बैठे थे. यही वजह है कि आज जब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क़ानून व्यवस्था सुधारी जाये, तो काफ़ी अटपटा लगता है. यह ठीक है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सूबे की क़ानून व्यवस्था में सुधार के लिए कठोर कदम उठाने में हिचकना नहीं चाहिए. जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. क़ानून की नज़र

में सभी समान हैं, लेकिन विपक्ष मुलायम की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक कहते हैं कि सपा प्रमुख अगर वास्तव में सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह कुछ बदलाव लायें. वंशवाद से आगे देखें. विजय को लगता है कि मुलायम सार्वजनिक रूप से सपा सरकार की खिंचाई का ड्रामा करके अखिलेश सरकार की नाक़ामयाबी पर परदा डालना चाहते हैं.

दरअसल, अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही न केवल विपक्ष, बल्कि सपा के भीतर और तमाम अधिकारियों में यह आम राय कायम हो गई है कि मुख्यमंत्री शासन चलाने में पूर्णत: आत्मनिर्भर नहीं हैं. उन्हें अपने फ़ैसलों के लिए कभी अपने पिता और पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह का मुंह देखना पड़ता है, तो अक्सर आज़म खां जैसे नेता उनके मार्गदर्शक की भूमिका में नज़र आते हैं. इसके अलावा, उन्हें अपने चाचाओं और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों का भी सहारा लेना पड़ता है. अनुभव की कमी और बात है, लेकिन युवा मुख्यमंत्री तो छोटे-छोटे फ़ैसले लेने में भी कतराते हैं. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को युवा मुख्यमंत्री की लाचारी पर तरस आता है. उन्हें लगता है कि अखिलेश को पार्टी के भीतर मोहरा बनाया जा रहा है. उनके हिस्से में सत्ता का ज़हर ही आ रहा है, जबकि अमृत आज़म और शिवपाल जैसे लोग लपक लेते हैं. मुलायम सिंह जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच और बैठकों में मुख्यमंत्री को निर्देशित करते हैं, इससे लगता है कि उन्हें अखिलेश की क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं है और न ही वे प्रदेश का शासन उनकी मर्जी पर छोड़ने वाले हैं. दूसरा पहलू यह भी है कि जब मुख्यमंत्री की क्षमता पर सपा के मुखिया को ही संदेह है, तो बाक़ी लोग उन्हें क्यों महत्व देंगे? जाहिर है, शासन के नेतृत्व का कमजोर होने का आभास व्यवस्था में तमाम गड़बड़ियां पैदा करता है. मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन करने वाले मनमाने तरीक़े से काम करने लगते हैं. कुछ दिन पहले इस तरह के हालात को ख़ुद मुख्यमंत्री ने बयां भी किया था कि आईएएस अफसर उनके आदेश पर भी काम को महीनों लटकाये रहते हैं. कोई भी शासन अगर इस तरह चलेगा, तो भला कहां से क़ानून व्यवस्था दुरुस्त होगी? हो सकता है कि पार्टी के वरिष्ठजनों के अनावश्यक हस्तक्षेप से ख़ुद मुख्यमंत्री के मनोबल पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा हो. मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तिसंपन्न और गरिमायुक्त होता है. मुलायम सिंह भले यह सोचते हों कि अपनी ही सरकार की आलोचना कर वे जनता की हमदर्दी हासिल कर लेंगे और लोकसभा चुनाव तक कोई सत्ता विरोधी लहर प्रदेश में पैदा न हो, लेकिन राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि यह मुलायम का भ्रम है. अगर सरकार क़ानून व्यवस्था और जनता को सुविधाएं देने के मामले में फिसड्डी रहती है, तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

इन चुनावों के नतीजों से सपा को भ्रम नहीं पालना चाहिए. आम चुनाव में माहौल दूसरी तरह का होगा. अगर पार्टी प्रमुख वर्तमान मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री को बदल देने में किसने रोका है? जनता ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है, तो इसकी अपनी अपेक्षाएं भी हैं और वह प्रदेश का विकास और सुशासन देखना चाहती है, न कि थोथी बहानेबाज़ियों से इसका काम चलने वाला है. इसलिए सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को अपने मुख्यमंत्री को विवेक से अधिकारों का इस्तेमाल करने देना चाहिए और अंतत: जब वे खरे नहीं उतरते हैं, तो कोई विकल्प देना चाहिए. मुलायम के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह अखिलेश के आलावा इन नेताओं और मंत्रियों पर भी पैनी नज़र रखें, जो वरीय होने का फ़ायदा उठाकर मुख्यमंत्री को उल्टी-सीधी नसीहतें देते हैं.■

## बहुगुणा-आर्य के बीच खटास

# बेचैन हैं कार्यकर्ता

*यशपाल आर्य लंबे समय से मुख्यमंत्री से नाराज़ बताये जा रहे हैं. यह नाराज़गी किस बात को लेकर है, इसे लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है. लेकिन दोनों के बीच इस खटास से सरकार और संगठन के अंदर भी बेचैनी है...*

जबर सिंह वर्मा

feedback@chauthiduniya.com


मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य के बीच अंदरखाने कुछ खिचड़ी पकने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर-शोर से चल रही है. ख़ासकर, सीएम की ओर से 31 मई को प्रदेश भर के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की देहरादून में बुलाई गई बैठक में दोनों नेताओं के रिश्ते में खटास की चर्चा है. दरअसल, आर्य लंबे समय से मुख्यमंत्री से नाराज़ बताये जा रहे हैं, इसे लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है. दोनों के बीच इस खटास से सरकार और संगठन के अंदर भी बेचैनी है.

31 मई को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुटे थे. बैठक से पूर्व सीएम अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज से सीधे दिल्ली गए और इस बहुप्रचारित बैठक में ऐन वक्त पर ही देहरादून पहुंचे. दूसरी तरफ़, अक्सर संगठन के लोगों के साथ खुलकर मिलने और कार्यकर्ताओं से घिरे रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य इस बैठक में खुल कर नहीं बोले, न ही कार्यकर्ताओं से मिलने पर हमेशा वाला अंदाज़ और उत्साह नज़र आ रहा था. आर्य बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ही बोले, वह भी बेहद सख्त लहजे में. आर्य ने सीएम की मौजूदगी में मीडियाकर्मियों के सामने सख्त अंदाज़ में दो टूक कहा, जो लोग संगठन में योगदान दे रहे हैं, उन्हें सम्मान के तौर पर दायित्व भी दिए जाने चाहिए. कार्यकर्ताओं के इंतज़ार की अब सभी हदें पार हो चुकी हैं. इस पर सीएम ने भी उसी समय सफ़ाई देते हुए कहा कि संगठन के लोगों को दायित्व ज़रूर दिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर न रावत गुट है, न आर्य गुट और न बहुगुणा गुट. लोकसभा चुनाव ही सबका लक्ष्य है. दरअसल, मुख्यमंत्री द्वारा संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेने, सरकार का 14 महीने का लंबा कार्यकाल निकलने के बावजूद सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व नहीं देने जैसे मसलों पर आर्य मुख्यमंत्री से ख़ासे नाराज़ बताए जा रहे हैं. पहले भी आर्य की यह नाराज़गी सामने आ चुकी है. इन दिनों सूबे में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने को लेकर भी कसरत चल रही है. सीएम के ख़ासमख़ास बताए जाने वाले नरेंद्र नगर विधायक सुबोध उनियाल अक्सर एक व्यक्ति-एक पद का मुद्दा उठाते रहे हैं. देहरादून में हुई बैठक में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया. वर्तमान में आर्य प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं. ऐसे में, सुबोध यह बयान आर्य पर हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है. हालांकि, आर्य स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं. फिलहाल, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की कसरत भी चल रही है. प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद आर्य और उनके समर्थक बहुगुणा सरकार के कैबिनेट में नंबर वन की जगह चाहेंगे. और इसके लिए उन्हें कुछ अहम विभागों की दरकार भी रहेगी, लेकिन सीएम इस मसले पर क्या रवैया अपना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है. फिलहाल, आर्य के पास राजस्व और सिंचाई विभाग है. सूत्रों की मानें, तो टिहरी उपचुनाव और निकाय चुनाव में मिली क़रारी शिकस्त और इसकी ज़िम्मेदारी तय करने को लेकर भी दोनों नेताओं में मतभेद उभरे हैं.

बीते विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के दौरान अध्यक्ष आर्य तब विजय बहुगुणा के पाले में मजबूती से खड़े हो गए थे, जिससे कद्दावर नेता हरीश रावत समेत चारों तरफ़ से पार्टी के अंदर हो रहे जबरदस्त विरोध के बावजूद बहुगुणा सीएम बनने में कामयाब रहे थे. तब आर्य स्वयं भी सीएम पद के प्रबल दावेदार थे. पिछले 14 महीनों में सरकार और संगठन के ये दोनों मुखिया कभी खुलकर एक-दूसरे के विरोध में नहीं दिखे, लेकिन दोनों के बीच अंदरखाने तक़रार की ख़बरें अक्सर आती रही हैं. ■

वर्तमान में प्रत्येक हजार बालकों पर प्रदेश में 890 बालिकाएं ही रह गई हैं, जबकि 2001 में प्रत्येक हजार बालकों पर 908 बालिकाएं थीं.

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

# घट रही हैं बेटियां

**जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बेटियों की संख्या दिन ब दिन घटती ही जा रही है. यह हाल तब है, जब पिछले दस सालों में प्रदेश की जनसंख्या में 16 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है.**

उत्तराखंड की जनगणना के अंतिम आंकड़े बता रहे हैं कि देवभूमि के लगभग सभी जिलों में बेटियों की संख्या घट रही है. कुछ दिनों पहले राज्य की गृह मंत्री इंदिरा हृदयेश ने जनगणना के आंकड़े पेश किए, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आये. हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में बालिकाओं का अनुपात घटा है. 2001 की तुलना में प्रदेश में 0–6 आयु वर्ग में बेटियों की संख्या 2011 तक प्रति हजार 18 और कम हो गई. वर्तमान में प्रत्येक हजार बालकों पर प्रदेश में 890 बालिकाएं ही रह गई हैं, जबकि 2001 में प्रत्येक हजार बालकों पर 908 बालिकाएं थीं. हां, हरिद्वार में बेटियों का अनुपात जरूर बढ़ा है. यहां पिछले 10 सालों में बेटियों की संख्या प्रति हजार 15 बढ़ी है. पिथौरागढ़ की स्थिति सबसे बदतर है. यहां 2001 के मुकाबले प्रति हजार 86 बालिकाएं कम हुई हैं. बेटियों की घटती जनसंख्या इसलिए भी चिंतनीय है, क्योंकि पिछले दस सालों में प्रदेश की आबादी करीब 16 लाख बढ़ी है. 2001 में हम 84,89,349 थे, अब यह आंकड़ा बढ़कर 1,00,86,292 तक पहुंच चुका है. इस दौरान महिलाओं की संख्या ही नहीं घटी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी इनकी भागीदारी कम हुई है. सुकून की बात यह है कि महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है और इस मामले में वे पुरुषों से भी आगे हैं.

कोख में ही बच्चियों का कत्ल बाल लिंगानुपात में लगातार गिरावट का एक बड़ा कारण है, जो राज्य में अल्ट्रासाउंड मशीनों के धड़ल्ले से प्रयोग के कारण हुआ है. यहां 518 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं. इनसे ज्यादा अनधिकृत केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनपर प्रशासन का कोई अंकुश ही नहीं है. जो पंजीकृत केंद्र हैं, उनका भी निरीक्षण नहीं किया जाता! कन्या भ्रूण हत्या में राजधानी देहरादून पहले नंबर पर है. वर्ष 2010–11 में उत्तराखंड में 4,344 कन्या भ्रूण हत्याएं हुईं. हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक, 15 से 49 साल की गर्भवती महिलाओं में 4.5 प्रतिशत ने गर्भपात कराया. इनमें से 3.9 फीसद ग्रामीण और 6.2 फीसद शहरी महिलाएं शामिल हैं. ■

## उत्तराखंड की जनसंख्या एक नजर में

| | |
|---|---|
| 2001 | 84,89,349 |
| 2011 | 1,00,86,292 |
| कुल वृद्धि | 18.8 फीसद |
| महिला आबादी | 4948519 |
| पुरुष आबादी | 5137773 |

बाल जनसंख्या (छह साल तक): बालक-717199, बालिकाएं-638615

## 10 साल में घटी बेटियों की संख्या

| ज़िला | 2001 | 2011 | अंतर |
|---|---|---|---|
| पिथौरागढ़ | 902 | 816 | -86 |
| रूद्रप्रयाग | 953 | 905 | -48 |
| चंपावत | 934 | 873 | -61 |
| चमोली | 935 | 889 | -46 |
| टिहरी | 927 | 897 | -30 |
| बागेश्वर | 931 | 904 | -27 |
| उत्तरकाशी | 942 | 916 | -26 |
| पौड़ी | 930 | 904 | -26 |
| यूएसनगर | 913 | 899 | -14 |
| अल्मोड़ा | 932 | 922 | -10 |
| नैनीताल | 910 | 902 | -08 |
| देहरादून | 894 | 889 | -05 |

# विकास का फ़ायदा नहीं मिला

जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें, तो पिछले 10 सालों में शहर की जनसंख्या लगभग 40 फीसद के अनुपात में बढ़ी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा महज 11.5 फीसद रहा है. हरिद्वार जिले में सबसे अधिक दबाव बढ़ रहा है, जबकि पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय जिलों में जनसंख्या घटी है. पहाड़ में बेरोजगारों की भरमार है और लगातार पलायन हो रहा है. रोजगार का सवाल विकराल रूप ले रहा है. शहरी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना भी बड़ी चुनौती साबित होगा. मैदानी जिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है, जबकि पर्वतीय जिलों में ऐसे लोगों की संख्या घट रही है. पहाड़ में 30 प्रतिशत कामगार आज भी छह माह का रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी आश्चर्यजनक रूप से कम हुई है. राज्य की सरकारें विकास दर बढ़ने से अपनी पीठ भले ही थपथपाती रहें, लेकिन हमारी किसानी खत्म हो रही है. खेती करने वालों की संख्या में 10 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है, जबकि खेतिहर मजदूरों की संख्या ढाई लाख से बढ़कर चार लाख हो गई है. वहीं, विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कामगारों की संख्या भी 72 हजार से बढ़कर 1.14 लाख तक ही बढ़ पाई है, जिससे औद्योगिक विकास का फायदा भी उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा है. ■

## कुर्सी ख़तरे में पड़ी

# छूटा मुख्यमंत्री का अफसर प्रेम

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

**पूरी कोशिशों के बाद भी टिहरी लोकसभा उपचुनाव और फिर निकाय चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अक्ल ठिकाने आ गई है. आराम फरमाने वाले मुख्यमंत्री जी अचानक इन दिनों अफसरों की सुध ले रहे हैं...**

सरकार के मुखिया के रूप में अपने 14 साल के कार्यकाल के दौरान बाबुओं के सहारे जनता का विश्वास और चुनाव जीतने की कोशिश में जुटे सीएम विजय बहुगुणा की अक्ल लगता है, अब ठिकाने आ गई है. पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने और पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद पहले टिहरी लोकसभा उपचुनाव और फिर निकाय चुनाव में मुंह की खाने के बाद सिंहासन डोला, तो मुख्यमंत्री अपनी गिरेबां में झांकने को मजबूर हो गए. तुरंत उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे सरकार के कामकाज की सुध लेने की याद आई. वैसे तो निकाय चुनाव हारने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर कई अफसरों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन अब तक अपने मनमौजी अफसरों को बेलगाम छोड़ने के लिए बदनाम हो चुके मुख्यमंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों को ढाल बनाकर भी नौकरशाहों को दंडित करने का मन बना चुके हैं. इसलिए इन दिनों अफसरों में भी हड़कंप है.

दरअसल, सूबे में कांग्रेस की सरकार होने और पूरा तामझाम जुटाने के बाद भी चुनावों में हार से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बेचैन हैं. खासकर, अब तक विश्वासपात्र रही अपनी नौकरशाही पर से तो उनका विश्वास ही उठ चुका है. ऐसे में, भावी लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने के लिए चिंतित सरकार और संगठन ने अपनी खामियां टटोलने के लिए गांवों–गली–मोहल्लों में पार्टी की बागडोर थामे ज़िला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर फीडबैक लेने के लिए देहारादून में घंटों सिर जोड़कर चिंतन–मनन किया. कार्यकर्ताओं ने बेलगाम और मनमानी पर उतारू अफसरों की जमकर शिकायतें भी कीं. मंत्रियों और विधायकों की कार्यप्रणाली भी निशाने पर रही. लोगों ने सीएम के समक्ष सड़क, बिजली, पानी, सस्ते गल्ले का अनाज नहीं मिलने, चिकित्सकों–शिक्षकों की कमी समेत जनहित से जुड़े सैकड़ों सवालों की झड़ियां लगा दीं. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. कार्यकर्ताओं की शिकायतों और असंतोष से सरकार और संगठन दोनों ही सकते में दिखे. मज़ाविरा होने के बाद सीएम बहुगुणा ने दावा किया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर अक्षम और भ्रष्ट अफसर हैं, जिनकी सूची तैयार कर ली गई है और अब उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री की मंशा से साफ़ जाहिर है कि अभी नीचे से ऊपर तक कई अधिकारियों पर गाज गिरनी बाक़ी है. वास्तव में जो अफसर ग़लत हैं, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए. ख़ासकर, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा उठाए गए क़दमों की वजह से बहुगुणा राज में बेलगाम हुए अफसरों पर लगाम लगी है. आए दिन उनके भ्रष्टाचार और मनमानी से जुड़े कारनामे सुर्खियों में बने रहते हैं. विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत से लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरके भटनागर और एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉ. राजकुमार भी नौकरशाही की मनमानी के मसले पर सार्वजनिक रूप से सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री को अपना अफसर प्रेम छोड़ना पड़ रहा है. हालांकि सिर्फ कांग्रेस पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर अफसरों को नापना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सत्ताधारी दल से जुड़े नेता अफसरों से मनमाने काम करवाना चाहते हैं, जो किसी के दबाव में न आकर साफ–सुथरा काम करना चाहते हैं. इसे सत्ताधारी दल के नेता अक्सर पचा नहीं पाते. जाहिर है, सीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में कुछ अच्छे अफसर भी पार्टी पदाधिकारियों के निशाने पर रहे होंगे. इसलिए पूरी जांच–पड़ताल कर वास्तविकता का पता लगाने के बाद ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, तो बेहतर है. ■

**मुख्यमंत्री की मंशा से साफ़ जाहिर है कि अभी नीचे से ऊपर तक कई अधिकारियों पर गाज गिरनी बाक़ी है. वास्तव में जो अफसर ग़लत हैं, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए. ख़ासकर, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा उठाए गए क़दमों की वजह से बहुगुणा राज में बेलगाम हुए अफसरों पर लगाम लगी है. आए दिन उनके भ्रष्टाचार और मनमानी से जुड़े कारनामे सुर्खियों में बने रहते हैं.**

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

# पंचायत चुनावों को लेकर खींचतान तेज

**उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को देखते हुए ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है...**

2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े सामने आने के साथ ही अब सितंबर, 2013 में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भी खींचतान तेज हो गई है. फिलहाल उत्तराखंड शासन 2001 की जनगणना को आधार मानकर पंचायत चुनाव कराने के मूड में है. इसके लिए ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य लगभग पूरा भी हो चुका है, जबकि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

2011 की जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें, तो प्रदेश की आबादी में पिछले 10 सालों में 16 लाख से अधिक का इजाफा हुआ है. अनुसूचित जाति की संख्या भी काफी बढ़ी है. लिहाजा, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने की स्थिति में आरक्षण का गणित बिगड़ना भी तय है. हाल ही में हुए निकाय चुनावों में भी 2011 के आधार पर परिसीमन कराने की मांग विपक्ष ने उठायी थी. इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, लेकिन तब प्रदेश सरकार ने तर्क दिया था कि नई जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित नहीं होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं है. इससे 2001 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव हुए थे, लेकिन अब नए आंकड़े सामने आ चुके हैं. 16 लाख से अधिक आबादी बढ़ने का मतलब यही है कि यह ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायतों के पूरा समीकरण ही बदल देगा.

वैसे मुख्य विपक्षी दल भाजपा और सरकार में सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की मांग पुरजोर तरीके से उठानी भी शुरू कर दी है. इन दलों का तर्क यही है कि नए आंकड़े आने के बाद इन्हीं के आधार पर परिसीमन विधिसम्मत है और सरकार यदि इसकी अपेक्षा करती है, तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत साफ कह चुके हैं कि 2011 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इसी को आधार मानकर चुनाव कराना विधिसम्मत है. यदि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन और त्रिस्तरीय चुनाव नहीं कराए गए, तो इसका विरोध किया जाएगा. बसपा प्रदेश अध्यक्ष मेघराज जरावरे ने भी नई जनगणना को आधार मानकर ही परिसीमन करने को औचित्यपूर्ण बताया. बसपा नेता इस मसले पर जल्द ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और राज्य निर्वाचन आयोग से भी मिलेंगे. ■

## प्रशासन नाक़ाम

# भू-माफ़िया कर रहा है अवैध निर्माण

**उत्तराखंड में कृषि भूमि पर भू-माफ़िया प्लॉटिंग कर किसानों को कर रहे हैं ज़मीन से बेदख़ल. इस पूरे खेल में भू-माफ़िया, नौकरशाहों और नेताओं के गठजोड़ की बात सामने आ रही है.**

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड बनने के बाद लहलहाते खेत कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गए हैं. बचे खेतों पर भू-माफ़िया प्लॉटिंग कर किसानों को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं. इस खेल में किसान और सरकारी तंत्र दोनों की मिलीभगत है. उत्तराखंड बनने के बाद भले ही प्रदेश ने विकास नहीं किया हो, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते ज़मीन के दाम आसमान छू चुके हैं. जिन खेतों में कभी हरियाली हुआ करती थी, वहां बड़े–बड़े भवन खड़े हो गए हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन है. सरकार के पास बढ़ते जंगलराज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है.

ऋषिकेश व डोइवाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहां अब खेतों में केवल भवन ही नजर आ रहे हैं. कई एकड़ कृषि भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग कर दी गई है. डोइवाला में भू-माफ़िया दून घाटी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर प्लॉटों को दुगने दामों पर बेच कर चांदी काट रहे हैं. कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस भेजने की खानापूर्ति की जाती है. डोइवाला के मारखमग्रांट, सिमलास ग्रांट, दुधली, नांगल, बुलंदावाला, लच्छीवाला, भानियावाला, फतेहपुर, माजरीग्रांट, जौलीग्रांट, बडोवाला, कालूवाला, रानीपोखरी, भोगपुर, कुंआवाला और हरावाला क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है. इन क्षेत्रों में दून घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भू-माफ़िया को बढ़ावा दे रहे हैं. कुछ ऐसे इलाके हैं, जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं. माजरी व लालतप्पड़ में बाहरी लोग स्थानीय लोगों की मदद से औने–पौने दामों में भूमि खरीदकर दुगने दामों में प्लॉटिंग करके बेच देते हैं, जिनमें ग्राम समाज की भूमि भी शामिल है. भू-माफ़िया द्वारा तहसील विभाग से जुड़े आला अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से कागजों में हेराफेरी कर ग्राम समाज की भूमि को बेच रहे हैं, प्रशासन इस खेल को नहीं रोक पा रहा है. यही हाल रानीपोखरी, थानों, बड़कोट ऋषिकेश के श्यामपुर, गुमानीवाला, छिद्दरवाला, रायवाला, गौहरीमाफी व प्रतीतनगर का है. तीर्थनगरी में कंक्रीट के जंगल को खड़ा करने में हरिद्वार विकास प्राधिकरण (एचडीए) भी भू-माफिया का साथ दे रहा है, जिसके चलते नगर में बिना नक्शे पास किये गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हो रहा है. गौरतलब है कि पशुलोक में जब से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निर्माण हुआ है, तब से इस क्षेत्र में भू-माफिया ने विस्थापितों की जमीन खरीदकर इसमें गगनचुंबी इमारतें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं. टिहरी बांध विस्थापितों को रहने व खेती करने के लिए सरकार ने आमबाग व निर्मलबाग में जो भूमि उपलब्ध करायी थी, इस भूमि को भू-माफिया ने औने–पौने दामों में खरीद कर इसे राज्य के बाहरी व्यवसियों को बेची थी. पशुपालन विभाग के कार्यालय के पास विस्थापितों को मिली कई एकड़ की भूमि पर अवैध रूप से गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है. खास बात यह है कि प्राधिकरण दो कमरे का निर्माण करने वाले से नक्शा पास करने को कहता है और नक्शा पास न करने पर उसे नोटिस थमा देता है. वहीं प्राधिकरण की लापरवाही के चलते विस्थापित क्षेत्र में धड़ल्ले से प्लॉट बनाने का काम तेजी से चल रहा है. एचडीए का आलम यह है कि वह विस्थापितों को अपने क्षेत्र से बाहर का बताता है. निजी भवन बनाने की बात पर कार्रवाई न करना तो समझ में आता है, लेकिन जो व्यवसायिक भवनों का निर्माण कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से आख़िर प्राधिकरण क्यों हिचक रही है. इस बात का जवाब प्राधिकरण के पास नहीं है. विस्थापित क्षेत्रों में एचडीए बिना नक्शे पास भवन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि कार्रवाई करने पर लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत करने पहुंच जाते हैं. देवभूमि में जंगलराज कायम रखने में भ्रष्ट अफसर और नेताओं का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है. ■

## उत्तराखंड/ ख़बरें

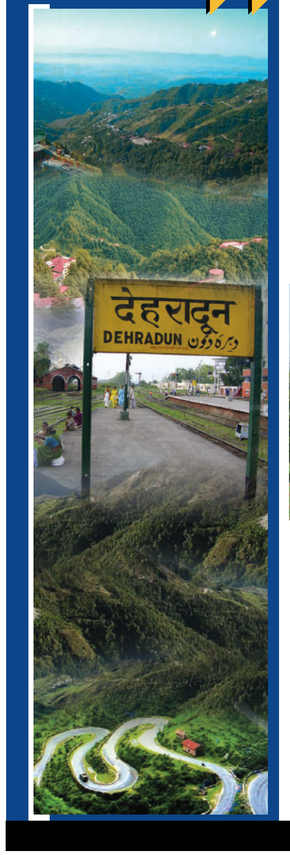


## वृक्षों को बचाने का लिया प्रण

# ग्रामीणों ने बांधे रक्षा सूत्र

रेवु शर्मा feedback@chauthiduniya.com

वन विभाग के अधिकारियों ने किया आवंटित भूमि का सर्वेक्षण और गांव वालों से मांगे दस्तावेज. गोडावर्मन केस के मुताबिक, पेड़ों से आच्छादित किसी भी किस्म की भूमि वन कानून के दायरे में ही आती है.

प्रदेश सरकार छरबा के जिस कोका कोला बॉटलिंग प्लांट के लिए वेताब है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टीएन गोडावर्मन केस का पेंच फंस रहा है. इस जमीन को प्लांट के लिए दिये जाने पर लगभग पचास हजार हरे वृक्षों को काटना पड़ेगा. गांव के लोगों ने इन वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया है. कोका कोला कंपनी को जो भूमि आवंटित की जा रही है, इसमें छरबा के ग्रामीणों ने शीशम–खैर आदि के हजारों पेड़ लगाए हैं और इसे ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया है. टीएन गोडावर्मन बनाम भारतीय संघ मामले से संबंधित अपने फैसले में ऐसी ही स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह पेड़ों से आच्छादित भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में माना जाएगा. इस तरह से यह भूमि वन कानून के दायरे में आती है, जहां गैर वन गतिविधियां नहीं की जा सकतीं और अगर इसमें गैर वन कार्य किए जाते हैं, तो इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति जरूरी है.

सरकार के कोका कोला के साथ एमओयू के बाद छरबा के ग्रामीण आशंका व्यक्त करते रहे हैं कि कोका कोला प्लांट के लिए इस जमीन के 50 हजार पेड़ काट दिए जाएंगे. अब ग्रामीणों के दावों की पड़ताल के लिए पिछले हफ्ते वन विभाग के अधिकारियों ने कोका कोला को आवंटित जमीन की स्थिति जानने के लिए एक सर्वे किया. छरबा के ग्राम प्रधान रूमी राम जायसवाल का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों से कहा है कि वे जमीन की स्थिति के बारे में दस्तावेजी प्रमाण दें. उनका कहना है कि गांव वालों ने कोका कोला को आवंटित इस भूमि पर 50 हजार पेड़ों की ग्रीन बेल्ट का विकास किया है. इसी आधार पर छरबा के ग्रामीणों ने इस भूमि पर दून विश्वविद्यालय का परिसर नहीं बनने दिया था. हाल ही में लोगों ने कोका कोला कंपनी के साथ हुए समझौते के विरुद्ध छरबा की भूमि पर उगे पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध कर इन्हें न कटने देने का संकल्प लिया है.

पिछले दिनों देहरादून के पर्यावरण प्रेमी लोगों के संगठन सिटिजन्स फॉर ग्रीन दून ने वन विभाग से कोका कोला को आवंटित भूमि के लिए एक सर्वे की मांग की थी. सिटिजन्स फॉर ग्रीन दून के मुख्य संयोजक डॉ. नितिन पांडेय ने भी अपनी मांग पत्र में गोडावर्मन बनाम भारतीय संघ व अन्य फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को भू–आवंटन के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए. सरकार ने पिछले दिनों छरबा में बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए कोका कोला के साथ 600 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं. सरकार भले ही प्लांट के माध्यम से 1000 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन छरबा और आस–पास के गांवों के लोग एमओयू के खिलाफ अब लामबंद हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पर्यावरण को तबाह करके मिलने वाले रोजगार की रोटी नहीं चाहिए. इसीलिए वे आंदोलनरत हैं. उनका कहना है कि एमओयू से पहले सरकार ने लोगों की सहमति नहीं ली. नदी बचाओ अभियान के सुरेश भाई का कहना है कि कोका कोला को जंगल देना सरकार का एक आपराधिक कृत्य है. उनका कहना है कि कोकाकोला किसी भी देश, राज्य व गांव के विकास व पर्यावरण संरक्षण में बाधक है. ■

# बढ़ रही है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा

**एजेंसी का मानना है कि जब शेष बचे पर्वतीय राज्यों का सर्वे हो जाएगा, तब पर्वतीय राज्यों के युवाओं के रुझान की असली तस्वीर सामने आएगी. वर्तमान में हिमाचल और उत्तराखंड के युवाओं पर किए गए सर्वे यही दर्शा रहे हैं कि युवा कार्यकर्ताओं की चाहत बढ़ी है और इसीलिए अब वे मुफ्त में कोई काम करने को तैयार नहीं हैं.**

**राजनीति में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है, उससे आने वाले कुछ वर्षों में पार्टी के प्रचार-प्रसार के लिए पेड कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ सकता है.**

रेवु शर्मा feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक दलों द्वारा अपने वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा घाटे का सौदा सिद्ध हो रहा है. अगर यही हाल रहा, तो डेढ़ दशक बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को पेड कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है. राजनीति से जुड़े कार्यकर्ताओं का पार्टियों से मोहभंग होना शुरू हो गया है. यह बात एक सर्वे एजेंसी द्वारा पर्वतीय राज्यों (जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है) में किए गए सर्वे से निकल कर सामने आई है. यंग वे ट्रेंड नाम की एक सर्वे एजेंसी ने राजनीति से जुड़े प्रदेश के युवाओं को लेकर अपने एक साल के सर्वे के दौरान पाया कि अब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई भी नेता या राजनीतिक दल ज्यादा दिनों तक बेवकूफ बना कर सम्मेलनों एवं रैलियों में शामिल नहीं करा सकते हैं. अब युवाओं का रुझान राजनीतिक पार्टियों की बजाय दलगत राजनीति से परे रहने वाली संस्थाओं की ओर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है.

सर्वे एजेंसी ने उत्तराखंड के अलावा, हिमाचल प्रदेश में अपने सर्वे का काम पूरा कर लिया है. अब जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वे का काम करना बाकी रह गया है. प्रदेश के बारे में इस एजेंसी का दावा है कि राजनीतिक पार्टियों में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की काफी कमी आई है. अब 20 से 25 फीसद कार्यकर्ताओं का विश्वास ही पार्टियों पर टिका हुआ है. इन आंकड़ों में संघ और वामपंथी पार्टियों को शामिल नहीं किया गया है. 40 से 50 फीसद कार्यकर्ता अपनी–अपनी पार्टियों से लाभ की चाहत में रहते हैं. पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष की कतार में बैठी हो, इससे कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 55 से 65 फीसद कार्यकर्ता पार्टियों के प्रति समर्पित हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इस एजेंसी ने वर्ष 2005 में जो सर्वे किया था, इसमें गांवों में पार्टियों के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की संख्या 40 से 50 फीसद ही रही. इस दौरान निष्ठावान कार्यकर्ताओं की संख्या 30 से 35 फीसद थी, जिसमें इस बार गिरावट देखने को मिली है. पद की चाहत रखने वालों की संख्या वर्ष 2005 में 30 से 35 फीसद रही. एजेंसी का मानना है कि जब शेष बचे पर्वतीय राज्यों का सर्वे हो जाएगा, तब पर्वतीय राज्यों के युवाओं के रुझान की असली तस्वीर सामने आएगी.

वर्तमान में हिमाचल और उत्तराखंड के युवाओं पर किए गए सर्वे यही दर्शा रहे हैं कि युवा कार्यकर्ताओं की चाहत बढ़ी है और इसीलिए अब वे मुफ्त में कोई काम करने को तैयार नहीं हैं. पहले अपने नेताओं की एक आवाज पर कार्यकर्ता घर छोड़कर पोस्टर चिपकाने एवं नुक्कड़ सभाओं में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है. कोई भी पार्टी कार्यकर्ता पहले लाभ देखता है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि एजेंसी ने सर्वे में इन्हीं युवाओं को शामिल किया है, जो राजनीतिक दलों के सदस्य हैं. एजेंसी के इस आकलन पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अभी प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पटाने के मकसद से यह ऐलान किया है कि जो अफसर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बातों को तवज्जो नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इन नेताओं का कहना है कि सरकार या अधिकारी का काम महज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही पीड़ा सुनना नहीं होता है. आम आदमी यदि अधिकारी के पास कोई समस्या लेकर जाए, तो अधिकारी को चाहिए कि वह समस्याओं का निपटारा करे. अधिकारी को कांग्रेस या भाजपा का चेहरा नहीं देखना चाहिए. भाजपा के नेता ने माना कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलने की वजह से ही कार्यकर्ताओं का पार्टियों से मोह भंग हो रहा है. भाजपा में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता जहां भी हैं, संगठित हैं और अपने नेता के एक इशारे पर जान देने को भी तैयार रहते हैं. इधर प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है. कार्यकर्ताओं में यदि किसी बात को लेकर कोई नाराजगी है, तो इसे दूर करने की कोशिश की जाती है. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य या पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, वे पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखते हैं. यह परम्परा रायबरेली और अमेठी में भी देखने को मिल रही है. रायबरेली में ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को दो पहिया वाहन के साथ कुछ पांकेट मनी भी दी जा रही है. यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दिन बहुरेंगे, ऐसी सम्भावनाओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं. ■

भाजपा के नेता ने माना कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलने की वजह से ही कार्यकर्ताओं का पार्टियों से मोह भंग हो रहा है.

ले. जनरल सुरेंद्र सिंह पवार को थलसेना चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक बनाकर दिल्ली भेजा गया है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467



# चीनी मिल बिक्री घोटाला

# नेता-नौकरशाहों को नहीं बख्शा जाएगा

**बसपा सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की बेशक़ीमती चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई थीं. अब जांच में नेता-नौकरशाह की गठजोड़ सामने आने से हड़कंप मच गया है. ऐसा लगता है कि अब नेता और नौकरशाहों को किसी भी क़ीमत पर नहीं बख्शा जाएगा.**

संजय सक्सेना feedback@chauthiduniya.com

बसपा सरकार का कार्यकाल वैसे तो कई मायनों में विवादित रहा, लेकिन अरबों रुपये के चीनी मिल घोटाले से इसकी साख को सबसे अधिक धक्का लगा. चीनी मिल घोटाले की जांच राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा कर रहे हैं. इधर, कुछ दिनों से चीनी मिल घोटाले की जांच में तेजी आने से सियासी पारा अपने आप ऊपर चढ़ गया है. नौकरशाही में हड़कंप मच गया है. इस घोटाले में कई बड़े आईएएस अफसरों पर गाज गिरनी तय है. लोकायुक्त पहले ही 12 आईएएस और दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को नोटिस थमा चुके हैं. गौरतलब है कि ये आईएएस चीनी मिल बिक्री के समय इन ज़िलों में तैनात थे. इसके अलावा, बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे क़रीबी पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी घोटालेबाज़ों की लिस्ट में शामिल है. कहा तो यह भी जाता है कि अगर जांच गहराई से हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आंचल पर भी छींटें पड़ सकती हैं, क्योंकि चीनी मिलों के विनिवेश का निर्णय मंत्रिपरिषद की मुहर लगने के बाद लिया गया था. दूसरी तरफ़ बसपा इसे राजनीतिक रंग देकर अपना दामन बचाने की कोशिश में लगी है.

सब जानते हैं कि बसपा राज में शराब माफिया पोंटी चड्ढा को बेशक़ीमती चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई थीं. उस समय क़रीब 1179.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की चपत सरकार को लगी थी. मनमाने तरीक़े से ज़िला स्तर पर कमेटी बनाई गई और इसके बाद स्टांप ड्यूटी में कमी का खेल खेला गया, जबकि स्टांप ड्यूटी तय करने का अधिकार सिर्फ़ जिलाधिकारी को होता है. कैग पहले ही अरबों के चीनी मिल घोटाले का ख़ुलासा अपनी जांच रिपोर्ट में कर चुका है. पहले दौर में बेची जाने वाली चीनी मिलों की बिडिंग करने वाली दोनों कंपनियां चड्ढा की ही थीं, जबकि दूसरे दौर में बिडिंग करने वाली सभी कंपनियों के निदेशक आपस में साझेदार थे. यूपीआरसीजीवीएनएल की मिलों में चड्ढा को लाभ देने के लिए भूमि के मूल्य में 128.41 करोड़ रुपये की कमी की गई और रजिस्ट्री शुल्क में चड्ढा को कुल 841.54 करोड़ रुपये का फ़ायदा पहुंचाया गया. हैरानी की बात तो यह है कि बड़ी ज़मीनों पर क़रीब 20 करोड़ रुपये की छूट तक दे दी गई. यूं तो पूरे चीनी मिल घोटाले में तमाम अफसरों की गर्दनें फंसी हैं, लेकिन सबसे अधिक मुश्किल में क़रीब आधा दर्जन आईएएस अफसरों का सचिव समूह और पूर्व भ्रष्ट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, जिनकी भूमिका घोटाले में बेहद संदिग्ध है. फिलहाल, पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव अतुल कुमार गुप्ता, आईएएस, अनूप मिश्रा, वीएन गर्ग, जुहैर बिन सगीर, नेतराम विनय प्रिय दुबे, जेएन चेंबर पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने अपना शिकंजा कस रखा है. इन नौकरशाहों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कुछ को छोड़कर कई बड़े अफसरों ने अपना जवाब लोकायुक्त को अभी तक नहीं भेजा है. चीनी मिल बिक्री घोटाले में मुख्य किरदार निभाने वाले पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता उस समय सचिव समूह के मुखिया थे. गुप्ता मायावती के बेहद क़रीबी अफसर होने के साथ ही क़रीब 4 हज़ार करोड़ के होटल आवंटन घोटाले समेत कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट–कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं. अतुल गुप्ता मायाराज में काफ़ी विवादित रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इस भ्रष्ट अफसर का बसपा सरकार में बाल तक बांका नहीं हुआ था. यही हाल दाग़ी आईएएस नेतराम का भी है, जो दाग़ी प्रमुख सचिव गृह रहे कुंवर फतेह बहादुर के साथ क़रीब 300 करोड़ के भूमि घोटाले की सतर्कता जांच में फंसे हैं. ख़ुद तत्कालीन दाग़ी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चीनी मिल घोटाले का ठीकरा सचिव समूह में शामिल आईएएस अफसरों पर फोड़ा था. लोकायुक्त से हटकर कैग की जांच पर नज़र डाली जाए, तो पता चलता है कि कैग के ऑडिट के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि चीनी मिलों के विनिवेश के फ़ैसले मंत्रिपरिषद से अनुमोदित है और कैग इसका ऑडिट नहीं कर सकता. कहा यह भी जा रहा है कि चीनी मिल बिक्री घोटाला काफ़ी बड़ा है. लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा ने गहराई से जांच की, तो न सिर्फ़ कद्दावर आईएएस अफसर नसीमुद्दीन बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी नप सकती हैं.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कहते हुए बताते हैं कि पांच साल लूट और झूठ के सहारे प्रदेश में बसपा का अंधेर राज चला. चौधरी का कहना था कि लोकायुक्त की जांच में सत्ता के दुरुपयोग और तमाम अनियमितताओं में फंसे बसपा नेताओं और इसकी सरकार ने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के बजाए इसे बदहाल और बदनाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में प्रयास करने की जगह पत्थरों, पार्कों और स्मारकों पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जाती रही. बसपा मुख्यमंत्री ने अपने जिंदा रहते जगह–जगह अपनी प्रतिमाएं लगवा दी.■

**ये आईएएस चीनी मिल बिक्री के समय इन ज़िलों में तैनात थे. इसके अलावा, बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे क़रीबी पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी घोटालेबाज़ों की लिस्ट में शामिल है. कहा तो यह भी जाता है कि अगर जांच गहराई से हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आंचल पर भी छींटें पड़ सकती हैं, क्योंकि चीनी मिलों के विनिवेश का निर्णय मंत्रिपरिषद की मुहर लगने के बाद लिया गया था.**

# ले. जनरल सुरेंद्र सिंह बने डीजीएमएस आर्मी

**ले. जनरल सुरेंद्र सिंह पवार ने 2 जनवरी, 1977 को सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त किया था. लखनऊ मेडिकल कॉलेज से ईएनटी के सर्जन बनने वाले जनरल पवार पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर हैं...**

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ छावनी स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र, कॉलेज के सेनानायक एवं एएमसी अभिलेख प्रमुख कमांडेंट ले. जनरल सुरेंद्र सिंह पवार को थलसेना चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक बनाकर दिल्ली भेजा गया है. पवार अब ले. जनरल गौतम रवींद्रनाथ की जगह लेंगे. ले. जनरल सुरेंद्र सिंह पवार ने 2 जनवरी, 1977 को सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त किया था. लखनऊ मेडिकल कॉलेज से ईएनटी के सर्जन बनने वाले जनरल पवार पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर हैं. उन्होंने यूके के जेम्स कूक यूनिवर्सिटी क्लेवलैंड एवं सीटी हॉस्पिटल बर्मिंघम से न्यूरो–ओटोलॉजी एंड कॉचलियर इंप्लांट सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल किया है. वे यूके स्थित जॉर्ज मेडिकल काउंसिल के सदस्य भी हैं. उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें सेना पदक एवं अतिविशिष्ट सेवा पदक पश्चिमी कमान के सेनाध्यक्ष का प्रशंसा पत्र तथा दो बार थल सेनाध्यक्ष के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है. जनरल पवार ने 1 जुलाई, 2012 को लखनऊ छावनी स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के सेनानायक एवं एएमसी अभिलेख प्रमुख का कार्यभार संभाला था. एक सप्ताह तक चले विभिन्न कार्यक्रमों के बाद 31 मई को उन्हें केंद्र एवं कॉलेज द्वारा भावभीनी विदाई दी गई. जनरल पवार ने इस मौक़े पर कहा कि श्रेष्ठ मानदंडों के लिए सैन्य चिकित्सकों को सेवा और देश प्रेम की भावना से काम करते रहना चाहिए.■

# राम भवनों के निर्माण में करोड़ों के घपले

**राम की पैड़ी हो या राम कथा संग्रहालय, इन परियोजनाओं के बहाने अयोध्या में जमकर लूट मची है, जबकि इन भवनों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है...**

राकेश कुमार यादव feedback@chauthiduniya.com

अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन आज भी यह नगरी विकास से कोसों दूर है. हालांकि विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर यहां सरकारों ने काफ़ी धन व्यय किए, लेकिन बावजूद इसके यहां के लोगों को न तो रोजगार मिला, न ही यहां का अब तक विकास हो पाया है. ऐसी योजनाएं ज़रूर बनीं, जो कुछ दिनों के लिए काफ़ी चर्चा में भी रहीं, लेकिन साल दो साल में ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाने लगीं. इन योजनाओं में सबसे चर्चित राम की पैड़ी का निर्माण रहा, लेकिन रख–रखाव के चलते यह भी अब बदरंग हो चुकी है. हालत यह है कि लोग यहां अब आना पसंद ही नहीं करते. हालांकि सूबे की सरकार अयोध्या को पर्यटन नगरी बनाने का दावा लगातार कर रही है. राम की पैड़ी पर अरबों रुपयों की नई परियोजना भी तैयार की जा चुकी है. 12.25 करोड़ रुपये से निर्माणाधीन राम कथा संग्रहालय के निर्माण का सवाल भी भविष्य के गर्भ में है. बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत एक विशाल भू–क्षेत्र में रामकथा संग्रहालय भवन निर्माण के लिए 12.25 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा भवन निर्माण की तिथि मार्च, 2010 तय भी की गई, लेकिन वर्ष 2013 तक भी संग्रहालय का निर्माण पूरा नहीं हो सका है. कार्यदायी संस्था जल निगम की सी एंड डीएस यूनिट 44 द्वारा भवन को अयोध्या शोध संस्थान को हस्तांतरित न किए जाने से धनराशि का आवंटन नहीं हो पाया है. प्रदेश में सपा सरकार की संस्कृति मंत्री अरुण कुमारी कोरी ने निर्माणाधीन भवन का कई बार निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की कच्छप गति पर नाराज़गी भी जताई. उनके निर्देश पर काम पूरा करने के लिए ज़िम्मेदारी निगम की यूनिट 21 को सौंप दी गई. निर्माणाधीन भवन की कार्यदायी संस्था के स्थानीय अधिकारी एपी पांडेय का कहना है कि फ़ैज़ाबाद ज़िला प्रशासन से मई 2013 तक का समय लिया गया है. संबंधित भवन में केवल रंगाई–पुताई का कार्य शेष है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा. वहीं रामकथा संग्रहालय के विभागीय लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था के अभियंता झूठ बोल रहे हैं. निर्माणाधीन भवन में एप्रोच रोड, सीवर लाइन, विद्युत, जल के अतिरिक्त बरसात में कमरों में जल भरने की समस्या और सीवेज समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया है. इसी अधूरे कार्य के कारण अयोध्या शोध संस्थान को कार्यदायी संस्था भवन को हैंडओवर नहीं कर रही है. बीते तीन सालों से निर्माण कार्य कच्छप गति से होने के कारण संग्रहालय को नवनिर्मित भवन में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है.

गौरतलब है कि रामकथा संग्रहालय अयोध्या शोध संस्थान में प्रतिमाह क़रीब 25 हज़ार 800 रुपये मासिक किराए पर संचालित किया जा रहा है. प्रस्तावित भवन की साज–सज्जा के लिए शासन ने आवास विकास परिषद को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया है. परिषद की परियोजना प्रबंधक आरए वर्मा का कहना है कि तेरहवें वित्त आयोग में प्रस्तावित कार्य के लिए ढाई करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. जब तक भवन हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक धन आवंटन नहीं हो पाएगा. भवन हस्तांतरित होते ही धन के आवंटन के बाद कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिया जाएगा. फिलहाल, शोध छात्रों और विद्वानों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि राम कथा संग्रहालय शीघ्र शुरू हो जाए. ■

**रामकथा संग्रहालय अयोध्या शोध संस्थान में प्रतिमाह क़रीब 25 हज़ार 800 रुपये मासिक किराए पर संचालित किया जा रहा है. प्रस्तावित भवन की साज-सज्जा के लिए शासन ने आवास विकास परिषद को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया है. परिषद की परियोजना प्रबंधक आरए वर्मा का कहना है कि तेरहवें वित्त आयोग में प्रस्तावित कार्य के लिए ढाई करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.**

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366